चौथी दुनिया

हिंदी का पहला साप्ताहिक अखबार

www.chauthiduniya.com

1986 से प्रकाशित | दिल्ली, 13 दिसंबर-19 दिसंबर 2010 | मूल्य 5 रुपये

भारतीय व्यवस्था का काला सच

पेज 3

भ्रष्टाचार के ख़िलाफ़ खड़े होने की राजनीति

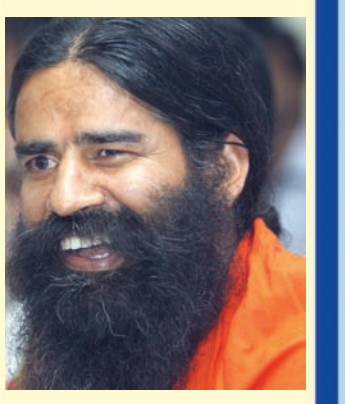

पेज 4

रक्षा मंत्री भी चुप रहे

पेज 5

साई की महिमा

पेज 12

सुप्रीम कोर्ट की चेतावनी

यह भ्रष्टाचार का दौर है. घोटालों का दौर है. भारत में भ्रष्टाचार का साम्राज्य फैला है. महंगाई हो या फिर मिलावट, ग़रीबी हो या भुखमरी, पुलिस का अत्याचार हो या फिर नक्सलवाद, सड़क, अस्पताल, पानी और बिजली की किल्लत हो या फिर शिक्षा, जंगल में विलुप्त होती वन्यजीवों की प्रजातियां हों या फिर किसानों की ज़मीन की नीलामी, सरकारी योजनाओं की असफलता, बेरोज़गारी हो या फिर टीके से मरने वाले बच्चे, सेना हो या अदालत, हर बीमारी की वजह देश के सरकारी तंत्र में मौजूद भ्रष्टाचार है. राजनेता, अधिकारी, उद्योगपति और दलाल संगठित होकर देश के संसाधनों को लूट-खसोट रहे हैं. अफ़सोस की बात यह है कि इसके बारे में सोचते हुए लोगों को न गुस्सा आता है और न ही निराशा होती है. सरकारी तंत्र में भ्रष्टाचार इतनी गहरी पैठ बना चुका है कि यह हमारे जीवन का एक अंग बन चुका है. पहले लोगों को उम्मीद थी कि एक दिन ऐसा वक़्त आएगा, कोई ऐसा नेता आएगा, जो इन सबको ख़त्म करने की कोशिश करेगा. बीते हुए कल और आज के हालात में फ़र्क़ सिर्फ इतना है कि अब यह उम्मीद भी ख़त्म हो गई है.

सभी फोटो- *प्रभात पाण्डेय*

मनीष कुमार

हर दिन एक न एक नया घोटाला आम जनता के सामने उजागर हो रहा है. अफ़सोस की बात यह है कि यह सब ऐसे प्रधानमंत्री के शासनकाल में हो रहा है, जो स्वयं ईमानदार एवं सज्जन पुरुष हैं. जिस तरह हर दिन एक के बाद एक घोटाले सामने आ रहे हैं, सरकारी तंत्र में फैले भ्रष्टाचार की असलियत सामने आ रही है, मन में एक सवाल उठता है कि अगर आज गांधी ज़िंदा होते तो क्या करते. शायद सत्याग्रह या फिर भूख हड़ताल के बजाय शर्म से आत्महत्या करने के अलावा उनके पास कोई दूसरा रास्ता नहीं बचता. यह सिर्फ़ गांधी की ही बात नहीं है. उन सभी महापुरुषों, जिन्होंने संघर्ष करके और बलिदान देकर देश को आज़ाद कराया, ने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा कि उनके बाद आने वाली पीढ़ी देश की यह दुर्दशा करेगी.

सुप्रीम कोर्ट ने 2-जी स्पेक्ट्रम घोटाले में उद्योगपतियों, नेताओं, अधिकारियों और दलालों के गठजोड़ के खुलासे को दिमाग़ हिलाने वाला करार दिया. एक जज ने यहां तक कह दिया कि हमने आज तक नदियों के प्रदूषण के बारे में सुना था, लेकिन यह तो पर्यावरण प्रदूषण से भी ज़्यादा ख़तरनाक है. मतलब यह कि हमारा पूरा सरकारी तंत्र ही सड़ चुका है. सवाल चीफ विजिलेंस कमिश्नर पी जे थॉमस के इस्तीफ़ा देने या न देने का नहीं है. हैरानी की बात यह है कि जब उन पर भ्रष्टाचार का मामला चल रहा है तो उन्हें सीवीसी बनाया ही क्यों गया. इतना ही नहीं, जब लोकसभा में विपक्ष की नेता सुषमा स्वराज ने उनके नाम पर सवाल खड़ा किया तो वैसे ही उन्हें सीवीसी नहीं बनना था. इसके बावजूद सरकार ने यह फ़ैसला लिया तो सरकार को अब यह जवाब देना चाहिए कि पी जे थॉमस में सरकार ने वे क्या ख़ूबियां देखीं, जो देश में दूसरे किसी अधिकारी के पास नहीं हैं. क्या इसे यह समझा जाए कि सरकार को लगता है कि पूरे तंत्र में एक भी ईमानदार अधिकारी नहीं बचा है. सबसे शर्मनाक़ स्थिति तो तब पैदा हुई, जब सुप्रीम कोर्ट ने पी जे थॉमस पर सवालिया निशान खड़ा कर दिया. सुप्रीम कोर्ट ने एक तरह से यह कह दिया कि पी जे थॉमस जैसे व्यक्ति का सीवीसी बनना उचित नहीं है तो इसके बाद सरकार किसके आदेश का इंतजार कर रही थी. बेशर्मी की हद तो तब हो गई कि चारों तरफ खुद की भर्त्सना होने के बावजूद पी जे थॉमस ने टीवी कैमरे के सामने यह कहने की हिम्मत जुटा ली कि सरकार ने उन्हें सीवीसी बनाया है और वह आज भी सीवीसी हैं. अब इसके बाद पी जे थॉमस ज़िंदगी भर सीवीसी बने रहें या फिर वह इस्तीफ़ा दे दें, इससे कोई फ़र्क़ नहीं पड़ता, क्योंकि सतर्कता आयोग को जो क्षति होनी थी, वह तो हो गई. जो कलंक लगना था, वह लग गया.

जब पी जे थॉमस सुप्रीम कोर्ट के सवाल के घेरे में हैं तो उनके द्वारा चुने गए सीबीआई के नए चीफ की नियुक्ति पर भी सवाल उठना लाजिमी है. अब पी जे थॉमस मामले में दखल दें या न दें, लेकिन इस मामले की जांच वही अधिकारी करेगा, जिसे थॉमस ने सीबीआई का चीफ बनाया है. क़ानून अपना काम करेगा, सुप्रीम कोर्ट अपना फ़ैसला देगा, लेकिन देश की जनता के सामने तो सरकारी तंत्र की साख ख़त्म हो गई. ख़तरा इसी विश्वास के खोने से पैदा होता है. अब किसी भी दलील या शक़ की कोई गुंजाइश नहीं रही, जब सुप्रीम कोर्ट ने ही यह दिया है कि पूरा तंत्र ही सड़ चुका है. सुप्रीम कोर्ट की यह चेतावनी हिंदुस्तान के लिए चेतावनी है. अगर इस चेतावनी को लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभाओं और राजनीतिक दलों ने नहीं सुना तो यह देश के लिए सबसे ख़तरनाक साबित होने वाला है. ख़तरा इस बात का भी है कि कहीं सुप्रीम कोर्ट की बातों को सेना ने सुन लिया तो भारत को पाकिस्तान बनने में देर नहीं लगेगी. यह बात अच्छी नहीं है, लेकिन हक़ीक़त है कि राजनीतिक दल जनता की नज़रों में इतने गिर चुके हैं, लोगों का विश्वास अधिकारियों और सरकारी तंत्र से इतना उठ चुका है कि अगर देश में सेना शासन करने के लिए उतर आए तो लोग उसका स्वागत करेंगे. यकीन मानिए, ख़तरा इतना ही गहरा है. अफ़सोस की बात यह है कि जिन लोगों को जनता ने भ्रष्टाचार से लड़ने के लिए अधिकार दिया है, उन्हीं के दामन आज काले हो गए हैं. इसके बावजूद हमें इस बात का पूरा यकीन है कि राजनीतिक दल इस चेतावनी को नहीं सुनेंगे.

एक अनुमान के मुताबिक़, 2009 के लोकसभा चुनाव में 10,000 करोड़ रुपये ख़र्च हुए, जिनमें 1300 करोड़ रुपये चुनाव आयोग ने ख़र्च किए. वहीं राज्य और केंद्र सरकार ने 700 करोड़ रुपये ख़र्च किए. बाकी के 8000 करोड़ रुपये राजनीतिक दलों और उम्मीदवारों ने ख़र्च किए. अब सवाल यह है कि 8000 करोड़ रुपये राजनीतिक दलों और उम्मीदवारों के पास कहां से आए. यह पैसा राजनीतिक दलों को बड़े-बड़े उद्योगपति देते हैं. उद्योगपति किसी विचारधारा या देशभक्ति के नाम पर पैसे नहीं देते, वे सरकार चलाने वाली पार्टी और विपक्ष दोनों को ही पैसे देते हैं. यह पैसा इसलिए दिया जाता है कि सरकार बनने के बाद वे उनके लिए मुनाफा कमाने का रास्ता साफ़ करेंगे. सरकार की मदद से उद्योगपति जितना पैसा राजनीतिक दलों को देते हैं, उससे दस गुना ज़्यादा पैसा कमाते हैं. चुनाव जीतने के लिए राजनीतिक दल उद्योगपतियों से पैसे लेते हैं और सरकार बनाने के बाद उनकी साठगांठ से जनता और सरकारी ख़ज़ाने को लूटते हैं, देश में बड़े-बड़े घोटालों को अंजाम देते हैं. यही वजह है, जब हमाम में सब नंगे हैं तो सरकारी संस्थाएं किसे पकड़ें और किसे छोड़ें. नतीजा सामने है, आज तक किसी भी नेता को किसी घोटाले के तहत सज़ा नहीं मिली. देश का राजनीतिक तंत्र अपने ही जाल में फंस चुका है. इसलिए यह बात बिल्कुल तय है कि भ्रष्टाचार के ख़िलाफ़ देश की राजनीतिक पार्टियां दिखावे का शोरशराबा और टीवी कैमरे के सामने हंगामा करने के अलावा कुछ नहीं करेंगी. उनसे उम्मीद करना बेकार है. पंद्रह दिनों तक संसद में जो हंगामा होता रहा, वह राजनीति से प्रेरित है. भारतीय जनता पार्टी केंद्र सरकार से आदर्श घोटाले और 2-जी स्पेक्ट्रम घोटाले में जेपीसी की मांग तो करती रही, लेकिन जब येदियुरप्पा का मामला सामने आया तो उसकी ज़ुबान बंद हो गई. कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी में इस बात की प्रतियोगिता शुरू हो गई कि कौन किससे कितना कम भ्रष्ट है. अब तो राजनीतिक दल ख़ुद को भ्रष्ट बताए जाने पर शर्मिंदगी महसूस नहीं करते. राजनीतिक दल भ्रष्टाचार के ख़िलाफ़ कोई क़दम नहीं उठाने वाले हैं.

सुप्रीम कोर्ट की इस बात की सराहना होनी चाहिए, क्योंकि जजों के भ्रष्टाचार की कहानियों के बीच सुप्रीम कोर्ट का बयान डूबते हुए जहाज के सामने एक द्वीप के समान है, आशा की आख़िरी किरण की तरह है. उस पर भरोसा करने के अलावा कोई दूसरा चारा नहीं है. सुप्रीम कोर्ट की यह चेतावनी देश के नौजवानों को सुननी होगी. नई पीढ़ी एवं युवा भारत को भ्रष्टाचार के ख़िलाफ़ आगे आना होगा. नहीं तो यह देश आने वाली पीढ़ियों के लिए अभिशाप साबित होने वाला है.

जब हम नई पीढ़ी या युवा भारत की बात करते हैं तो इसमें राहुल गांधी, वरुण गांधी और राहुल महाजन जैसे लोगों को इस श्रेणी से अलग रखते हैं. राहुल गांधी का युवा भारत का सर्वमान्य नेता बनने का सपना है. यही उनकी और उनकी पार्टी की ख्वाहिश है. उनके एजेंडे में पार्टी को मज़बूत करना ज़्यादा ज़रूरी है, लेकिन भ्रष्टाचार के ख़िलाफ़ युवाओं को एकजुट करना उनकी रणनीति में नज़र नहीं आता. राहुल गांधी कांग्रेस के दूसरे

(शेष पृष्ठ 2 पर)

भ्रष्टाचार पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा

"सरकार कोई प्राइवेट बिजनेस हाउस नहीं है."

"हमने नदियों ख़ासकर गंगा के प्रदूषण के बारे में सुना है, लेकिन यह प्रदूषण पर्यावरण प्रदूषण से भी ज़्यादा ख़तरनाक है. टेप से हुए खुलासे दिमाग़ हिलाने वाले हैं."

-जस्टिस सिंघवी

"दूरसंचार विभाग के सचिव के रूप में थॉमस ने 2-जी स्पेक्ट्रम मामले में कई ऐसी कार्रवाइयों को जायज़ ठहराया था, जिनकी सीबीआई आज जांच कर रही है. सीबीआई सीवीसी के तहत काम करती है तो ऐसे में थॉमस जांच की देखरेख कैसे कर पाएंगे?"

"ए राजा ने 2-जी स्पेक्ट्रम आवंटन के पहले अटार्नी जनरल का मत जानने की विधि मंत्रालय की सलाह को संदर्भहीन माना."

साल की शुरुआत में अप्रैल महीने में संयुक्त सचिव-डिजास्टर मैनेजमेंट ओ रवि को रिश्वतखोरी के आरोप में सीबीआई ने गिरफ्तार किया था.

दिल्ली का बाबू

दिलीप चेरियन

गृह मंत्रालय सकते में

कॉरपोरेट घरानों को अवैध रूप से सूचनाएं देने के आरोप में गृह मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारी रवि इंदर की पहले गिरफ्तारी और फिर निलंबन ने मंत्रालय के शीर्ष अधिकारियों की पेशानी पर बल डाल दिए हैं. आंतरिक सुरक्षा वैसे ही गृह मंत्रालय की नीतियों के केंद्र में होती है. रवि इंदर सिंह की गिरफ्तारी के बाद सेक्स और पैसे के प्रति उनके लालच को सुर्खियां मिलीं, लेकिन मंत्रालय इसलिए ज्यादा चिंतित है, क्योंकि सिंह तीसरे ऐसे अधिकारी हैं, जिन्हें एक साल के अंदर इस तरह की कारगुजारियों के लिए गिरफ्तार किया गया है या छापे मारे गए हैं. साल की शुरुआत में अप्रैल महीने में संयुक्त सचिव-डिजास्टर मैनेजमेंट ओ रवि को रिश्वतखोरी के आरोप में सीबीआई ने गिरफ्तार किया था. इसके बाद आर एस शर्मा भी ऐसे ही आरोपों के चलते जांच एजेंसियों के घेरे में आए थे. लेकिन रवि इंदर सिंह के मामले को जिस तरह सुर्खियां मिलीं, उससे मंत्रालय के अधिकारी सकते में हैं. सूत्रों के मुताबिक, खुद गृह सचिव जी के पिल्लई ने सिंह के फोन टेप किए जाने के निर्देश दिए थे, जिसके आधार पर उनकी गिरफ्तारी हुई. अपनी साफ-सुथरी छवि के लिए पहचाने जाने वाले पिल्लई और गृहमंत्री पी चिदंबरम भ्रष्ट अधिकारियों पर लगाम कसने के लिए कृतसंकल्प हैं. आने वाले समय में गृह मंत्रालय शीर्ष पदों पर नियुक्त किए जाने वाले अधिकारियों के पिछले रिकॉर्ड की ज्यादा कड़ाई से जांच-पड़ताल कर सकता है. रवि इंदर सिंह मामले पर मचे शोरगुल का यह एक अच्छा परिणाम हो सकता है.

नौकरशाह भी नपेंगे

जब कभी घोटालों की बात होती है तो अक्सर यह सवाल पूछा जाता है कि क्या इसमें शामिल नौकरशाहों को भी बाहर का रास्ता नहीं दिखाया जाना चाहिए? ऐसे उदाहरण बार-बार देखने को मिले हैं, जब नौकरशाह तो बच निकलते हैं, लेकिन उनके राजनीतिक आकाओं की बलि चढ़ जाती है. मुंबई हमले के बाद भी राजनीतिज्ञों को ही अपना पद छोड़ना पड़ा था, जबकि गलतियों के लिए जिम्मेदार अधिकारी अपना काम पहले की तरह ही करते रहे. लेकिन आरोपों और घोटालों के इस मौसम में हालात में कुछ बदलाव के संकेत मिल रहे हैं. जब सारे देश में स्पेक्ट्रम घोटाला, हाउसिंग लोन घोटाला, राष्ट्रमंडल खेल घोटाला और अन्य बड़े घोटालों को लेकर कोहराम मचा है तो नौकरशाह भी इसकी तपिश महसूस कर रहे हैं. इसकी शुरुआत महाराष्ट्र के नए मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण ने की, जब उन्होंने आदर्श घोटाले में शामिल अधिकारियों को निशाने पर लिया और अब सीबीआई भी राष्ट्रमंडल खेल एवं हाउसिंग लोन घोटाले में शामिल दागी अधिकारियों के पीछे पड़ गई है. हालांकि सत्ता के गलियारों से भ्रष्टाचार खत्म करने की इस मुहिम के पीछे असली वजह जनता का डर है और उसका विश्वास भी दोबारा हासिल करना है, लेकिन सरकार यदि अपने रुख पर कायम रहे तो देश में नौकरशाही के काम करने का तरीका बदल सकता है.

dilipcherian@gmail..com

साउथ ब्लॉक

चंद्रमौली को अतिरिक्त प्रभार

स्वास्थ्य मंत्रालय में सचिव के चंद्रमौली को नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन (नाको) का भी अतिरिक्त प्रभार दे दिया गया है. अब 1977 बैच के उन आईएएस अधिकारियों का इंतजार थोड़ा और लंबा हो सकता है, जो इस पद के लिए आस लगाए बैठे थे.

राव को सेवा विस्तार

कैबिनेट ने विदेश सचिव निरूपमा राव को 7 महीने का सेवा विस्तार देने के लिए फंडामेंटल रूल्स में संशोधन पर मुहर लगा दी है. निरूपमा राव का कार्यकाल दिसंबर में खत्म होने वाला था.

योजना आयोग में नया सलाहकार

प्रेम नारायण को योजना आयोग में सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया है. यह पद अतिरिक्त सचिव के समकक्ष है. प्रेम 1978 बैच और उत्तर प्रदेश कैडर के आईएएस अधिकारी हैं.

डीजीसीए का मुखिया?

उत्तर प्रदेश कैडर के आईएएस अधिकारी नसीम जैदी की नागरिक उड्डयन मंत्रालय में सचिव पद पर नियुक्ति के बाद अब सवाल यह है कि डीजीसीए का नया मुखिया कौन होगा?

नादादूर पहुंचे स्पेस

डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस में नए सचिव की नियुक्ति कर दी गई है. आर जी नादादूर को सचिव बनाया गया है. वह कर्नाटक कैडर और 1980 बैच के आईएएस अधिकारी हैं.

सुप्रीम कोर्ट की चेतावनी

पृष्ठ 1 का शेष

सबसे शक्तिमान नेता हैं. उनके एक इशारे पर घोटालेबाज़ सलाखों के पीछे जा सकते हैं, लेकिन राहुल गांधी चुप हैं. राहुल गांधी मीडिया में ज़्यादातर चुनावों में भाषण देते नज़र आए हैं, कभी गांव में ग़रीबों के साथ खाना खाते तो कभी नरेगा के मज़दूरों के साथ मिट्टी उठाते नज़र आए हैं. राहुल नरेगा के मज़दूरों से मिलते हैं, उत्तर प्रदेश से मुंबई की ट्रेन में आम लोगों की परेशानी समझने की कोशिश करते हैं. गांवों में जाकर रात बिताते हैं, ग़रीबों के यहां खाना खाते हैं. क्या वह यह सब पर्यटन, देशाटन या फिर मौज़मस्ती के लिए करते हैं. अगर नहीं, तो क्या आज तक उन्हें किसी ने यह नहीं बताया कि केंद्र की नरेगा जैसी योजना हो या फिर राज्य सरकार की कोई योजना, मंत्रालय से लेकर पंचायत तक भ्रष्टाचार का बोलबाला है. क्या अब तक उन्हें यह पता नहीं चल पाया कि बिना घूस और कमीशन के सरकारी दफ्तरों में काम नहीं होता. क्या उन्हें पता नहीं है कि हमारे देश में दो भारत हैं. एक वह, जो भ्रष्टाचार और घोटाला करता है और दूसरा भारत वह है, जो इन कुकर्मों का फल भुगतता है. जब तक घोटालों का पर्दाफ़ाश नहीं हुआ था तो राहुल यह भी कहा करते थे कि दिल्ली से भेजा गया एक रुपया गांव तक पहुंचते- पहुंचते 15 पैसे बन जाता है. पचासी पैसे ग़ायब हो जाते हैं. जबसे घोटालों के सामने आने का दौर शुरू हुआ है, तबसे राहुल ने भ्रष्टाचार के ख़िलाफ़ बोलना ही बंद कर दिया है.

भारतीय जनता पार्टी के युवा नेता वरुण गांधी से भी उम्मीद नहीं है, क्योंकि उनकी विचारधारा में ग़रीबों और आम जनता के पैसे लूटने वाले नेताओं एवं अधिकारियों के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाने का कोई स्थान ही नहीं है. पार्टी लाइन का पालन करते हुए या फिर उससे हटकर वरुण गांधी जब मुंह खोलते हैं तो घृणा और हिंसा की बात करते हैं. भावनाओं को भड़काने और उससे फ़ायदा उठाने की कोशिश करते हैं. वरुण गांधी ने जो बात लोकसभा चुनाव के दौरान कही थी, अगर वही बात भ्रष्टाचारियों और घोटालेबाज़ों के लिए कही होती तो वह जनता के नायक बन गए होते. एक ही झटके में उनकी लोकप्रियता और राजनीतिक प्रासंगिकता राहुल गांधी से काफ़ी ज़्यादा हो जाती. देश की जनता उनसे कुछ उम्मीद भी करती, लेकिन राहुल गांधी की तरह वरुण गांधी भी चुप हैं. हमें राजनीतिक दलों की खाल ओढ़े ऐसे युवा नेताओं से बचना होगा, जो सिर्फ़ उम्र से युवा हैं. जाति और धर्म की आड़ में राजनीति चमकाने वाले इन युवा नेताओं से भ्रष्टाचार के ख़िलाफ़ लड़ाई लड़ने की उम्मीद नहीं करनी चाहिए. देश की जनता को राहुल महाजन जैसे युवाओं से भी बचना होगा, जो अपनी ज़िंदगी में इतने मदमस्त और परेशान हैं कि उन्हें समाज और देश के बारे में सोचने का वक़्त नहीं मिल पाता. ऐसे युवाओं से उम्मीद नहीं करनी चाहिए, जिनके जीवन का एकमात्र उद्देश्य निजी स्वार्थ है. ऐसे युवा नेताओं पर भरोसा नहीं किया जा सकता, जो अपने पिता या परिवार की बदौलत राजनीति में हैं, क्योंकि ये उसी भ्रष्ट तंत्र से उपजे हुए पौधे हैं, जिससे पूरा तंत्र खोखला हो चुका है.

भ्रष्टाचार से लड़ने के लिए उन युवाओं को आगे आना होगा, जिनका भविष्य दांव पर है. स्कूल, कॉलेज और विश्वविद्यालयों के विद्यार्थियों को सड़कों पर उतरना होगा, जो पढ़-लिखकर, मेहनत करके अपने भविष्य को संवारने का सपना देख रहे हैं. अगर वे सड़कों पर नहीं उतरते हैं तो भ्रष्टाचार का भूत उनकी मेहनत पर पानी फेर देगा और सपने सच होने के बजाय मृग मरीचिका में तब्दील हो जाएंगे. मज़दूरों और किसानों को इस भ्रष्टाचार के ख़िलाफ़ आंदोलन करना होगा, क्योंकि जो ग्रेटर नोएडा, दादरी, नंदीग्राम और सिंगूर में हुआ, वह भ्रष्टाचार का ही एक्सटेंशन है. यदि अब यह नहीं रोका गया तो देश में कई दादरी और नंदीग्राम पैदा हो जाएंगे. सरकारी तंत्र में फैले भ्रष्टाचार का सबसे ज़्यादा असर मध्यम वर्ग पर पड़ता है. इनमें वे लोग हैं, जो नौकरीपेशा या व्यापार करते हैं. ये भ्रष्टाचार के सबसे नग्न रूप से परिचित हैं, उसे आएदिन झेलते हैं, लेकिन चुपचाप सब कुछ सहन करते हैं, भ्रष्टाचारियों का साथ देते हैं. इस बार इन्हें भी भ्रष्टाचार के ख़िलाफ़ एकजुट होना होगा. देश के अल्पसंख्यकों को इस लड़ाई में महत्वपूर्ण भूमिका निभानी होगी. ऐसा देखा गया है कि जब भी समाज किसी जनांदोलन या परिवर्तन के लिए आगे आया है तो राजनीतिक दलों और उनसे जुड़े संगठनों ने देश में धार्मिक उन्माद फैलाया है. इस बार भी जब भ्रष्टाचार के ख़िलाफ़ लोगों का गुस्सा फूटेगा तो मंदिर-मस्जिद और हिंदू- मुसलमान के नाम पर समाज को बांटने की कोशिश होगी.

एक बात और कि वे लोग, जो बाज़ारवाद और उदारवाद के प्रवर्तक हैं, यह दलील देते हैं कि भ्रष्टाचार को अगर कम करना है तो देश में सरकार की भूमिका को ही कम करना पड़ेगा, लेकिन 2-जी स्पेक्ट्रम घोटाले से यह दलील चारों खाने चित हो गई. निजी कंपनियों ने एक ही झटके में सारे घोटालों के रिकॉर्ड को ध्वस्त कर दिया. इसलिए यह ज़रूरी है कि हमें भ्रष्टाचार से लड़ने के लिए सरकारी तंत्र की ही सफ़ाई करनी होगी. अगर इस मौक़े को गंवा दिया गया तो फिर देर हो जाएगी. भ्रष्टाचार को रोकने का सबसे कारगर तरीका सरकार के कामकाज में पारदर्शिता, सेल्फ गवर्नेंस, समय निर्धारित योजनाएं, उत्तरदायित्व आदि हैं. सरकार के हर काम पर लोगों की नज़र रहे, ऐसा प्रावधान ज़रूरी है. और इससे भी ज़्यादा ज़रूरी है कि भ्रष्टाचार के मामले में कड़ी और त्वरित कार्रवाई हो. जिस तरह से नेताओं से चुनाव के दौरान प्रॉपर्टी का लेखा-जोखा लिया जाता है, वैसा ही लेखा-जोखा सरकारी अधिकारियों और सरकार से जुड़े लोगों से हर साल लिया जाए.

1947 से पहले हम अंग्रेजी हुकूमत के गुलाम थे, आज हम सभी एक भ्रष्ट व्यवस्था के गुलाम बन गए हैं. गांधी को राजनीतिक दलों ने अप्रासंगिक कर दिया है तो उनके द्वारा बताया संघर्ष का रास्ता भी अप्रासंगिक हो गया है. देश की जनता के सामने यह भी तरीका नहीं बचा है कि वह रिश्वत चुकाने से इंकार करके कोई उदाहरण पेश करे. अगर न्याय न हो तो शांति भी नहीं हो सकती. और न्याय तब तक मुमकिन नहीं है, जब तक ईमानदार लोगों को ईमानदारी से जीने की इजाज़त नहीं मिलती. भ्रष्टाचार के ख़िलाफ़ अगर देश में हिंसक आंदोलन की शुरुआत हो जाए तो जनता इसका स्वागत करेगी और इसकी ज़िम्मेदारी भी राजनीतिक दलों और देश को खोखला करने वाले अधिकारियों की होगी.

manish@chauthiduniya.com

चौथी दुनिया
देश का पहला साप्ताहिक अखबार

वर्ष 2 अंक 40
दिल्ली, 13 दिसंबर-19 दिसंबर 2010
RNI-DELHIN/2009/30467

संपादक
संतोष भारतीय

मैसर्स अंकुश पब्लिकेशंस प्राइवेट लिमिटेड के लिए मुद्रक व प्रकाशक रामपाल सिंह भदौरिया द्वारा जागरण प्रकाशन लिमिटेड डी 210-211 सेक्टर 63, नोएडा उत्तर प्रदेश से मुद्रित एवं के- 2, गैनन, चौधरी बिल्डिंग, कनॉट प्लेस, नई दिल्ली 110001 से प्रकाशित

संपादकीय कार्यालय

के-2, गैनन, चौधरी बिल्डिंग
कनॉट प्लेस, नई दिल्ली 110001
कैंप कार्यालय एफ-2, सेक्टर -11, नोएडा
गौतमबुद्ध नगर उत्तर प्रदेश-201301

फोन न.

संपादकीय 0120-4783999/11-23418962
विज्ञापन + 91 9810017924
प्रसार + 91 9013478398
फैक्स न. 0120-4783950

पृष्ठ-16 (+4+4)

चौथी दुनिया में छपे सभी लेख अथवा सामग्री पर चौथी दुनिया का कॉपीराइट है. बिना अनुमति के किसी लेख अथवा सामग्री के पुनः प्रकाशन पर क़ानूनी कार्रवाई की जाएगी.

समस्त कानूनी विवादों का क्षेत्राधिकार दिल्ली न्यायालयों के अधीन होगा.

भारतीय व्यवस्था का काला सच

नीरा राडिया के टेप भारतीय व्यवस्था के उस पहलू को उजागर करते हैं, जो सत्ता सूत्र और भ्रष्ट तत्वों के बीच की साठगांठ पर आधारित है और देश के कॉरपोरेट एवं राजनीतिक तंत्र के बीच गोंद का काम करता है. जैसा कि स्कूल जाने वाला कोई सुकुमार बच्चा अच्छी तरह जानता है कि चीर-फाड़ का काम बड़ा ही मुश्किल होता है. कुछ बच्चे इससे बचने के लिए हरसंभव उपाय करते हैं तो कुछ बच्चे घबरा जाते हैं या डर जाते हैं. किसी जैविक तंत्र की अंदरूनी संरचना को बर्दाश्त करने की ताक़त हर किसी के पास नहीं होती. कुछ दिन पहले अलग-अलग लोगों के बीच टेलीफोन पर हुई बातचीत के 104 ब्योरों के चाकू ने भारतीय व्यवस्था के उस हिस्से को नंगा कर दिया, जो भ्रष्टाचार के दलदल में पूरी तरह धंसा हुआ है. इससे जो बात खुलकर सामने आई, वह इतनी अरुचिकर है कि ब्रेकिंग और एक्सक्लूसिव ख़बरों के पीछे पड़े रहने वाले कई प्रमुख अख़बारों और टेलीविज़न न्यूज़ चैनलों ने अपनी निगाहें दूसरी ओर मोड़ लीं. उनकी यह चुप्पी हालांकि समझ से परे नहीं है, लेकिन निराशाजनक है और माफी के काबिल भी नहीं है. आख़िर नीरा राडिया की फोन बातचीत के ये टेप तब सामने आए हैं, जबकि इसके ठीक पहले 2-जी स्पेक्ट्रम के लाइसेंस आवंटन पर सीएजी की रिपोर्ट आई है और इसमें यह स्पष्ट रूप से बताया गया है कि तत्कालीन संचार मंत्री ए राजा ने कुछ निजी कंपनियों को फ़ायदा पहुंचाने के लिए राष्ट्रीय हितों की क़ीमत पर नियम- क़ानूनों की धज्जियां उड़ाईं. राजा की कारगुजारियों से लाभांवित होने वालों में अनिल अंबानी और रतन टाटा भी शामिल थे. एक टेप में एक अज्ञात शख्स राडिया से, जिनके क्लाइंट्स में टाटा और मुकेश अंबानी शामिल हैं, पूछता है कि मुकेश अंबानी ग्रुप राजा का समर्थन क्यों कर रहा है, जबकि स्पेक्ट्रम आवंटन से सबसे ज़्यादा फ़ायदा अनिल अंबानी को हो रहा है. इस पर राडिया जवाब देती हैं कि यह मामला बड़ा पेचीदा है, क्योंकि रतन टाटा भी उसके क्लाइंट हैं और उन्हें भी फ़ायदा हो रहा है.

दूरसंचार के अलावा राडिया के ये टेप अंबानी बंधुओं के बीच गैस विवाद पर भी रोशनी डालते हैं. इस विवाद में मुकेश अंबानी ने गैस एक राष्ट्रीय संसाधन है के तर्क का मीडिया की मदद से बड़ी दक्षता से इस्तेमाल किया था. दूसरी ओर सांसदों के साथ अपने व्यक्तिगत संबंधों की मदद से उन्होंने कृष्णा गोदावरी बेसिन में अपनी कंपनी के लिए टैक्स में छूट के लिए हरसंभव कोशिश भी की थी. ऐसा करते वक़्त तेल के राष्ट्रीय संसाधन होने का तर्क वह बड़ी सफाई से भूल गए थे. एनडीटीवी और इंडियन एक्सप्रेस, दो ऐसे मीडिया घराने जो टेप कांड से बचने की कोशिश करते रहे हैं, को दिए गए एक इंटरव्यू में रतन टाटा ने इन टेपों को धुएं का ऐसा गुबार बताया, जिसका असली मक़सद सच्चाई पर पर्दा डालना है. लेकिन टाटा के इस बयान में रत्ती भर सच्चाई नहीं है, वह झूठ बोल रहे हैं. हमें यह पता नहीं कि इन टेपों को किसने लीक किया. प्रवर्तन निदेशालय और आयकर अधिकारियों ने राडिया पर निगाह रखने के लिए 5000 से भी ज़्यादा बातचीत रिकॉर्ड कराई थीं, उनमें से इन टेपों का चुनाव किसने किया, हमें यह भी पता नहीं. लेकिन इन टेपों से जो कहानी उभर कर सामने आती है, भले ही वह कॉरपोरेट लॉबिंग के कुछ खास पहलुओं को ही उजागर क्यों न कर रही हो, उसके तथ्यों की न तो हम अनदेखी करने का जोखिम ले सकते हैं, न ही उसे झुठला सकते हैं. फिक्शन फिल्म द मैट्रिक्स में मॉर्फस नियो से कहता है, तुम यहां इसलिए हो, क्योंकि तुम जानते हो कि इस दुनिया में कुछ गड़बड़ है. द मैट्रिक्स की अहमियत के बारे में वह कहता है कि इसका वजूद ही इसीलिए है कि लोगों की आंखों पर पर्दा डालकर उन्हें इस सच्चाई से दूर रखा जाए कि वे गुलाम हैं. वह नियो को दो तरह की गोलियों का विकल्प देता है, नीली और लाल गोलियां. नीली गोलियां लो और कहानी वहीं ख़त्म हो जाती है. तुम अपने बिछावन से उठो और जो चाहो, उस पर भरोसा कर लो. लाल गोली लो और फिर मैं तुम्हें दिखाता हूं कि इस गड़बड़झाले की जड़ें कितनी गहरी हैं.

पिछले दिनों आउटलुक और ओपन पत्रिकाओं द्वारा नीरा राडिया के जो टेप इंटरनेट पर डाले गए हैं, वे हमारे जमाने की लाल गोलियां हैं. ये भारतीय राज्य के वायरस, सोर्स कोड, नेटवर्क और गंदगी के मैट्रिक्स के बारे में बताती हैं. व्यवस्था सुचारू रूप से चलती रहे, इसके लिए ज़रूरी है कि इसके विभिन्न केंद्रों के बीच सूचना, जिसे हम ख़बर का नाम भी दे सकते हैं, का आदान-प्रदान होता रहे. व्यवस्था के विभिन्न अंगों के बीच समस्याओं को सुलझाने का माध्यम भी ख़बर ही होती है. यदि आप इस रिकॉर्डिंग को सुनते हैं तो आपको पता चल जाएगा कि भारतीय व्यवस्था की सच्चाई क्या है. कोई आश्चर्य नहीं, यदि हम में से अधिकांश लोग नीली गोली का विकल्प चुनना चाहेंगे, क्योंकि यदि आपने लाल गोली चुनी तो आप इस गड़बड़झाले की तहों में जाने के लिए मजबूर होंगे और यह भी सच्चाई है कि इस गड़बड़झाले की जड़ें काफी गहरी हैं. इसका इससे बड़ा उदाहरण और क्या हो सकता है कि इन टेपों में एन के सिंह, जो सांसद हैं और जिनसे हम उन लोगों का पक्ष रखने की उम्मीद रखते हैं जिन्होंने उन्हें चुना है, को मुकेश अंबानी के लिए उनके स्वार्थ वाले कॉरपोरेट क्षेत्र में एकाधिकार की वकालत करते हुए सुनते हैं. एक टेप में एन के सिंह राडिया को बताते हैं कि वह अंबानी को टैक्स में छूट के लिए वित्त मंत्री के पास पैरवी कर रहे हैं. वित्त मंत्री ने गैस उत्पादन में इस कर छूट की घोषणा 2009 में की थी और सिंह चाहते थे कि इस घोषणा को पिछली तारीख़ से ही लागू कर दिया जाए, ताकि अंबानी को इसका फ़ायदा हो सके. राडिया उन्हें बताती हैं कि टैक्स में छूट से रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड को होने वाले 81,000 करोड़ रुपये के मुनाफ़े वाली ख़बर को उन्होंने दबा दिया है, क्योंकि इस पर हंगामा हो सकता था, लेकिन सिंह इससे ज़्यादा संसद में वित्त विधेयक पर होने वाली बहस को लेकर फिक्रमंद थे.

उन्हें इस बात का डर था कि यदि विपक्षी दलों के सांसद एक खास कंपनी को सुविधा उपलब्ध कराने के मामले पर ज़्यादा शोरगुल करते हैं तो वित्त मंत्री शायद कुछ न कर पाएं और कर में छूट के फ़ैसले को पिछली तारीख़ से लागू करने की संभावना ही ख़त्म हो जाएगी. सिंह भाजपा नेता अरुण शौरी पर अनिल अंबानी का पक्ष लेने का आरोप लगाते हैं और यह भी बताते हैं कि उन्होंने वेंकैया नायडू से कहकर शौरी की जगह दूसरे नेता को इस मामले पर संसद में पार्टी का मुख्य वक्ता बनवा दिया है. बिहार से जदयू के टिकट पर संसद पहुंचे सिंह राडिया से पूछते हैं कि मुकेश अंबानी वेंकैया नायडू को कितना जानते हैं. राडिया बताती हैं कि आरआईएल के एक वरिष्ठ अधिकारी पी एम एस प्रसाद नायडू को अच्छी तरह जानते हैं. इस पर सिंह कहते हैं कि मैं आज ही प्रसाद को वेंकैया से मिलाने का प्रबंध करता हूं, क्योंकि पार्टी के पहले वक्ता के रूप में यदि वेंकैया नायडू पार्टी का स्टैंड ले लेते हैं तो शौरी चाहकर भी उससे ज़्यादा अलग नहीं बोल सकते. हमारी पहली चिंता यही है कि हमें संसद में होने वाली बहस को सुनियोजित करना होगा, क्योंकि यदि ऐसा नहीं हुआ और कर में राहत दिलाने में हम कामयाब नहीं होते हैं तो यह एक बड़ा झटका होगा. हम यह नहीं जानते कि एन के सिंह की इच्छा के अनुरूप पी एम एस प्रसाद वेंकैया नायडू से मिले या नहीं, लेकिन दो दिनों बाद उन्होंने संसद में जो भाषण दिया, वह कुछ इस प्रकार था, बंगाल की खाड़ी भारत का नया उत्तरी सागर बन चुकी है. सरकार के विभागों को इस मुद्दे पर झगड़ना नहीं चाहिए कि खनिज तेल प्राकृतिक गैस है या नहीं. तेल खदानों की खुदाई या आधारभूत संरचना के क्षेत्र में राहत का जो भी मामला है, वह देश की ऊर्जा सुरक्षा से जुड़ा है. नायडू के इस भाषण में पेट्रोलियम मंत्रालय द्वारा वित्त मंत्रालय को लिखी गई उस चिट्ठी की बू आती है, जिसमें प्राकृतिक गैस के लिए भी खनिज तेल की तरह कर में छूट की मांग की गई थी. पेट्रोलियम मंत्रालय प्राकृतिक गैस को केवल न्यू एक्सप्लोरिंग लाइसेंसिंग राउंड-3 के प्रावधानों के तहत ही कर में छूट से संतुष्ट नहीं था, क्योंकि रिलायंस इंडस्ट्रीज का केजी बेसिन इसके दायरे में नहीं आता था, लेकिन राजस्व सचिव ने पेट्रोलियम मंत्रालय की इस मांग को मानने से इंकार कर दिया था.

कुछ रिकॉर्डिंग्स में हम पत्रकारों और संपादकों, जिनका असल काम ख़बर देना और बेबाक विश्लेषण करना है, को कॉरपोरेट घरानों की आपसी लड़ाई में सिपाही और संदेशवाहक बनने की पेशकश करते हुए देखते हैं. इन टेपों में हम रंजन भट्टाचार्य को भी देखते हैं, जिनकी एकमात्र राजनीतिक पहचान भाजपा के एक बड़े नेता से पारिवारिक रिश्ता है. रंजन कांग्रेस नेताओं, खासकर गुलाम नबी आज़ाद से अपनी नजदीकियों की चर्चा करते हुए नजर आते हैं तो यह दावा भी करते हैं कि वह जब चाहें, एसजी बॉस को संदेश भेज सकते हैं. यहां एसजी बॉस से मतलब कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी से है. मुकेश अंबानी की चर्चा करते हुए रंजन कहते हैं कि मुकेश के लिए कांग्रेस अपनी दुकान की तरह है. यह हो सकता है कि रंजन अपनी पहचान और प्रभाव के बारे में झूठ बोल रहे हों, लेकिन राडिया को छोटा-मोटा ठग मानने की ग़लती हम नहीं कर सकते. देश के सबसे बड़े उद्योगपतियों में शुमार किए जाने वाले रतन टाटा आज भले ही देश में छद्म पूंजीवाद के बारे में भारी-भरकम बयान दे रहे हों, भारत के टुकड़ों में बंट जाने के ख़तरे के प्रति आगाह कर रहे हों, लेकिन इन टेपों में उनकी असलियत भी उजागर हो जाती है. वह अपनी पीआर एजेंट नीरा राडिया के माध्यम से ए राजा को संचार मंत्री बनाए जाने के लिए लॉबिंग करते नज़र आते हैं.

मनमोहन सिंह सरकार द्वारा साल 2008 और 2009 में स्पेक्ट्रम आवंटन यदि स्वतंत्र भारत के सबसे बड़े घोटालों में से एक है, तो मई 2009 में जब यूपीए दोबारा सत्ता में लौटा था और रतन टाटा, सुनील मित्तल और मुकेश अंबानी जैसे बड़े उद्योगपति जिस तरह अपनी पसंद के संचार मंत्री के लिए लॉबिंग कर रहे थे, वह इस पूरे घटनाक्रम का एक महत्वपूर्ण पहलू है. लेकिन राडिया के साथ घालमेल में शामिल रहे किसी भी पत्रकार ने इस ख़बर के बारे में कुछ नहीं बताया. द्रमुक के नेताओं के बीच आपसी सिर फुटौव्वल या द्रमुक और कांग्रेस के बीच की खींचतान से भी ज़्यादा बड़ी ख़बर कैबिनेट के गठन में बड़े औद्योगिक घरानों की भूमिका थी और इसे मीडिया में सुर्ख़ियां मिलनी चाहिए थी. राडिया सुनील मित्तल और एटी एंड टी कंपनी के बारे में बताती हैं कि वे टाइम्स नाउ न्यूज़ चैनल की मदद से ऐसी ख़बरें प्रचारित करा रहे थे कि संचार मंत्री बनने की होड़ में दयानिधि मारन सबसे आगे हैं और ए राजा को अपनी पार्टी के शीर्ष नेतृत्व का समर्थन हासिल नहीं है. वहीं ख़ुद राडिया बरखा दत्त और शंकर अय्यर जैसे बड़े पत्रकारों की मदद से एनडीटीवी और हेडलाइंस टुडे जैसे चैनलों पर इसके विपरीत ख़बरें प्रचारित कराने की रणनीति पर काम कर रही थीं, ताकि संचार मंत्रालय ए राजा को मिल सके. द्रविड़ मुनेत्र कड़गम के अंदर चल रही उठापटक के बारे में जानने के लिए राडिया को एक सूत्र के रूप में इस्तेमाल करने से ज़्यादा ज़रूरत इस बात की थी कि एक ऐसे मंत्री, जिसकी छवि उस समय भी संदेह से परे नहीं थी, को कैबिनेट में स्थान दिलाने के लिए उनकी और उनके क्लाइंट्स की भूमिका का खुलासा किया जाए. लेकिन दिल्ली तो सत्ता के मठाधीशों का केंद्र स्थल है और सत्ता का नशा ही कुछ ऐसा होता है कि उसके साथ नज़दीकियां आपके सोचने-समझने की क्षमता को शिथिल कर देती हैं. भारतीय पत्रकारों को आज सबसे बड़ी ज़रूरत दूरियां बढ़ाने की है राजनीतिज्ञों एवं उद्योगपतियों से. लाल गोली को निगलने का फ़ैसला कभी भी क्यों न लिया जाए, लेकिन कभी नहीं से तो देर ही भली.

सिद्धार्थ वरदराजन
feedback@chauthiduniya.com
द हिन्दू से साभार

सभी फोटो–प्रभात पाण्डेय

> नीरा राडिया की फोन बातचीत के ये टेप तब सामने आए हैं, जबकि इसके ठीक पहले 2-जी स्पेक्ट्रम के लाइसेंस आवंटन पर सीएजी की रिपोर्ट आई है और इसमें यह स्पष्ट रूप से बताया गया है कि तत्कालीन संचार मंत्री ए राजा ने कुछ निजी कंपनियों को फ़ायदा पहुंचाने के लिए राष्ट्रीय हितों की क़ीमत पर नियम- क़ानूनों की धज्जियां उड़ाईं. राजा की कारगुजारियों से लाभांवित होने वालों में अनिल अंबानी और रतन टाटा भी शामिल थे.

> दूरसंचार के अलावा राडिया के ये टेप अंबानी बंधुओं के बीच गैस विवाद पर भी रोशनी डालते हैं. इस विवाद में मुकेश अंबानी ने गैस एक राष्ट्रीय संसाधन है के तर्क का मीडिया की मदद से बड़ी दक्षता से इस्तेमाल किया था. दूसरी ओर सांसदों के साथ अपने व्यक्तिगत संबंधों की मदद से उन्होंने कृष्णा गोदावरी बेसिन में अपनी कंपनी के लिए टैक्स में छूट के लिए हरसंभव कोशिश भी की थी. ऐसा करते वक़्त तेल के राष्ट्रीय संसाधन होने का तर्क वह बड़ी सफाई से भूल गए थे.

बिहार चुनाव के परिणामों से भ्रम में आने की ज़रूरत नहीं है. बिहार में मतदाताओं ने नीतीश कुमार को इसलिए वोट नहीं दिया कि लालू पर भ्रष्टाचार के गंभीर मामले थे.

भ्रष्टाचार के ख़िलाफ़ खड़े होने की राजनीति

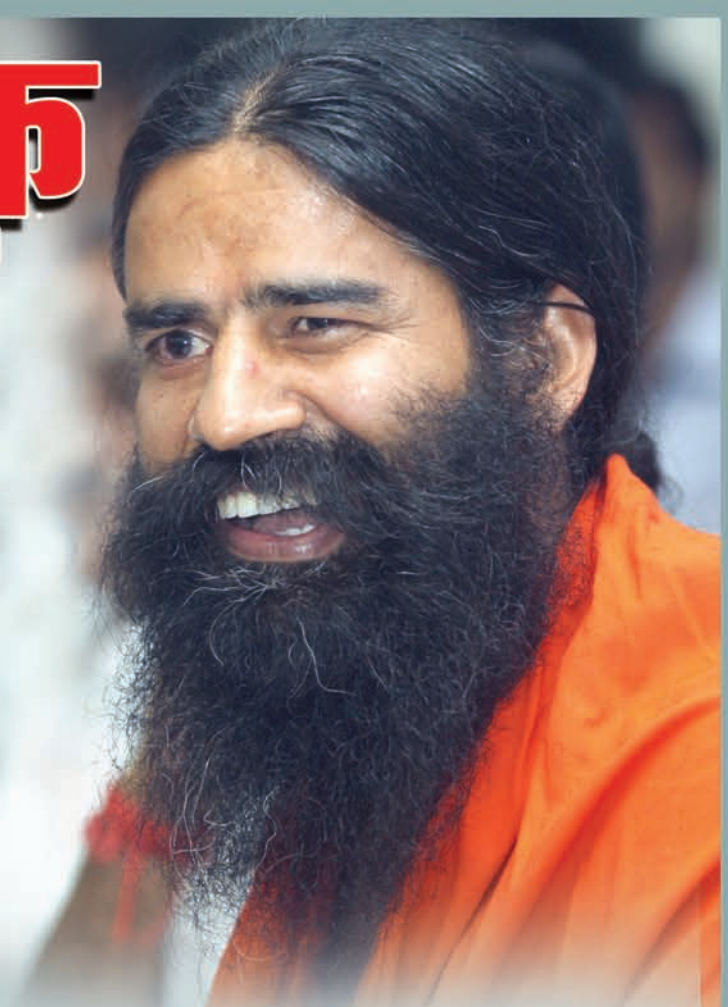

सरकार में घोटालेबाज़ या घोटालेबाज़ों की सरकार, फ़र्क़ करना मुश्किल हो गया है. घोटालों के नाम भी ऐसे कि सिर चकरा जाए. चारा, अलकतरा, चीनी, खाद, शेयर, स्पेक्ट्रम और आदर्श भी. ऐसे में एक बाबा भ्रष्टाचार के ख़िलाफ़ हल्ला बोलने की बात करते हैं, वह भी राजनीति में सक्रिय होकर. क्या यह कोशिश सफ़ल होगी? सवाल इसलिए, क्योंकि यह समझना बाक़ी है कि बाबा राजनीति में भ्रष्टाचार की बात कर रहे हैं या भ्रष्टाचार के नाम पर राजनीति.

प्रभात रंजन दीन

अब भ्रष्टाचार पर राजनीति हो रही है. कभी कोई दल घेरे में तो कभी कोई. अभी घेरे में कांग्रेस और भाजपा है. भ्रष्टाचार में आकंठ डूबे क्षेत्रीय राजनीतिक दल, खास तौर पर उत्तर प्रदेश की बहुजन समाज पार्टी चुप्पी साधे सियासत का तापमान देख रही है. ऐसे में योग गुरु बाबा रामदेव की राजनीतिक परिवर्तन लाने की पहल आंधी में पतंग उड़ाने जैसी है. योग और राजनीति में मौलिक भारतीय फ़र्क़ बाबा को दिख नहीं रहा है. भारतीय लोकतंत्र की साठ साला सीख में यहां के लोग दैहिक स्वास्थ्य के प्रति जागरूक हुए हैं, लेकिन नैतिक स्वास्थ्य के प्रति उतने ही लापरवाह. यह लापरवाही सोची-समझी है और भ्रष्टाचार में शरीक होने की सामाजिक अभिव्यक्ति है. आज़ादी के बाद भारतीय लोकतंत्र में राजनीति को धन बटोरने का पेशा बना दिया जाना, नेताओं का ख़ुद घूस खाना और दूसरों को नैतिक नसीहतें देना, लोकतांत्रिक रास्तों से निर्मित सत्ता के गलियारों में नोट गिनने की मशीनें स्थापित होना, राष्ट्रधर्म के मायने राष्ट्र का धन लूटकर विदेशी बैंकों में जमा करना होना, पंचायतों तक पहुंचे सत्ता सूत्र को भ्रष्ट कमाई का ज़रिया माना जाना और सरकारी योजनाओं का धन की लूट का माध्यम बन जाना आदि भ्रष्टाचार के ग्रास रूट लेवल तक पहुंचने का सामाजिक ऐलान है. राजनीतिक धरातल पर अभी जो कुछ भी बाबा रामदेव कर रहे हैं, वह सब फौरी और सतही है. बाबा के मुंह खोलने पर भले ही केंद्र की सरकार संभालने वाली कांग्रेस और उत्तराखंड में सत्ता संभालने वाली भाजपा बैकफुट पर दिखती हो, कर्नाटक के मुख्यमंत्री येदियुरप्पा भले ही आरोपों के दायरे में दिखते हों, उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री भुवनचंद खंडूरी बाबा पर भले ही गुस्सा दिखाते हों और मौजूदा मुख्यमंत्री रमेश पोखरियाल निशंक घूस मांगने वाले मंत्री के नाम का खुलासा करने की चुनौती देकर अपने बचाव की जुगत करने लगते हों, पर यह सब उस कहावत की तरह है कि बाबा भी लग्गी से घास हटा रहे हैं.

बिहार चुनाव के परिणामों से भ्रम में आने की ज़रूरत नहीं है. बिहार में मतदाताओं ने नीतीश कुमार को इसलिए वोट नहीं दिया कि लालू पर भ्रष्टाचार के गंभीर मामले थे. अगर ऐसा होता तो बिहार में राबड़ी देवी लालू की डमी मुख्यमंत्री कभी नहीं बनतीं. विकास मुद्दा बन सकता है, क्योंकि देश के लोगों को सुविधाएं चाहिए. लेकिन भ्रष्टाचार मुद्दा नहीं बन सकता, क्योंकि इसका रसास्वादन अब ऊपर से लेकर नीचे तक के पायदान पर खड़े लोग कर रहे हैं. समाज से स्वाद की वर्जनाएं समाप्त हो गई हैं. सुविधाओं के लिए विकास ज़रूरी है और भ्रष्टाचार का विरोध सादे जीवन की साधना है. दोनों अलग-अलग मसले और मसाइल हैं. योग को फिर से पुनर्जीवित करने वाले बाबा रामदेव इस साधना के भाव को पुनर्जीवित करने के बजाय राजनीति को साधने की कोशिश कर रहे हैं. जिन लोगों के बूते राजनीति साधी जा सकती है, उन्हें नैतिक योग का प्रशिक्षण दिए बग़ैर उनके बल पर सत्ता हासिल करने और सत्ता के ज़रिए भ्रष्टाचार ख़त्म करने का बीड़ा बाबा को बहुत पीड़ा देने वाला है. देश के लोगों को नेताओं ने राज-नैतिक स्कूलिंग से दूर रखा और भ्रष्टाचार को शीर्ष से लेकर निम्न तक ले जाने का लगातार प्रयास किया, ताकि जनता की एक छोटी इकाई भी इतना नैतिक मनोबल न रख पाए कि दूसरे के भ्रष्टाचार पर उंगली उठा सके. नेताओं ने पूरे देश को छद्म सिखाया. जो जितना बड़ा झूठा और चोर, वह उतना ही बड़ा नीति वक्ता.

बाबा रामदेव के राजनीति में उतरने को लेकर नित्यानंद पुरी या किसी भी अन्य की प्रतिक्रिया के अपने-अपने पूर्वाग्रह और निहितार्थ हो सकते हैं, लेकिन शरीर से लेकर लोकतंत्र तक को शुद्ध करने की बाबा रामदेव की प्रतिज्ञा की मंशा पर देश को कोई संदेह नहीं है. लोगों में विकल्प की तलाश और छटपटाहट तो है, लेकिन इसकी वजह भ्रष्टाचार कतई नहीं. विकल्प की छटपटाहट महंगाई को लेकर हो सकती है, कुशासन को लेकर हो सकती है, अपराध के कारण अपनी असुरक्षा को लेकर हो सकती है, लेकिन भ्रष्टाचार को लेकर नहीं. भ्रष्टाचार के कारण विकल्प तलाशने की छटपटाहट रहती तो साठ साल नहीं लगते और देश गिरवी न रख दिया जाता. अगर भ्रष्टाचार के कारण विकल्प तलाशने की छटपटाहट रहती तो लालू यादव, मधु कोड़ा, शिबू सोरेन, मायावती, जयललिता, सुखराम, गेगांग अपांग, येदियुरप्पा, ए राजा और जाने ऐसे कितने राजाओं को भारतीय लोकतंत्र की प्रजा बार-बार कतई नहीं चुनती. संसद से लेकर विधानसभाएं तक भ्रष्टाचारियों, अपराधियों, लुटेरों, डकैतों, बलात्कारियों और तस्करों से नहीं भर जातीं. शशि थरूर पहले नहीं चले जाते और ए राजा के मसले पर पूरी सत्ता मौन नहीं साधे रहती. भ्रष्टाचार का विनाश अकेले बाबा के बूते की बात नहीं. यह देश की नस्लों को पुरखे राजनीतिज्ञों से संस्कार में मिला है.

आज़ादी के फ़ौरन बाद से ही देश में पवित्र लोकतांत्रिक माहौल का सृजन करने के बजाय शुरुआत ही जीप घोटाले से हुई. संवेदनशील कश्मीर ऑपरेशन में ही ब्रिटेन में भारत के उच्चायुक्त वी के कृष्ण मेनन ने नियमों को ताक पर रखकर एक विदेशी फर्म से जीपें ख़रीद लीं. अनंत शयनम अयंगार की अध्यक्षता में न्यायिक जांच कमेटी भी गठित हुई और बाद में एकतरफा जांच बंद भी कर दी गई. कृष्ण मेनन नेहरू मंत्रिमंडल में काबीना मंत्री का दर्जा भी पा गए. फिर भ्रष्टाचार का सिलसिला शुरू हो गया. 1951 में मुदगल केस, 1957 में मूंद्रा डील, 1963 में मालवीय-शिराजुद्दीन स्कैंडल, 1963 में ही प्रताप सिंह कैरों का मामला सामने आया. फिर तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी द्वारा स्टेट बैंक के चीफ कैशियर वी पी मल्होत्रा से 60 लाख रुपये मांगे जाने का मामला उजागर हुआ. उसके बाद तो फेयरफैक्स, एचबीजे पाइपलाइन, टेलीकॉम घोटाला, एचडीडब्लू पनडुब्बी ख़रीद घोटाला, बोफोर्स घोटाला, नरसिम्हाराव कार्यकाल में झामुमो घूस प्रकरण, फ्रांस के साथ एयरबस-320 ख़रीद घोटाला, हर्षद मेहता शेयर घोटाला, गोल्ड स्टार स्टील घोटाला, जैन हवाला केस, यूरिया घोटाला, अलकतरा घोटाला, तांसी भूमि घोटाला, चुरहट लॉटरी घोटाला, चारा घोटाला एवं 2-जी स्पेक्ट्रम जैसे घोटालों और इनमें राजनीतिज्ञों की मिलीभगत की तो जैसे झड़ी लग गई. घोटालों और भ्रष्टाचार की इस झड़ी की तरह घोटाला करने वाले नेताओं की चुनाव में जीतों की भी झड़ी लगी रही. यह क्रम लगातार जारी है. यह भारतीय लोकतंत्र और भारतीय लोक की असलियत है.

सचमुच भारतीय लोकतंत्र राजा नंद का दरबार हो गया है और बाबा रामदेव चाणक्य की भूमिका में हैं, लेकिन चंद्रगुप्त की चमक और प्रतिबद्ध फौज की धमक सुनाई नहीं पड़ रही. यदि चंद्रगुप्त भी बाबा ही बनना चाहते हैं तो वह भी राजनीतिक ह्रास का पात्र बनेंगे और उनका दल भी दलों के दलदल में धंसा मान लिया जाएगा. सवाल केवल नेतृत्वकर्ता चंद्रगुप्त का नहीं है, सवाल केवल प्रतिबद्ध फौज (कार्यकर्ताओं) का भी नहीं है. सवाल है भ्रष्टाचारी व्यवस्था को ध्वस्त करने के औज़ार का, सवाल है देश की नस्लों के संस्कार में दीमक की तरह जा घुसे भ्रष्टाचार के कीड़े को नष्ट करने की दवा का और सवाल है भ्रष्टाचार के ख़िलाफ़ खड़े होने की समवेत मनोवृत्ति का. केवल स्विस बैंक का पैसा वापस ले आना ही समस्या का हल नहीं है. आज़ादी के बाद से जितने भी घोटाले हुए, उनकी रकम की वापसी भी समस्या का हल नहीं है. वापस हुई रकम किन हाथों से फिर ख़र्च होगी और इसकी पाई-पाई की ईमानदारी की गारंटी क्या होगी, सवाल यह भी है और यह समस्या भी है. भ्रष्टाचार करने वाले नेताओं और नौकरशाहों की भारी जमात को उसकी करतूतों की सख्त सज़ा क्या कम बड़ा सवाल है? और अगर ऐसे लोगों को सज़ा नहीं मिली और वे समाज से बहिष्कृत नहीं हुए तो फिर बाबा की कठिन कसरत का औचित्य क्या रहेगा? भ्रष्टाचार के ज़रिए विदेशी बैंकों में जमा पैसे की महज़ वापसी क्या हमें नैतिक रूप से संस्कारित करने में सक्षम होगी?

हम साठ साल से पीछे नहीं जाना चाहते. हमारे समक्ष उदाहरण है पड़ोसी देश चीन का, जिसने इन साठ वर्षों में ख़ुद को कितना कद्दावर बना लिया. भ्रष्टाचार से लेकर आबादी बढ़ाते जाने की अनैतिक हरकतों के ख़िलाफ़ चीन की सख्ती ने उसे कहां से कहां लाकर खड़ा किया. लेकिन जिस देश में, जिसकी जितनी संख्या भारी-उसकी उतनी हिस्सेदारी जैसी ग़ैर ज़िम्मेदार और निर्लज्ज नारेबाज़ी लोकतंत्र का मुख्य आधार बनती हो, जिस देश के संसाधनों की उपलब्धता और उसकी हिफाज़त का ख्याल किए बग़ैर ओछे स्वार्थों से आबादी बढ़ाई जाती हो, जिस देश की एक बड़ी आबादी को लोकतंत्र के मायने नहीं पता, जहां वह केवल वोट डालने का उपकरण मात्र हो, जिस देश में ज़िम्मेदारी से एक-दो बच्चे पैदा करने वाले नागरिकों की कोई लोकतांत्रिक कद्र नहीं, जिस देश में लोगों ने थूकने और शौच करने का तौर-तरीक़ा नहीं जाना, उस देश के लोगों से नैतिकता और समझदारी की उम्मीद विकास पर वोट डालने मात्र से नहीं की जा सकती. बाबा समझ रहे हैं न!

prabhatranjandeen@chauthiduniya.com

घोटाला टॉप 10

2 जी स्पेक्ट्रम	2008	1.76 लाख करोड़
राष्ट्रमंडल खेल	2009-10	70 हज़ार करोड़
स्टांप पेपर (तेलगी)	1992-2002	20 हज़ार करोड़
सत्यम	2009	14 हज़ार करोड़
बोफोर्स	1987	16 मिलियन डॉलर
चारा घोटाला	1996	900 करोड़
हवाला	1996	18 मिलियन डॉलर
आईपीएल	2009	6000 करोड़ की लीग है और हर फिक्स्ड मैच पर सट्टेबाजी होती थी.
स्टॉक मार्केट घोटाला		
(हर्षद मेहता)	1992	4 हज़ार करोड़
(केतन पारीख)	1999-2001	1 हज़ार करोड़

यह भ्रष्टाचार की मुख़ालफ़त का नतीजा है

भ्रष्टाचार के ख़िलाफ़ खड़े होने और सत्ता के ज़रिए उसे उखाड़ फेंकने का संकल्प लेकर सियासी मैदान में उतरे बाबा रामदेव को बहुत मुश्किलों का सामना करना है. जब योग को पुनर्जीवित और शुद्ध आयुर्वेदिक दवाओं का निर्माण शुरू करने मात्र से घबरा कर लोग उनके ख़िलाफ़ किस्म-किस्म की साजिशें करने लगे तो आगे क्या-क्या बिसातें बिछनी हैं, उनकी हम कल्पना कर सकते हैं. आप याद करें वामपंथी नेता वृंदा करात को. सिद्धांतों एवं ईमानदारी के लिए चर्चित और प्रचारित वामपंथियों की करतूत आप देख चुके हैं. दवा सिंडिकेट से उपकृत होकर वृंदा करात और उनके समर्थकों ने बाबा की दवा में हड्डी का चूर्ण तलाशने के अलावा क्या-क्या नहीं किया! अब ईमानदारी और नैतिकता को पुनर्जीवित करने में लगे बाबा रामदेव के साथ देश के कितने लोग हैं, इसका ताजा उदाहरण है उत्तराखंड में बाबा के ख़िलाफ़ खड़ा हो गया उत्तराखंड क्रांति दल. उक्रांद भाजपा के विरोध में था और सरकार से समर्थन वापसी का दबाव भी बना रहा था, लेकिन बाबा केभ्रष्टाचार विरोध को भाजपा का विरोध मानते हुए उक्रांद ने बाबा के ही ख़िलाफ़ वार शुरू कर दिया. उक्रांद ने पतंजलि योगपीठ को दी गई भूमि पर सवाल उठाया और ऋषिकेश के नटराज चौक पर बाबा का पुतला फूंका. भाजपा सरकार के दबाव में हरिद्वार नगरपालिका ने भी बाबा रामदेव की फार्मेसी पर निशाने लगाने शुरू कर दिए हैं. नगरपालिका की सार्वजनिक निर्माण समिति ने दिव्य फार्मेसी से निकलने वाले पानी को केमिकल युक्त बताते हुए उसकी निकासी की व्यवस्था पर आपत्ति ज़ाहिर की है. समिति ने चेतावनी दी है कि अगर इस संबंध में शीघ्र ही क़दम नहीं उठाया गया तो वह पूरे मामले को अदालत में ले जाएगी. सार्वजनिक निर्माण समिति केअध्यक्ष दिनेश जोशी ने दिव्य फार्मेसी केप्रबंधक को जो पत्र भेजा है, उसमें कहा गया है कि बस्ती से होकर गुजरने वाले नाले में फार्मेसी के केमिकल युक्त पानी की निकासी होने से लोगों को चर्म रोग होने की शिक़ायतें मिली हैं. इस पानी से आम केबाग में कई पेड़ भी सूख चुके हैं. देश भर की नदियों और नालों का बदनुमा हश्र लोगों को दिख नहीं रहा. दरअसल इन सारी पेशबंदियों का लब्बोलुबाव यह है कि बाबा के उग्र तेवर से भ्रष्टाचार के पेड़ सूखते नज़र आ रहे हैं, इसलिए अभी उत्तराखंड में विरोध शुरू हुआ है और शीघ्र ही देश भर में शुरू हो जाएगा. यह है भ्रष्टाचार के ख़िलाफ़ देश के लोगों के बाबा के साथ समवेत रूप से खड़े हो जाने की असलियत. बाबा की राजनीतिक यात्रा की परिणति दिख रही है...

यशबीर सिंह ने अपने पत्र में रक्षा मंत्री के सामने सबसे अहम बात रखते हुए लिखा है कि उक्त इमारत रक्षा प्रतिष्ठान के 300 मीटर के दायरे के भीतर बनाई गई है.

आदर्श घोटाले पर रक्षा मंत्री भी चुप रहे

ए के एंटनी

सभी फोटो-**प्रभात पाण्डेय**

टू-जी स्पेक्ट्रम घोटाले में प्रधानमंत्री चुप रहे, नतीजतन उन्हें सर्वोच्च अदालत को जवाब देना पड़ा. राजा को इस्तीफ़ा देना पड़ा, सो अलग. आदर्श हाउसिंग सोसाइटी मामले में भी रक्षा मंत्री ए के एंटनी सालों चुप रहे, लेकिन कोई उनसे जवाब नहीं मांग रहा. चौथी दुनिया को मिले कुछ एक्सक्लूसिव पत्रों से यह साबित होता है कि जिस तर्ज पर प्रधानमंत्री कार्यालय राजा की ग़लती छुपाता रहा, उसी तर्ज पर एंटनी ने अपने सैन्य अफ़सरों की ग़लती पर मुंह खोलना ज़रूरी नहीं समझा. जबकि एक सांसद ने महीनों पहले उन्हें इसकी जानकारी दे दी थी. चौथी दुनिया की ख़ास पड़ताल.

- सपा सांसद यशबीर सिंह ने एंटनी को लिखा पत्र
- अगस्त में ही आदर्श घोटाले की दे दी थी सूचना
- अक्टूबर के अंत में हुआ घोटाले का खुलासा
- एंटनी ने सिर्फ़ 3 दिनों के भीतर दिया पत्र का जवाब
- 3 महीने में भी नहीं की कोई कार्रवाई
- एंटनी बोले, आई एम शॉक्ड. लेकिन क्यों?

शशि शेखर

आदर्श घोटाला. सुनकर अच्छा नहीं लगता. क्या कोई घोटाला भी आदर्श हो सकता है? लेकिन सेना के अधिकारियों, नेताओं एवं नौकरशाहों की मिलीभगत और रक्षा मंत्री की चुप्पी से जन्मा आदर्श नामधारी एक हाउसिंग सोसाइटी का घोटाला राजनीति में एक नया आदर्श स्थापित कर रहा है. वह आदर्श है, तब तक चुप रहो, जब तक मीडिया या अदालत अपना डंडा न चला दे. पुरानी कहावत है. एक चुप, सौ सुख. लेकिन कभी-कभी यह चुप्पी महंगी भी पड़ जाती है. इसी का एक नमूना 2-जी स्पेक्ट्रम में देखने को मिला. इस मामले में प्रधानमंत्री को अपना मुंह बंद रखने का खामियाजा भुगतना पड़ा. राजा को तो हटाया ही गया, प्रधानमंत्री को सुप्रीमकोर्ट में जवाब भी देना पड़ा. लेकिन यूपीए सरकार के मुखिया या प्रधानमंत्री कार्यालय ही नहीं, बल्कि ऐसे कई मंत्री और भी हैं, जिन पर किसी शिक़ायत या सलाह का असर नहीं पड़ता. ऐसे ही एक मंत्री है, ए के एंटनी. देश के रक्षा मंत्री और एक आदर्श नेता की छवि वाले एंटनी ने आदर्श हाउसिंग सोसाइटी घोटाले में जो चुप्पी साधी, वह तभी टूटी, जब एक-एक करके सैन्य अफसरों के नाम इस घोटाले से जुड़ते चले गए. तब उन्होंने बयान दिया कि आई एम शॉक्ड.

लेकिन, ***चौथी दुनिया*** के पास उपलब्ध दस्तावेज (एक सांसद का पत्र) इस बात को साबित करने के लिए काफी है कि एंटनी का उक्त बयान महज़ एक छलावा था, दिखावा था. उन्हें इस पूरे घोटाले की जानकारी बहुत पहले से थी. घोटाले से जुड़े एक-एक तथ्य के बारे में उन्हें महीनों पहले से पता था. सबसे खास बात यह है कि उन्हें यह जानकारी किसी संस्था या किसी आम आदमी ने नहीं दी थी, बल्कि आदर्श हाउसिंग सोसाइटी से जुड़े हर एक घपले-घोटाले की ख़बर समाजवादी पार्टी के सांसद यशबीर सिंह ने अगस्त 2010 में ही पत्र के माध्यम से दे दी थी. यशबीर सिंह उत्तर प्रदेश के नगीना लोकसभा क्षेत्र से सांसद हैं. इस पत्र में यशवीर सिंह ने एंटनी तक आदर्श सोसाइटी से जुड़ी हर एक सूचना अगस्त में ही पहुंचा दी थी. अपने पत्र में यशबीर सिंह ने साफ-साफ लिखा है कि आदर्श को-ऑपरेटिव सोसाइटी (लि.) ने ग़ैर क़ानूनी तरीक़े से कोलाबा के आवासीय क्षेत्र नेवी नगर और रक्षा प्रतिष्ठान के आसपास इमारत का निर्माण किया है. यह योजना कारगिल युद्ध में शहीद हुए लोगों के परिवार वालों के लिए बनाई गई थी. यशबीर सिंह ने अपने पत्र में इस बात का भी जिक्र किया है कि योजना में 80 फ़ीसदी असैनिक नागरिकों को फ्लैट आवंटित किए गए हैं. यशबीर सिंह ने अपने पत्र की प्रति रक्षा राज्यमंत्री एम एम पल्लम राजू और वेस्टर्न नेवल कमांड के एफओसी-इन-चार्ज (लीगल एंड इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट) को भी भेजी थी. मजेदार बात यह है कि यशबीर सिंह के पत्र का जवाब रक्षा मंत्री ए के एंटनी और रक्षा राज्यमंत्री एम एम पल्लम राजू ने तत्काल दे दिया. 18 अगस्त को लिखे इस पत्र का जवाब ए के एंटनी 21 अगस्त को ही दे दिया. एम एम पल्लम राजू ने भी 26 अगस्त को इस पत्र का जवाब दे दिया. पत्र का जवाब जिस त्वरित गति से दिया गया, उससे तो एक बार यशबीर सिंह को भी लगा होगा कि उनके द्वारा पत्र लिखे जाने का कोई ठोस असर ज़रूर होगा. मंत्रीद्वय की तरफ़ से इस मामले की तुरंत जांच कराई जाएगी, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ. अब ज़रा इस बात पर भी ग़ौर करना चाहिए कि आख़िर मंत्रीद्वय ने अपने जवाब में लिखा क्या? ए के एंटनी अपने जवाब में यशबीर सिंह को सूचित करते हैं कि मुझे आपका पत्र मिला और मैं इस मामले को देख रहा हूं. यही जवाब एम एम पल्लम राजू का भी आता है. ग़ौर करने की बात है कि वेस्टर्न कमांड के एफओसी-इन-चार्ज (लीगल एंड इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट) की तरफ़ से कोई जवाब यशबीर सिंह को नहीं मिलता.

एम एम पल्लम राजू

यशबीर सिंह के पत्र का जवाब रक्षा मंत्री ए के एंटनी और रक्षा राज्यमंत्री एम एम पल्लम राजू ने तत्काल दे दिया. 18 अगस्त को लिखे इस पत्र का जवाब ए के एंटनी 21 अगस्त को ही दे दिया. एम एम पल्लम राजू ने भी 26 अगस्त को इस पत्र का जवाब दे दिया. लेकिन कार्रवाई के नाम पर कुछ नहीं हुआ.

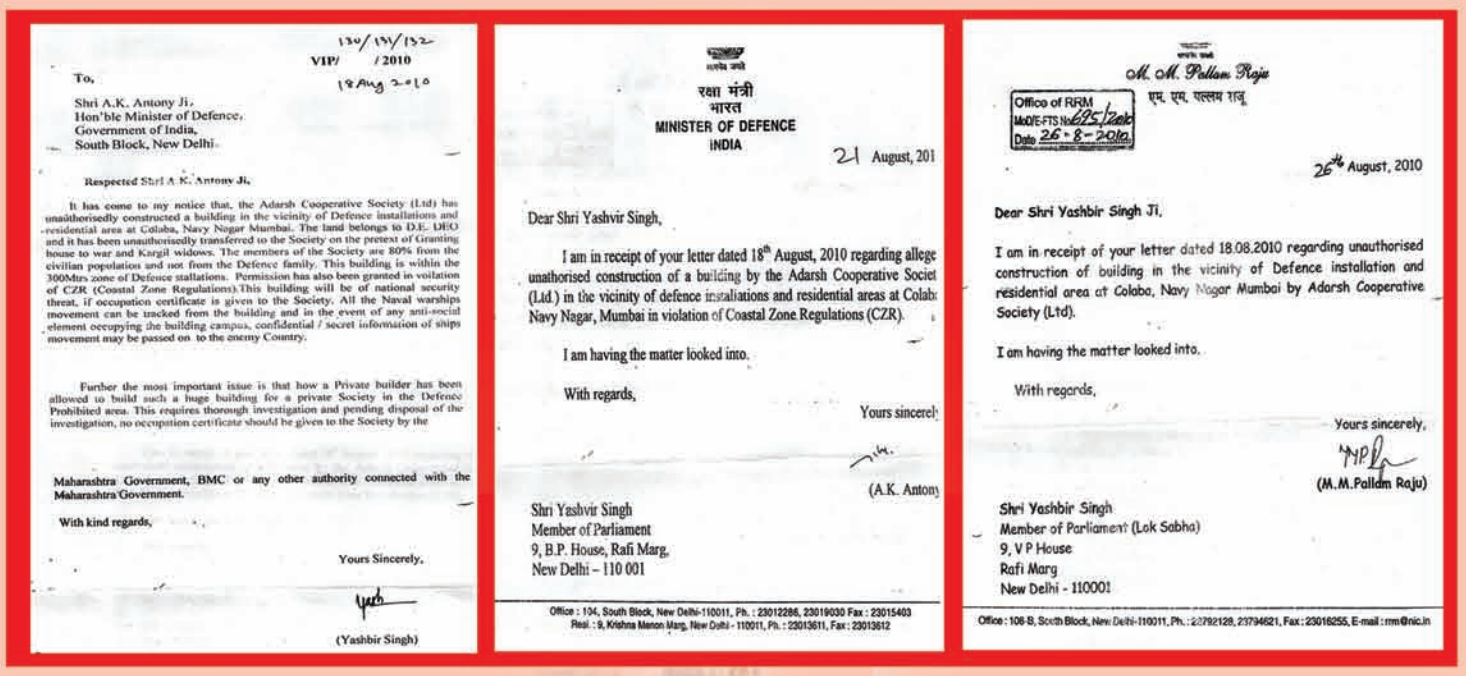

130/131/132
VIP/ /2010
18 Aug 2010

To,

Shri A.K. Antony Ji,
Hon'ble Minister of Defence,
Government of India,
South Block, New Delhi.

Respected Shri A.K. Antony Ji,

It has come to my notice that, the Adarsh Cooperative Society (Ltd) has unauthorisedly constructed a building in the vicinity of Defence installations and residential area at Colaba, Navy Nagar Mumbai. The land belongs to D.E. DEO and it has been unauthorisedly transferred to the Society on the pretext of Granting house to war and Kargil widows. The members of the Society are 80% from the civilian population and not from the Defence family. This building is within the 300Mtrs zone of Defence stallations. Permission has also been granted in voilation of CZR (Coastal Zone Regulations).This building will be of national security threat, if occupation certificate is given to the Society. All the Naval warships movement can be tracked from the building and in the event of any anti-social element occupying the building campus, confidential / secret information of ships movement may be passed on to the enemy Country.

Further the most important issue is that how a Private builder has been allowed to build such a huge building for a private Society in the Defence Prohibited area. This requires thorough investigation and pending disposal of the investigation, no occupation certificate should be given to the Society by the

Maharashtra Government, BMC or any other authority connected with the Maharashtra Government.

With kind regards,

Yours Sincerely,

(Yashbir Singh)

रक्षा मंत्री
भारत
MINISTER OF DEFENCE
INDIA

21 August, 201

Dear Shri Yashvir Singh,

I am in receipt of your letter dated 18th August, 2010 regarding allege unathorised construction of a building by the Adarsh Cooperative Societ (Ltd.) in the vicinity of defence installations and residential areas at Colab Navy Nagar, Mumbai in violation of Coastal Zone Regulations (CZR).

I am having the matter looked into.

With regards,

Yours sincerel

(A.K. Antony

Shri Yashvir Singh
Member of Parliament
9, B.P. House, Rafi Marg,
New Delhi – 110 001

Office : 104, South Block, New Delhi-110011, Ph. : 23012286, 23019030 Fax : 23015403
Resi. : 9, Krishna Menon Marg, New Delhi - 110011, Ph. : 23013611, Fax : 23013612

M. M. Pallam Raju
एम. एम. पल्लम राजू

Office of RRM
MoD/E-FTS No 695/2010
Date 26-8-2010

26th August, 2010

Dear Shri Yashbir Singh Ji,

I am in receipt of your letter dated 18.08.2010 regarding unauthorised construction of building in the vicinity of Defence installation and residential area at Colaba, Navy Nagar Mumbai by Adarsh Cooperative Society (Ltd).

I am having the matter looked into.

With regards,

Yours sincerely,

(M.M.Pallam Raju)

Shri Yashbir Singh
Member of Parliament (Lok Sabha)
9, V P House
Rafi Marg
New Delhi - 110001

Office : 106-B, South Block, New Delhi-110011, Ph. : 23792129, 23794621, Fax : 23016255, E-mail : rrm@nic.in

यशबीर सिंह ने अपने पत्र में रक्षा मंत्री के सामने सबसे अहम बात रखते हुए लिखा है कि उक्त इमारत रक्षा प्रतिष्ठान के 300 मीटर के दायरे के भीतर बनाई गई है. यशबीर सिंह यह भी लिखते हैं कि उक्त इमारत राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए एक बड़ा ख़तरा साबित हो सकती है, क्योंकि इतनी ऊंची इमारत से कोई भी असामाजिक तत्व रक्षा प्रतिष्ठानों में चल रही हर एक गतिविधि और नेवल वारशिप मूवमेंट पर नज़र रख सकता है और इससे जुड़ी गुप्त सूचनाएं शत्रु देश को पहुंचा सकता है. यशबीर सिंह मंत्रीद्वय से यह आग्रह करते हैं कि तत्काल इस बात की जांच कराई जाए कि किसके आदेश पर एक निजी बिल्डर ने रक्षा प्रतिष्ठान के नज़दीक और आम लोगों के लिए निषिद्ध क्षेत्र में इतनी ऊंची इमारत बना दी.

लेकिन एक सांसद की शिक़ायत पर भी रक्षा मंत्री ने कोई कार्रवाई करने या जांच के आदेश देने की ज़रूरत नहीं समझी. अगस्त में की गई शिक़ायत के बाद जब अक्टूबर के अंतिम दिनों में आदर्श नाम का घोटाला बोतल से बाहर निकला, तब रक्षा मंत्री नींद से जागे और उन्हें पता चला कि जनरल दीपक कपूर और जनरल एन सी विज के अलावा पूर्व नौसेना प्रमुख एडमिरल माधवेंद्र सिंह के नाम पर सोसाइटी में नियम-क़ानूनों की अनदेखी करते हुए फ्लैट आवंटित किए गए. जबकि इसमें कारगिल युद्ध के शहीदों के परिवारों को फ्लैट देने का प्रावधान करने का वादा किया गया था. खुलासे के बाद इन अफसरों ने कहा है कि उन्होंने अपने फ्लैट वापस कर दिए हैं. इस तरह जब एंटनी के अपने ही पूर्व सैन्य अफसरों की पोल खुलनी शुरू हुई तो बयान आया कि आई एम शॉक्ड. यह कैसा शॉक था? क्या एंटनी को इस सब की जानकारी नहीं थी? या सब कुछ जानते हुए भी वह अपने प्रधानमंत्री की राह पर चल रहे थे. यानी सत्ता का मज़ा लेना है तो चुप रहो. यहां तक कि सरकार आदर्श आवासीय सोसाइटी घोटाला मामले की जांच के लिए (जेपीसी) के गठन की विपक्ष की मांग पर भी ध्यान देने से कतरा रही है. सवाल यह है कि प्रधानमंत्री की चुप्पी पर तो सुप्रीमकोर्ट ने जवाब मांग लिया, लेकिन ए के एंटनी की चुप्पी का हिसाब कौन मांगेगा?

shashishekhar@chauthiduniya.com

इस जांच का क्या होगा?

मीडिया में ख़बर आने के बाद रक्षा मंत्री ए के एंटनी ने आदर्श मामले में सशस्त्र बलों और डिफेंस अधिकारियों की जवाबदेही की जांच करने के लिए सीबीआई जांच का आदेश दिया. यह आदेश उन स्थितियों की जांच के लिए था, जिनकी वजह से सेना की ज़मीन पर 31 मंजिला इमारत बनाने का अनापत्ति प्रमाणपत्र जारी किया गया. लेकिन इस जांच का अर्थ क्या है? इसकी गंभीरता क्या है? यह इस बात से पता चल जाता है कि आदर्श को-ऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी से जुड़े महत्वपूर्ण दस्तावेज गुम हो गए हैं. सोसाइटी कार्यालय की फाइलों से उक्त महत्वपूर्ण दस्तावेज लापता हैं. उक्त दस्तावेज सीबीआई को जांच के लिए सौंपे जाने थे. इन दस्तावेजों में कुछ महत्वपूर्ण लोगों के हस्ताक्षर थे, जो योजना को स्वीकृति देने के लिए किए गए थे. ज़ाहिर है, दस्तावेज गुम हुए हैं या गुम कराए गए हैं, इसका अंदाज़ा लगा पाना कोई बहुत मुश्किल काम नहीं है. दस्तावेज गुम होने की घटना से यह भी साफ होता है कि इस घोटाले के तार कहां से कहां जुड़े हो सकते हैं. मतलब यह कि इसके पीछे इतने ताक़तवर लोग हैं, जो सरकारी दस्तावेज ग़ायब करा सकने की हैसियत रखते हैं. लेकिन एंटनी जी, देश की जनता हर सवाल आपसे ही पूछेगी, अफसरों से नहीं.

विश्वनाथ प्रताप सिंह ने मंडल आयोग की सिफ़ारिशें जिस मक़सद से लागू कीं, क्या वह पूरा हो सका, पिछड़े वर्ग में राजनीतिक चेतना आई, उनका आर्थिक स्तर कितना सुधर सका?

फ़क़ीर की याद में तक़दीर की तलाश

पूर्व प्रधानमंत्री विश्वनाथ प्रताप सिंह को गुजरे दो बरस हो गए. उनकी पुण्यतिथि चुपके से गुजर गई. कोई बड़ा आयोजन नहीं हुआ. पिछड़े वर्ग के हिमायती बनने वाले तमाम संगठनों को भी उनकी याद नहीं आई. पिछड़ों की राजनीति के दम पर मुख्यमंत्री बनने वाले नेता भी उन्हें भूल गए. उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में एक कार्यक्रम हुआ, जो पूरी तरह ग़ैर राजनीतिक था. इस आयोजन के ज़रिए कुछ सवाल उठे, जो आज के दौर में भी मौजूद हैं. मसलन विश्वनाथ प्रताप सिंह ने मंडल आयोग की सिफ़ारिशें जिस मक़सद से लागू कीं, क्या वह पूरा हो सका, पिछड़े वर्ग में राजनीतिक चेतना आई, उनका आर्थिक स्तर कितना सुधर सका? सामाजिक और शैक्षिक स्तर पर पिछड़े कितने अगड़े हुए? अकलियतों के विकास के लिए वीपी सिंह ने जो प्रयास किए, वे आज के संदर्भ में कितने सफल दिखाई देते हैं? इन सवालों के घेरे में पिछड़े और अल्पसंख्यकों, ख़ास तौर पर मुस्लिम समाज के वे तमाम नेता आते हैं, जिन्होंने ख़ुद को इनका रहनुमा घोषित कर रखा है. भ्रष्टाचार के ख़िलाफ़ वीपी सिंह ने ही पहली बार आवाज़ बुलंद की, लेकिन आज प्रधानमंत्री कार्यालय तक सवालों के घेरे में है. कॉमनवेल्थ गेम्स में हुए भ्रष्टाचार से देश शर्मसार है, वहीं बैंकों से लोन दिलाने में घपलेबाज़ी को मामूली बात कहकर पल्ला झाड़ने की कोशिशें हो रही हैं.

जननायक विश्वनाथ प्रताप सिंह मेमोरियल सोसाइटी की तरफ़ से लखनऊ के अंबेडकर महासभा परिसर में 27 नवंबर को आयोजित स्मृति सभा में प्रमुख वक्ताओं ने अपने जो विचार रखे, यह उसका लब्बोलुबाव है. पूर्व प्रधानमंत्री को श्रद्धांजलि देने के लिए आयोजित इस ग़ैर सरकारी कार्यक्रम में ख़ास तौर पर चौथी दुनिया के प्रधान संपादक संतोष भारतीय दिल्ली से लखनऊ आए. इसके अलावा उर्दू–अरबी–फारसी विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर अनीस अंसारी और वीपी सिंह के अंतरंग रहे राजनीतिज्ञ एवं समाजसेवी अशोक सिंह मुख्य वक्ताओं में शामिल थे.

संतोष भारतीय वीपी सिंह के कार्यकाल में फर्रुखाबाद से चुनाव जीतकर संसद पहुंचे थे. भारतीय ने वीपी सिंह के सिद्धांतों और प्रतिबद्धताओं का उल्लेख किया और कहा कि उनका पूरा जीवन हाशिए पर रहने वाले लोगों के लिए संघर्ष करने की गाथा है. शायद देश में पहली बार संतोष भारतीय ने ही वीपी सिंह की किडनी फेल होने की अंतर्कथा उजागर की. संतोष भारतीय ने कहा कि बाबरी मस्जिद विध्वंस के बाद मुंबई में दंगा फैलने पर धार्मिक उन्माद से दुखी वीपी सिंह आमरण अनशन पर बैठ गए, हफ्ते भर उन्होंने पानी तक नहीं पिया और जब सरकार ने उन्हें जबरन गिरफ़्तार कर लिया और अस्पताल में भर्ती कराया, तब तक उनकी किडनी फेल हो चुकी थी. हर दूसरे दिन डायलिसिस पर रहने की पीड़ा झेलने के बावजूद वीपी सिंह किसानों, ग़रीबों और अल्पसंख्यकों के लिए लगातार संघर्ष करते रहे. इसके बाद का जीवन उन्होंने काफ़ी कष्ट सहकर व्यतीत किया, लेकिन ग़रीबों की लड़ाई वह मौत के दो दिन पहले तक लड़ते रहे. यहां तक कि उनकी मौत भी किसानों की पीड़ा अभिव्यक्त करते हुए ही हुई. वीपी सिंह के नज़रिए से देखें तो बिहार चुनाव उम्मीद की एक किरण है. बिहार में वीपी सिंह का सपना पूरा होता नज़र आता है. इसके नतीजे बताते हैं कि विकास, इज़्ज़त और आर्थिक समृद्धि में हिस्सेदारी की चाहत नीचे तक पहुंचने लगी है. अब ज़रूरत बस मुल्क के खामोश तबके तक उसके हितों की बात पहुंचाने भर की है.

उर्दू–अरबी–फारसी विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर अनीस अंसारी ने देश की सियासत में पिछड़ों के लिए 27 प्रतिशत आरक्षण की आवाज़ बुलंद की. उनका कहना था कि जिस तरह दलितों के लिए विधानसभा और लोकसभा की सीटों में आरक्षण का प्रावधान है, ठीक उसी तरह पिछड़ों को भी उनकी आबादी के हिसाब से सीटें दी जाएं. अनीस अंसारी राजनीतिज्ञ नहीं हैं, वह प्रदेश के वरिष्ठ नौकरशाह भी रहे हैं.

जननायक वीपी सिंह मेमोरियल सोसाइटी की तरफ़ से लखनऊ के अंबेडकर महासभा परिसर में आयोजित स्मृति सभा में (बाएं से) अशोक कुमार सिंह, अब्दुल नसीर नासिर, संतोष भारतीय, अनीस अंसारी और रीना मौर्या. फोटो: प्रीति सोनकर

उर्दू-अरबी-फारसी विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर अनीस अंसारी ने देश की सियासत में पिछड़ों के लिए 27 प्रतिशत आरक्षण की आवाज़ बुलंद की. उनका कहना था कि जिस तरह दलितों के लिए विधानसभा और लोकसभा की सीटों में आरक्षण का प्रावधान है, ठीक उसी तरह पिछड़ों को भी उनकी आबादी के हिसाब से सीटें दी जाएं. अनीस अंसारी राजनीतिज्ञ नहीं हैं, वह प्रदेश के वरिष्ठ नौकरशाह भी रहे हैं. अंसारी साफ़ कहते हैं कि संविधान में पहले यह कहीं नहीं लिखा था कि हिंदुओं में जो दलित या पिछड़े हैं, केवल उन्हें ही आरक्षण का लाभ मिले.

अंसारी साफ़ कहते हैं कि संविधान में पहले यह कहीं नहीं लिखा था कि हिंदुओं में जो दलित या पिछड़े हैं, केवल उन्हें ही आरक्षण का लाभ मिले. यह व्यवस्था राजनीतिक लाभ और मुसलमानों को पीछे धकेलने के इरादे से बाद में की गई, जो मजहब के नाम पर ग़रीब तबके को बांटने की साजिश है. उन्होंने पिछड़ों के लिए सियासी आरक्षण के साथ ही मुसलमानों और ईसाइयों में दलितों को भी आरक्षण का लाभ देने की वकालत की. वीपी सिंह की राजनीतिक यात्रा में उनके साथ रहे वरिष्ठ राजनीतिज्ञ एवं राजद के उत्तर प्रदेश अध्यक्ष अशोक कुमार सिंह ने कहा कि विश्वनाथ प्रताप सिंह को पिछड़ों के आरक्षण के दायरे में संकुचित करके देखने की नहीं, बल्कि जातिविहीन, सांप्रदायिकताविहीन समाज के उनके प्रयासों को व्यापक सिद्धांतों के दायरे में रखकर समझने की ज़रूरत है. वीपी सिंह के विशाल व्यक्तित्व को पिछड़ों के दायरे में रखना छोटापन होगा. वह हमेशा जातिविहीन समाज का सपना देखते थे, लिहाज़ा हमें जातिवादी प्रलोभनों के बजाय वृहत्तर मानसिकता से काम करना चाहिए, यही उनके प्रति सच्ची श्रद्धांजलि होगी. कई अन्य वक्ताओं ने अपने संस्मरणों में कहा कि वीपी सिंह ने ही चुनाव से लेकर सियासत तक में व्याप्त भ्रष्टाचार को मुद्दा बनाया. पिछड़े वर्ग की तमाम जातियों के लिए मंडल आयोग की सिफ़ारिशें लागू कराकर उन्हें सरकारी नौकरियों, शैक्षिक संस्थानों में अवसर उपलब्ध कराए. वीपी सिंह के इन क़दमों से देश में पिछड़ों–दलितों की राजनीति का दौर शुरू हुआ. इसके बलबूते ही उत्तर प्रदेश में मुलायम सिंह यादव, कल्याण सिंह और मायावती को मुख्यमंत्री बनने का मौक़ा मिला तो बिहार की राजनीति में लालू यादव, नीतीश कुमार, शरद यादव चमके. फिर भी सरकारी नौकरियों में हज़ारों की संख्या में आरक्षित पद रिक्त हैं.

उत्तर प्रदेश की बात करें तो यहां की मौजूदा मुख्यमंत्री मायावती ने ज़रूर अभियान चलाकर इन पदों को भरने की कोशिश की, लेकिन उनका यह प्रयास एक जाति विशेष तक ही सिमट कर रह गया. यही हाल मुलायम सिंह का रहा. उनके समय में भी यादवों को ही पिछड़ा माना गया तो कल्याण सिंह के जमाने में लोधी और कुर्मी. इस दौड़ में अति पिछड़े गुम हो गए, जिन्हें केवल वोट लेने के लिए ही पिछड़ों में गिना जाता रहा है. वीपी सिंह ने अति पिछड़े समाज के विकास की जिस परिकल्पना के साथ मंडल आयोग और सामाजिक न्याय का ताना–बाना बुना था, वह पिछड़ों के अगड़ों ने हाईजैक कर लिया. इस हक़ीक़त को भांपकर ही बिहार में नीतीश कुमार ने अति पिछड़ी जातियों के लिए अलग से आरक्षण की व्यवस्था की, इसका मीठा फल भी उन्हें बिहार विधानसभा चुनाव में मिला. जननायक वीपी सिंह मेमोरियल सोसाइटी के अध्यक्ष अब्दुल नसीर नासिर ने यह मसला भी उठाया कि वीपी सिंह अगर स्वास्थ्यगत कारणों से सक्रिय राजनीति से अलग न होते तो शायद दलितों की तरह पिछड़ों के लिए संसद और विधानसभाओं में सीटों के आरक्षण का लाभ मिल जाता. महिला आरक्षण के मसले पर संसद ठप्प कर देने वाली यादव तिकड़ी मुलायम, लालू और शरद ने पिछड़ों के लिए इस सियासी आरक्षण की मांग को पूरा कराने की ईमानदार कोशिश कभी नहीं की. बात सिर्फ़ सियासी आरक्षण या भ्रष्टाचार के मसले तक ही सीमित नहीं रही, वीपी सिंह के व्यक्तित्व के तमाम अनछुए पहलुओं पर भी विस्तार से चर्चा हुई.

चौथी दुनिया ब्यूरो
feedback@chauthiduniya.com

सरकार की तरफ़ से तय समय पर निश्चित बैठकें तो होती ही हैं, इसके अलावा जब भी कभी पूरे गांव का कोई मसला होता है तो ग्रामसभा की बैठक बुलाई जाती है

गोपालपुरा

- यहां की पंचायत पूरे गांव को साथ लेकर फ़ैसले लेती है.
- पंचायत रजिस्टर पर कोई भी अपनी शिक़ायत लिख सकता है.
- गांव की गायों के चारे की व्यवस्था भी पंचायत करती है.

सामूहिक निर्णय प्रक्रिया से बदली तस्वीर

हमारे गांव में हम ही सरकार हैं. अपने विकास के लिए पैसा तो हम सरकार से ही लेंगे, लेकिन इन पैसों का इस्तेमाल कहां और कैसे करना है, यह हम ख़ुद तय करेंगे. यानी गांव के लोग ख़ुद तय करेंगे कि विकास कैसे और कहां किया जाना है. राजस्थान के चुरू ज़िले की गोपालपुरा पंचायत की पूर्व सरपंच जब यह बात कहती हैं तो सहसा गांधी का ग्राम स्वराज याद आता है. ऐसा आभास होता है कि गांधी का सपना इस गांव में मूर्त रूप ले रहा है. इस पंचायत ने एक मत से सामूहिक निर्णय लेने की जिस प्रक्रिया का विकास किया है, वह अद्‌भुत है. यहां की सफलता देश की बाक़ी पंचायतों को आईना दिखाती है. एक संदेश देती है कि आम आदमी की ताक़त के आगे सारी ताक़तें बौनी हैं.

राज्य कभी नहीं चाहता कि समाज एकजुट, मज़बूत और आर्थिक रूप से संपन्न हो. वह हमेशा चाहता है कि समाज बंटा रहे, टूटा रहे, इस पर आश्रित रहे और गुलाम मानसिकता में जीना सीख ले. यहां तक कि गुलामी के दिनों में भी समाज के मामलों में राज्य का इतना हस्तक्षेप नहीं था, जितना स्वतंत्रता के बाद लोकतांत्रिक भारत में बढ़ता चला गया. अब तो समाज व्यवस्था को छिन्न-भिन्न कर दिया गया है और राज्य ही समाज का स्थान लेता हुआ दिख रहा है. इसका समाधान इस रूप में देखा गया कि लोकतंत्र को लोक स्वराज की तरफ़ मोड़ा जाए. मसलन गांवों में लोक स्वराज का प्रयोग किया जाए. लोक और तंत्र के बीच की दूरी को कम किया जाए. संविधान द्वारा तंत्र संरक्षक की भूमिका में स्थापित है, जबकि इसे प्रबंधक की भूमिका में होना चाहिए था. लोक और तंत्र के बीच बढ़ती हुई इसी दूरी को कम करने का काम देश के कुछ हिस्सों में चल रहा है. ऐसा ही एक गांव है गोपालपुरा. राजस्थान के चुरू ज़िले के सुजानगढ़ के रेगिस्तान में गोपालपुरा गांव विकास की नई कहानी लिख रहा है. 2005 में हुए पंचायत चुनाव में गोपालपुरा पंचायत के तहत आने वाले तीन मजरों- गोपालपुरा, सुरवास एवं डूंगर घाटी के लोगों ने सविता राठी को सरपंच चुना. वकालत की पढ़ाई कर चुकीं सविता राठी ने लोगों के साथ मिलकर गांव के विकास का नारा दिया था. सरपंच बनने के बाद सविता ने सबसे पहला काम ग्रामसभा की नियमित बैठकें बुलाने का किया. एक पिछड़े और ग़रीब गांव के विकास के लिए पांच साल कोई बहुत लंबा समय नहीं होता, लेकिन ग्रामसभा की बैठकें होने से गांव के लोगों में विश्वास जागा कि उनके गांव की स्थिति भी बेहतर हो सकती है. गांव में अब हर तरफ़ सफाई रहने लगी है. विकास के काम का पैसा गांव के विकास में लग रहा है. ग़रीबों के लिए बनी योजनाओं का लाभ उन लोगों तक पहुंचने लगा है, जो सबसे ग़रीब हैं. दीवारों पर शिक्षा और पानी को लेकर नारे हर तरफ़ दिखते हैं, जो ख़ुद गांव वालों ने लिखे हैं, वह भी बेहद सरल भाषा में. जैसे पानी बचाने के लिए लिखा है, जल नहीं तो कल नहीं. गोपालपुरा पंचायत का नाम आज देश भर में इसलिए जाना जाता है कि वहां की सरपंच सबको साथ लेकर फ़ैसले लेती हैं.

पंचायतों को टाइड फंड नहीं मिलना चाहिए, अनटाइट फंड मिलना चाहिए. हर जगह की अलग-अलग परिस्थिति होती है और हर गांव में अलग-अलग तरह के जीवनयापन के साधन होते हैं तो योजनाएं भी वहीं के लोग बनाएं. पंचायतों में योजनाएं बनें और सरकार यह सुनिश्चित करे कि सारे फ़ैसले ग्रामसभा की बैठकों में हों.

–सविता राठी, *पूर्व सरपंच, गोपालपुरा*

तीन गांवों को मिलाकर यह पंचायत बनी. गोपालपुरा, सुरवास और डूंगर घाटी. गोपालपुरा में क़रीब 800 परिवार हैं. सुरवास में 150 और डूंगर घाटी अलग गांव नहीं है, अलग से बस्ती है और इसमें भी 150 परिवार हैं. कुल मिलाकर 6000 की आबादी. ज़्यादातर लोग पिछड़ी जातियों से हैं. यहां पंचायत का हर काम ग्रामसभा की खुली बैठक में तय होता है. ग्रामसभा में फ़ैसले होने के चलते लोग ऐसे-ऐसे फ़ैसले भी मान लेते हैं, जो सामान्यत: अगर अफसरों या नेताओं द्वारा लिए जाएं तो कभी न माने जाएं. इसमें सबसे अहम रहा पानी बेचने का फ़ैसला. सरपंच के साथ गांव वालों ने लगकर पानी की कमी पूरी की. पानी के स्रोत ठीक किए गए. तालाबों में पानी बढ़ गया. ज़मीन के नीचे का पानी भी ऊपर उठ आया. इसके बाद पानी का व्यापार शुरू हो गया. राजस्थान में पानी की कमी रहती है. कुछ लोगों ने गांव के तालाबों का पानी टैंकरों में बाहर ले जाकर बेचने का धंधा शुरू कर दिया. इसमें गांव के भी कुछ लोग शामिल थे, लेकिन ग्रामसभा में जब यह मुद्दा उठा तो तय हुआ कि बड़ी मुश्किल से पानी का स्तर ऊपर आया है और गांव का पानी इस तरह बेचा नहीं जाना चाहिए. ग्रामसभा में निर्णय लेकर तालाबों के चारों तरफ़ चहारदीवारी बनवाई गई और गेट लगाकर ताले जड़ दिए गए. अब गांव में टैंकर से कोई पानी नहीं उठाता.

तीन गांवों को मिलाकर यह पंचायत बनी. गोपालपुरा, सुरवास और डूंगर घाटी. गोपालपुरा में करीब 800 परिवार हैं. सुरवास में 150 और डूंगर घाटी अलग गांव नहीं है, अलग से बस्ती है और इसमें भी 150 परिवार हैं. कुल मिलाकर 6000 की आबादी. ज़्यादातर लोग पिछड़ी जातियों से हैं. यहां पंचायत का हर काम ग्रामसभा की खुली बैठक में तय होता है.

गांव में आपस में ख़ूब झगड़े थे. आएदिन लोग एक-दूसरे के ख़िलाफ़ एफआईआर कराते रहते थे. महीने में एक-दो मामले दर्ज होना सामान्य बात थी. धीरे-धीरे जब ग्रामसभा की बैठकें होने लगीं तो यह मुद्दा भी उठा और आश्चर्यजनक रूप से लोगों के मतभेद कम होते चले गए. गांव में लोग कचरा इधर-उधर फैलाते थे. निर्मल ग्राम योजना का भी कोई फ़ायदा नहीं हो रहा था. तब ग्रामसभा की बैठक में स्वच्छता की ज़रूरत पर भी चर्चा हुई और सब लोगों ने मिलकर कचरा निस्तारण की व्यवस्था की. गांव में राशन की चोरी बंद हो गई है. पटवारी, आशा बहनों एवं आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं आदि सबका ग्रामसभा की बैठक में आना ज़रूरी है. पंचायत भवन में एक रजिस्टर रखा है. अगर किसी को कोई शिक़ायत होती है तो वह उसे इस पर लिख जाता है. पंचायत इस पर कार्रवाई करती है. ज़रूरत पड़ने पर अगली बैठक में भी इस पर चर्चा होती है. गांव में गाय फ़सल न चर जाएं, इसलिए फ़सल के दौरान साझा गौचर का काम चलाया जाता है और खेती की रक्षा होती है. इसके लिए किसानों से 5 रुपये से 7 रुपये प्रति बीघा लिया जाता है, जिससे गांव की गायों के चारे की व्यवस्था की जाती है.

सरकार की तरफ़ से तय समय पर निश्चित बैठकें तो होती ही हैं, इसके अलावा जब भी कभी पूरे गांव का कोई मसला होता है तो ग्रामसभा की बैठक बुलाई जाती है और उस मसले को हल किया जाता है. औसतन महीने में एक बैठक ग्रामसभा की होती ही है और हर बैठक में लगभग 100-200 लोग आते हैं. शुरू में तो प्रभावशाली और दलाल किस्म के लोग सोचते थे कि महिला सरपंच काम नहीं कर पाएगी, लेकिन जब सविता राठी ने अपना काम शुरू किया, तब लोगों की यह सोच ख़त्म हो गई और आम जनता में विश्वास कायम हुआ ग्रामसभा की बैठकों द्वारा. जनता को लगा कि सविता वाकई हमारे लिए कुछ करेंगी, क्योंकि पंचायत की बैठकों में केवल पंच नहीं, पूरा गांव इकट्ठा होता है, जहां लोगों की समस्याएं सुनकर उनका निस्तारण किया जाने लगा. इससे विश्वास जमा. जब सविता राठी ने कार्यभार संभाला तो पंचायत भवन में कुछ नहीं था. इसके बाद पंचायत घर खुलवाया गया और वहां बैठके शुरू हुईं. लोगों को विश्वास दिलाया गया कि अगर वे आएंगे तो उनकी बात ज़रूर सुनी जाएगी और काम भी होगा. जब विश्वास जमा तो लोग आने शुरू हुए. अगर कोई ऐसा मसला आया भी, जिसमें विवाद उठा तो ख़ुद गांव वालों ने ही एक-दूसरे को समझाया और उसका हल निकला. ग़रीबों के लिए बनी योजनाओं का लाभ लेने के लिए ख़ूब मारामारी रहती है. हर कोई, खासकर प्रभावशाली लोग ग़रीब बनकर इन योजनाओं का लाभ लेना चाहते हैं, लेकिन इस समस्या के समाधान के लिए सबसे अच्छा ज़रिया ग्रामसभा है. ग्रामसभा में लोगों के सामने प्रभावशाली व्यक्ति यह नहीं कह सकता कि फ़ायदा मुझे मिले. पंचायत की निजी आय भी बढ़ाई गई, टैक्स वग़ैरह लगाकर. निजी आय से भी ज़रूरतमंद लोगों की सहायता की गई. दानदाताओं को भी प्रेरित किया गया. एक दानदाता ने 5 लाख रुपये दिए, ताकि ग़रीब लोगों के मकान बन सकें. सविता राठी कहती हैं कि पंचायतों को टाइड फंड नहीं मिलना चाहिए, अनटाइट फंड मिलना चाहिए. हर जगह की अलग-अलग परिस्थिति होती है और हर गांव में अलग-अलग तरह के जीवनयापन के साधन होते हैं तो योजनाएं भी वहीं के लोग बनाएं. पंचायतों में योजनाएं बनें और सरकार यह सुनिश्चित करे कि सारे फ़ैसले ग्रामसभा की बैठकों में हों. फ़िलहाल, सविता राठी की जगह नए सरपंच का चुनाव हो चुका है. ख़ुशी की बात यह है कि सविता अभी भी पंचायत के कामों में जुटी हैं और वर्तमान सरपंच को अपनी मदद देती रहती हैं. राठी ने विकास के जो मानक तय किए थे, उन्हें वर्तमान सरपंच भी अपना रहे हैं.

शशिशेखर
shashishekhar@chauthiduniya.com

बिहार में कांग्रेस की संभावनाएं तो तभी ख़त्म हो गई थीं, जब जगदीश टाइटलर को प्रभारी बनाकर भेजा गया था. पूरी चुनाव प्रक्रिया के दौरान राज्य में पार्टी का कोई ऐसा नेता नहीं दिखा, जिसकी अपनी कोई पहचान हो.

मेघनाद देसाई

नई राजनीति, पुराने नेता

एक पखवाड़े के अंदर भारतीय राजनीति में इतने झंझावात, इतने सारे उतार-चढ़ाव. ऐसा अक्सर नहीं होता, कांग्रेस पार्टी के दो-दो मुख्यमंत्रियों को एक के बाद एक अपना पद छोड़ना पड़े और संसद सप्ताहों तक लगातार बाधित होती रहे. कांग्रेस महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण के इस्तीफ़े को अपने फ़ायदे के लिए इस्तेमाल कर रही है, लेकिन आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री के रोसैय्या के साथ ऐसा क्यों हुआ? कहीं इसकी वजह यह तो नहीं कि दिवंगत मुख्यमंत्री वाई एस राजशेखर रेड्डी के बेटे जगन मोहन ने अपने न्यूज़ चैनल पर सोनिया गांधी का मखौल उड़ाया? अब यदि वह बग़ावत पर उतारू हो गए तो कांग्रेस क्या करेगी? वहीं दूसरी ओर कर्नाटक के मुख्यमंत्री बी एस येदियुरप्पा के इस्तीफ़े के मामले में भारतीय जनता पार्टी को अपनी हैसियत का अंदाज़ा हो गया. भाजपा के केंद्रीय नेतृत्व की तमाम कोशिशों के बावजूद येदियुरप्पा अपना पद छोड़ने को राजी नहीं हुए. भाजपा अध्यक्ष नितिन गडकरी को सुशासन के बारे में अभी काफी कुछ जानने की ज़रूरत है, साथ ही पार्टी के शीर्ष नेताओं के बीच उन्हें अपना कद भी बढ़ाना होगा. बिहार विधानसभा चुनाव में राजग गठबंधन की एकतरफा जीत ने भाजपा को चेहरा बचाने का साधन उपलब्ध करा दिया, लेकिन पार्टी यह अच्छी तरह जानती है कि इस जीत का सारा श्रेय नीतीश कुमार को जाता है. भाजपा का इसमें कोई खास योगदान नहीं है और सच तो यह है कि चुनाव प्रचार में गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी को शामिल करने के इसके प्रस्ताव को नीतीश ने सिरे से खारिज कर दिया था और अब वह इसके लिए वाहवाही लूट रहे हैं.

मोदी के प्रचार अभियान में शामिल होने से परिणामों पर क्या असर पड़ता, यह अंदाज़ा लगाना मुश्किल है, लेकिन यह स्पष्ट है कि नीतीश के सामने भाजपा की एक नहीं चली. इसमें कोई संदेह नहीं कि गुजरात में नरेंद्र मोदी ने काफी काम किया है और एक अच्छे प्रशासक की छवि बनाई है, लेकिन ख़ुद मोदी और भाजपा भी नहीं जानती कि इसके बावजूद वह एक बोझ की तरह क्यों हैं. बिहार चुनावों में मुसलमानों ने राजग गठबंधन के पक्ष में वोट ज़रूर दिया, लेकिन इसकी वजह भाजपा नहीं है. पार्टी जितनी जल्दी इसे समझ ले, उतना ही अच्छा है, अन्यथा उसे लंबे समय तक केंद्र में विपक्ष में बैठने को मजबूर होना पड़ेगा. बिहार चुनाव के लिए प्रचार अभियान जब अपने चरम पर था, तभी आरएसएस प्रमुख के एस सुदर्शन ने सोनिया गांधी पर व्यक्तिगत रूप से निशाना साधते हुए उन पर तमाम तरह की साजिशों में शामिल होने का आरोप लगा दिया. इसका सोनिया पर तो कोई असर पहीं पड़ा, हां इतना ज़रूर हुआ कि संघ के मानसिक दिवालिएपन की बात एक बार फिर सतह पर आ गई. फिर भी हमें यह जरूर मान लेना चाहिए कि बिहार में राजग की जीत यदि किसी के लिए समस्या है तो वह कांग्रेस ही है. कांग्रेस ने इन चुनावों में बड़ा जोखिम लेते हुए सभी 243 सीटों पर अपने उम्मीदवार खड़े किए थे, जबकि बाक़ी सभी प्रमुख पार्टियां अपने गठबंधन के साझीदार दलों के साथ चुनावी वैतरणी में उतरी थीं. कांग्रेस

नई राजनीति

शायद उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनावों से पहले राहुल गांधी के करिश्मे को आजमाना चाहती थी. यदि यह सही है तो बिहार चुनाव के परिणाम 2007 के विधानसभा चुनावों की तर्ज पर हैं, न कि 2009 के लोकसभा चुनावों की. राहुल गांधी का करिश्मा लोकसभा चुनावों में तो काम कर सकता है, लेकिन राज्य विधानसभा के चुनावों को प्रभावित करने की ताक़त शायद उनके पास नहीं है.

बिहार में कांग्रेस की संभावनाएं तो तभी ख़त्म हो गई थीं, जब जगदीश टाइटलर को प्रभारी बनाकर भेजा गया था. पूरी चुनाव प्रक्रिया के दौरान राज्य में पार्टी का कोई ऐसा नेता नहीं दिखा, जिसकी अपनी कोई पहचान हो. कमोबेश यही हालत गुजरात, पश्चिम बंगाल और कर्नाटक में भी है. राहुल गांधी ने पार्टी को मज़बूत बनाने के लिए ज़मीनी स्तर पर कितना काम किया है, यह अंदाज़ा लगाना अभी मुश्किल है, लेकिन इतना तय है कि अभी उनकी कोशिशों का कोई परिणाम नहीं दिख रहा. महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश के लिए नए मुख्यमंत्रियों का चुनाव जिस अलोकतांत्रिक ढंग से किया गया, उससे यह बात और भी ज़्यादा स्पष्ट हो जाती है. लेकिन जैसा कि आंध्र प्रदेश में देखने को मिल रहा है और भविष्य में महाराष्ट्र में भी देखने को मिल सकता है कि राज्य सरकारों को केंद्र की कठपुतली की तरह चलाने के दिन अब लद चुके हैं. जगन मोहन रेड्डी दोबारा पलटवार करने से नहीं चूकेंगे, क्योंकि वह भी इस बात से अच्छी तरह वाक़िफ़ हैं.

तेलंगाना रिपोर्ट से पार्टी हाईकमान को तत्काल अपनी प्रतिष्ठा बचाए रखने में कामयाबी मिल सकती है, लेकिन आने वाले दिनों में आंध्र प्रदेश में पार्टी के लिए मुश्किलें बढ़ेंगी, इसमें कोई संदेह नहीं. नीतीश की जीत ने यह दिखा दिया है कि राज्यों की राजनीति में स्थानीय मुद्दे ज़्यादा प्रभावी होते हैं, न कि राष्ट्रीय मुद्दे. इसमें कोई आश्चर्य भी नहीं होना चाहिए. अमेरिका में पहले से ही ऐसा होता रहा है और भारत जैसे विशाल गणतंत्र में भी ऐसा होना अवश्यंभावी है. भारत में केंद्रीयकृत विचारधारा का जनक इंग्लैंड को माना जाता है, लेकिन स्कॉटलैंड, वेल्स और उत्तरी आयरलैंड को देखने से यह स्पष्ट हो जाता है कि प्रांतीय और राष्ट्रीय मुद्दों के बीच का अंतर वहां भी आम हो चुका है. लेकिन भारतीय राजनीति में न तो कांग्रेस और न ही भाजपा इस नई सच्चाई को मानने के लिए तैयार है.

दोनों ही पार्टियां राज्यों को केंद्रीय स्तर से दिशा निर्देशित करने की कोशिश करती हैं और येदियुरप्पा मामले में भाजपा के केंद्रीय नेतृत्व को जिस तरह मुंह की खानी पड़ी, यह उसी का नतीजा है. नरेंद्र मोदी शायद कभी भी राष्ट्रीय राजनीति में प्रवेश न कर सकें और नीतीश कुमार इसके लिए शायद कोशिश भी न करें. डीएमके प्रमुख करुणानिधि तमिलनाडु की राजनीति में किस तरह ख़ुश हैं, यह हम देख ही रहे हैं. अच्छे शासन का सीधा संबंध स्थानीय मुद्दों से होता है, न कि राष्ट्रीय मुद्दों से. भारतीय राजनीति में भी ऐसा हो सकता है कि केंद्र में किसी पार्टी का शासन हो और राज्यों में दूसरी पार्टियों का. ऐसा भी हो सकता है कि कांग्रेस पार्टी आम चुनावों में जीतती रहे, लेकिन राज्यों के विधानसभा चुनावों में उसे बार-बार हारना पड़े. भारतीय राजनीति के इस नए चेहरे के असली नायक तो दो पुराने समाजवादी हैं, लोहिया और जेपी. उनका एकमात्र उद्देश्य कांग्रेस को कमज़ोर करना था, क्योंकि उन्हें लगता था कि पार्टी बदलाव की राह में बाधा है. उत्तर प्रदेश और बिहार जैसे राज्यों के पिछड़ेपन का सबसे बड़ा कारण दशकों तक कांग्रेस का सवर्ण आधारित शासन रहा है. इन दोनों नेताओं ने इसे महसूस किया और कांग्रेस के ख़ात्मे के लिए कमर कस ली. आज जो बदलाव हम देख रहे हैं, उसके बीज लोहिया की कांग्रेस विरोधी विचारधारा और जेपी के 1975 के आंदोलन द्वारा ही बोए गए थे. राहुल गांधी को भी इसे समझना होगा. उन्हें यह समझ लेना चाहिए कि भारत में परिस्थितियों में वास्तविक बदलाव में दशकों का समय लग जाता है, यह सालों में नहीं होता.

feedback@chauthiduniya.com

विकीलीक्स और कूटनीति

कूटनीति का कारोबार वैसे ही काफी संवेदनशील होता है और जब निजी एवं गोपनीय संवाद सार्वजनिक होने लगे तो यह और भी ज़्यादा मुश्किलें पैदा करता है. लेकिन विकीलीक्स द्वारा गोपनीय दस्तावेजों को लीक करने की ताजा घटना में जो चीज सबसे ज़्यादा ध्यान खींचती है और भरोसा भी दिलाती है, वह यह कि इसमें दस्तावेजों के साथ कोई चालबाज़ी नहीं की गई है. इससे पहले बुश प्रशासन के दौर के जो भी दस्तावेज लीक किए गए थे, उनमें सत्ता के दुरुपयोग, जैसे अपहरण एवं शारीरिक प्रताड़ना की ख़बरों पर ही ज़्यादा जोर होता था, लेकिन ओबामा प्रशासन के दौर के जो दस्तावेज लीक किए गए हैं, उन्हें देखकर लगता है कि इस दौर की कूटनीति न केवल बेहतर है, बल्कि उनके कूटनीतिक सलाहकार दक्ष भी हैं. इसका सबसे अच्छा उदाहरण ईरान मामले में देखने को मिलता है. लीक हुए दस्तावेजों से यह पता चलता है कि ईरान के परमाणु कार्यक्रम पर रोक लगाने के लिए उस पर आक्रमण करने के लिए इजरायल और अरब देशों का दबाव ओबामा प्रशासन पर था, लेकिन यह दबाव प्रशासन पर हावी नहीं हो सका. ओबामा के कूटनीतिकार ईरान पर आक्रमण से बचते रहे और उसके ख़िलाफ़ कड़े प्रतिबंधों का रास्ता चुना गया. द टाइम्स और दूसरे मीडिया संस्थानों में इस बारे में पहले ही काफी चर्चा हो चुकी है, लेकिन विकीलीक्स के नए दस्तावेजों ने इसे और रोचक बना दिया है. नए दस्तावेजों में इजरायल के रक्षा मंत्री एहुद बराक कहते हैं कि ईरान को परमाणु हथियार बनाने से रोकने के लिए बाक़ी दुनिया के पास केवल 6 से 18 महीने ही बचे हैं, सउदी अरब के सुल्तान किंग अब्दुल्ला अमेरिका से सांप का फन कुचलने की विनती करते हैं तो बहरीन के सुल्तान का कहना है कि ईरान के परमाणु कार्यक्रम का बेरोकटोक आगे बढ़ते रहना पूरी दुनिया के लिए ख़तरनाक है.

मामला ईरान से जुड़ा हो तो इजरायल शोर मचाने से कभी बाज नहीं आता, लेकिन अरब देशों के अधिकांश नेता कभी ऐसा नहीं करते. यदि उन्हें लगता है कि ईरान की ओर से कोई ख़तरा हो सकता है तो वे यह बात अपने लोगों को बताते हैं और ईरान पर दबाव बनाने के लिए जीतोड़ कोशिश करते हैं. विकीलीक्स के दस्तावेजों से यह बात भी खुलकर सामने आती है कि अमेरिका ने ईरान पर प्रतिबंध आरोपित करने के लिए किस दक्षता से पृष्ठभूमि तैयार की. चीन का समर्थन हासिल करने के लिए ओबामा प्रशासन ने सउदी अरब से तेल की आपूर्ति बनाए रखने का आश्वासन बीजिंग को दिलवाया. रूस को अपनी ओर करने के लिए उसने बुश प्रशासन के जमाने की मिसाइल डिफेंस योजना को ही बदल दिया. नई योजना की प्रभावशीलता में कोई कमी नहीं आई है, लेकिन मॉस्को को यह अपने लिए कम ख़तरनाक लगती है. हालांकि क्यूबा की गुआंटानामो खाड़ी के कैदियों से संबंधित दस्तावेजों का लीक होना ओबामा प्रशासन के लिए परेशानी का कारण ज़रूर हो सकता है. कैदियों को स्वीकार करने के लिए दूसरे देशों की सरकारों पर दबाव बनाने के लिए किस तरह के हथकंडे अपनाए गए, यह बात अब सार्वजनिक हो चुकी है. स्लोवानिया से कहा गया कि राष्ट्रपति ओबामा से मिलना है तो कैदियों को स्वीकार करना होगा. कितना अच्छा होता, यदि राष्ट्रपति कार्यालय ने जेल को बंद कराने हेतु कांग्रेस को राजी कराने के लिए भी इसी स्फूर्ति और दक्षता का सहारा लिया होता.

हमें बार-बार यह विश्वास दिलाया गया था कि वाशिंगटन पाकिस्तान पर इस बात के लिए दबाव बना रहा है कि वह अपने परमाणु रिएक्टर से ईंधन हटा ले, ताकि आतंकवादियों द्वारा इसे अपने फ़ायदे के लिए इस्तेमाल करने का ख़तरा न रहे. साथ ही यह भी कि अमेरिका और दक्षिण कोरिया उत्तर कोरिया के विघटन की आशंका के मद्देनज़र पैदा होने वाले हालात पर गंभीरतापूर्वक विचार-विमर्श कर रहे हैं. लेकिन अब जो बात सामने आ रही है, उससे यही लगता है कि उत्तर कोरिया के नए यूरेनियम संवर्धन प्रतिष्ठान के बारे में न तो वाशिंगटन जानता था, न ही सियोल. ओबामा प्रशासन जॉर्ज बुश के एक फ़ैसले को जारी रखने की नीति से भी शर्मिंदगी महसूस कर सकता है. बुश प्रशासन ने अपने अधिकारियों को यह आदेश दिया था कि वे दूसरे देशों से आने वाले अधिकारियों की व्यक्तिगत डिटेल्स, जैसे क्रेडिट कार्ड नंबर, टिकट से संबंधित जानकारियां आदि अपने पास रखें. ओबामा प्रशासन ने इस फ़ैसले में कोई बदलाव नहीं किया, लेकिन इससे कूटनीतिज्ञों और जासूसों के बीच का फ़र्क़ ख़त्म हो जाने का गंभीर ख़तरा पैदा हो सकता है और यह ऐसा काम है, जिसे जासूस ही करें तो ज़्यादा अच्छा है. कूटनीतिक संवादों को गोपनीय रखने के वैध और जायज़ कारण होते हैं. विकीलीक्स द्वारा लीक किए गए ताजा दस्तावेजों से मुश्किलें केवल इसीलिए पैदा नहीं हो सकती हैं कि इसमें दुनिया भर के नेताओं के गोपनीय और व्यक्तिगत बयान दर्ज हैं. विदेश मंत्री हिलेरी क्लिंटन जब यह कहती हैं कि इससे राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए ख़तरा पैदा हो सकता है तो यह मामले को बढ़ा-चढ़ाकर देखने की कोशिश लगती है. ये दस्तावेज महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि इनमें अमेरिका की नीतियों को उसी रूप में प्रकाशित किया गया है, जिस रूप में अमेरिकी जनता और बाक़ी लोग देखना चाहते हैं और जो उनका हक़ है.

हमें बार-बार यह विश्वास दिलाया गया था कि वाशिंगटन पाकिस्तान पर इस बात के लिए दबाव बना रहा है कि वह अपने परमाणु रिएक्टर से ईंधन हटा ले, ताकि आतंकवादियों द्वारा इसे अपने फ़ायदे के लिए इस्तेमाल करने का ख़तरा न रहे. साथ ही यह भी कि अमेरिका और दक्षिण कोरिया उत्तर कोरिया के विघटन की आशंका के मद्देनज़र पैदा होने वाले हालात पर गंभीरतापूर्वक विचार-विमर्श कर रहे हैं.

न्यूयॉर्क टाइम्स से साभार

feedback@chauthiduniya.com

राजनीति में उलझे नौकरशाह

पीएमओ के सभी अधिकारियों की संपत्ति की जांच होनी चाहिए. वहां कई ऐसे अधिकारी कार्यरत हैं, जिनके चलते भ्रष्टाचार, अराजकता और कुव्यवस्था का पूरे देश में बोलबाला है. वे सर्वोच्च न्यायालय के कामों में हस्तक्षेप और उसे भ्रष्ट लोगों के पक्ष में प्रभावित करने की कोशिश भी करते हैं.

-क्रांति, *ई-मेल से.*

बिहार में राहुल

कांग्रेस का जन्म साम्राज्यवाद से टक्कर लेने के लिए हुआ था, लेकिन ब्रिटिश साम्राज्यवाद से लड़ते-लड़ते उसकी खुद की सोच भी वैसी ही हो गई. जवाहर लाल नेहरू लोकतांत्रिक मूल्यों के समर्थक थे और संसद की कार्यप्रणाली के प्रति विश्वास रखते थे, परंतु दलीय आंतरिक लोकतंत्र और विपक्षी दलों के प्रति वह बहुत सम्मानजनक नज़रिया नहीं रखते थे. उनकी राजनीतिक वारिस इंदिरा गांधी ने संसद की गरिमा को अंतहीन क्षति पहुंचाई. तब बिहार राजनीतिक परिवर्तन का साक्षी बना. जय प्रकाश नारायण के नेतृत्व में क्रांति का प्रादुर्भाव हुआ. उसी के फलस्वरूप लालू, नीतीश, सुशील मोदी, शरद यादव, रामविलास पासवान, मुलायम सिंह यादव जैसे मध्यमार्गी समाजवादियों का राजनीतिक जन्म हुआ. इस छद्म समाजवाद के अब तक कई रूप हमारे सामने आ चुके हैं. नीतीश का दोबारा चुना जाना उसी प्रक्रिया का एक हिस्सा है. राहुल जिस तरीक़े के भारत का प्रतिनिधित्व करते हैं, वह आम भारत से अलग है. आपने लिखा कि वह भारत की बात करते हैं और मनमोहन सिंह की सरकार में बात होती है इंडिया की. मैं इसे और स्पष्ट कर दूं कि राहुल वास्तव में विपक्षहीन भारतीय राजनीति में सक्रिय-निष्क्रिय विपक्ष की भूमिका में हैं. वह केंद्र का विरोध भी करते हैं, आशाएं भी जगाते हैं, पर उन समस्याओं के हल का कोई रास्ता नहीं सुझाते. वह सारे काम एक इवेंट की तरह करते हैं. सारे काम एक मजेदार माहौल में होता है. बिसलरी से नहाने-धोने की संस्कृति वाले लोगों से बहुत बड़ी उम्मीद करना देश के साथ धोखा होगा. अभी राहुल को बहुत समय चाहिए भारत को समझने और लोगों को अपने साथ जोड़ने के लिए, जिससे राजनीति में बड़ा बदलाव लाया जा सके.

-जय कुमार झा, *ई-मेल से.*

ओबामा का भारत आगमन

22-28 नवंबर के अंक में छपा लेख-यह दोस्ती ख़तरनाक है, भारत सरकार के लिए विचारणीय है. मेरी दृष्टि में अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा भारत को एक वैश्विक शक्ति के रूप में तो देखते हैं, परंतु उससे भी कहीं अधिक इस देश को विश्व का सबसे बड़ा बाज़ार मानते हैं. यही कारण है कि अपने स्तर से उन्होंने भारत के साथ वाणिज्यिक संबंध सुधारने की दिशा में सारे प्रयास किए. भारत द्वारा अर्थव्यवस्था को उदार बनाने के नाम पर विदेशी निवेश को रिटेल जैसे क्षेत्रों में बढ़ावा देने का अर्थ होगा हज़ारों व्यापारियों के साथ-साथ लाखों फुटकर विक्रेताओं और पटरी-ठेले वालों को बेरोज़गार करना. अमेरिकी सामान भारत में बेचने के लिए बाज़ार की क़ीमत का निर्धारण आदि प्रक्रिया को पूरी तरह नियंत्रण मुक्त करने के दुष्परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं. किसानों से सीधे ख़रीद के नाम पर बहुराष्ट्रीय कंपनियों को मनमाने दोहन से हम कैसे रोक पाएंगे? सरकारी आंकड़ों में रोज़गारविहीन आर्थिक वृद्धि के लिए अमेरिका को खुदरा बिक्री के लिए स्टोर खोलने का आमंत्रण राष्ट्रहित में कतई न होगा. ओबामा ने भारत के 26/11 के बारे में दु:ख जताते हुए उसे कभी न भूल पाने की बात कही और ताज होटल में रुके भी. लेकिन अमेरिकी प्रशासन 9/11 की घटना की 9वीं बरसी मनाने के बाद भी आज तक ओसामा बिन लादेन को पकड़ नहीं सका. जबकि तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति ने उसे एक महीने के भीतर पकड़ कर सजा देने की बात कही थी. पाकिस्तान के ख़िलाफ़ पर्याप्त सबूत मिलने के बावजूद उसे आतंकवाद को प्रश्रय देने वाला देश घोषित कर दंडित करने की बात न कहकर मध्यस्थता की बात करने से स्पष्ट हो गया कि अमेरिका की नीयत कितनी साफ है. विश्वास है कि भारत के राजनेता अमेरिका के साथ वाणिज्यिक संबंधों पर तात्कालिक जनहित के बजाय दूरगामी राष्ट्रहित के बारे में सोचने के बाद ही कोई निर्णय लेंगे.

-डॉ. सुशील कुमार गुप्त, *खगड़िया, बिहार.*

दस रुपये में 27 हज़ार

बैंककर्मियों की मनमानी से परेशान हुए पेंशनर शोकहारा-बिहार निवासी 62 वर्षीय विष्णुदेव शर्मा द्वारा सूचना का अधिकार क़ानून का इस्तेमाल करने पर भारतीय स्टेट बैंक की बरौनी शाखा ने लगभग 27,397 रुपये की बकाया राशि का भुगतान कर दिया. छठवें केंद्रीय वेतन आयोग की अनुशंसाओं के आलोक में महालेखाकार द्वारा शर्मा की पेंशन का पुनरीक्षण किया गया था, जिसके काग़ज़ात 2009 में बेगूसराय कोषागार को भेजे गए थे. कोषागार ने उन्हें भुगतान के लिए भारतीय स्टेट बैंक की मुख्य शाखा बेगूसराय के पास अग्रसारित कर दिया. नियमानुसार पुन: उन काग़ज़ातों को बैंक की बरौनी शाखा में भेजा जाना था, जहां शर्मा के बचत खाते में वह राशि जमा होनी थी. बेगूसराय से बरौनी की दूरी मात्र 16 किलोमीटर है. शर्मा ने जब बरौनी शाखा से संपर्क किया तो उन्हें बताया गया कि न कोई काग़ज़ आया है और न कोई बकाया राशि. शर्मा ने पुन: बेगूसराय शाखा से संपर्क किया तो उन्हें बताया गया कि आपके काग़ज़ात बरौनी शाखा को भेजे जा चुके हैं, वहीं संपर्क करें. शर्मा फिर बरौनी शाखा पहुंचे और शाखा प्रबंधक से मिले तो उनसे कहा गया कि आपको जो मर्जी आए, करें. निराश शर्मा ने सूचना का अधिकार कानून का सहारा लिया और इसके लिए उन्होंने आरटीआई एक्टिविस्ट गिरीश प्रसाद गुप्ता से संपर्क स्थापित करके सूचना प्राप्त करने का आवेदन लोक सूचना पदाधिकारी सह महाप्रबंधक, पटना के पास भेजा. आवेदन मिलते ही वहां हड़कंप मच गया और बैंक के लोक सूचना पदाधिकारी ने संबंधित काग़ज़ात एवं राशि की खोज शुरू कर दी. नतीजा यह हुआ कि बीते 22 अक्टूबर को शर्मा जी के बचत खाते में 27,397 रुपये जमा कर दिए गए. इससे उन्होंने काफी राहत महसूस की है. यह सूचना का अधिकार क़ानून का ही चमत्कार है.

-गिरीश प्रसाद गुप्ता, *बरौनी, बिहार.*

आप अपने स्वतंत्र विचार तथा प्रतिक्रियाएं हमें इसी पते पर भेजें. संपादक, चौथी दुनिया, एफ-2, सेक्टर-11 नोएडा, (उत्तर प्रदेश) पिन-201301

ई-मेल पता : feedback@chauthiduniya.com

जब तोप मुक़ाबिल हो

सुप्रीम कोर्ट के संकेत चिंता का विषय हैं

संतोष भारतीय

देश की संसद ठप है. कौन जांच करे, पार्लियामेंट की ज्वाइंट कमेटी या पब्लिक एकाउंट्स कमेटी, यह बहस है. दोनों ने नाक का सवाल बना लिया है, पर चिंता का विषय है कि क्यों संसद के बाहर न कोई राजनेता और न राजनैतिक दल, एक लाख छिहत्तर हज़ार करोड़ के भ्रष्टाचार तथा कॉमनवेल्थ खेलों में हुए सत्तर हज़ार करोड़ के ख़र्चों में हुई गड़बड़ी को मुख्य मुद्दा नहीं बना रहे हैं.

क्या होता अगर सुप्रीम कोर्ट इस पर ध्यान नहीं देता? दोनों सवाल ख़ामोशी से राजनीति के क़ब्रिस्तान में दफ़न हो जाते. सुप्रीम कोर्ट ने कई चिंताएं जताईं, जिनमें सबसे महत्वपूर्ण है प्रधानमंत्री पद का उनके साथियों द्वारा आदर न करना. दयानिधि मारन ने संचार मंत्री रहते हुए प्रधानमंत्री को खत लिखा कि वह अपने मंत्रालय में आज़ाद हैं और उन्हें दख़ल मंजूर नहीं. जब ए राजा संचार मंत्री बने तो उन्होंने कंपनियों के चुनाव और आवंटन में प्रधानमंत्री की सलाह नहीं मानी. सरकार को घाटा एक हज़ार रुपये का लगा या एक लाख छिहत्तर हज़ार करोड़ का, यह सवाल नहीं है, सवाल है प्रधानमंत्री पद की अवमानना का. प्रधानमंत्री संविधान का पालन करने वाली मशीनरी का मुखिया होता है, उसकी राय नहीं मानी गई और प्रधानमंत्री ख़ामोश रहे. क्या मजबूरियां रही होंगी?

मनमोहन सिंह की मजबूरी शायद सरकार चलाने की रही होगी, क्योंकि अगर वह ए राजा को टोकते तो द्रमुक समर्थन वापस ले सकता था. या फिर उन्हें सोनिया गांधी ने कहा कि वह ख़ामोश रहें या फिर उनमें ही इतनी हिम्मत नहीं रही कि वह अपने पद की गरिमा बचा सकते. मैं मनमोहन सिंह जी को वीपी सिंह के प्रधानमंत्रित्व काल के अंतिम दिनों की एक घटना याद दिलाना चाहता हूं. आडवाणी जी की रथ यात्रा चल रही थी. वीपी सिंह की सरकार भी भाजपा और वामपंथियों के संयुक्त समर्थन से चल रही थी. यह साफ हो गया था कि यदि आडवाणी जी गिरफ़्तार हो जाते हैं तो भाजपा समर्थन वापस ले लेगी और वीपी सिंह की सरकार गिर जाएगी. अटल बिहारी वाजपेयी यह नहीं चाहते थे.

वह वीपी सिंह के पास गए. उनसे कहा कि पांच आदमी बाबरी मस्जिद के पास जाएंगे और केवल पांच ईंटें वहां रखकर वापस चले आएंगे. सरकार का समर्थन जारी रहेगा. वीपी सिंह ने विनम्रता से अटल जी से कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है और उस आदेश का पालन करना विश्वनाथ का नहीं, इस देश के प्रधानमंत्री का फर्ज है. अगर उस आदेश का पालन मैं नहीं करा सका तो मुझे इस पद पर बने रहने का हक नहीं है. अटल जी ने आख़िरी कोशिश की कि पर यह तो सांकेतिक होगा, इस पर वीपी सिंह ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट और संविधान के मामले में सांकेतिक कुछ नहीं होता. उन्होंने पांच ईंटें रखने की अनुमति नहीं दी, आडवाणी जी गिरफ़्तार हुए और अटल जी ने राष्ट्रपति को समर्थन वापसी का खत सौंप दिया. वीपी सिंह की सरकार गिर गई.

सरकार के मुखिया मनमोहन सिंह को चाहिए था कि वह ए राजा या उन जैसे मंत्रियों को बाहर निकाल फेंकते, उनकी कारगुजारियों को देश के सामने रखते और जनता के पास चले जाते. कांग्रेस पूरे बहुमत से वापस आती. पर इसकी जगह उन्होंने बार–बार सोनिया गांधी को अपना त्यागपत्र सौंपा. राजा के मसले पर और कॉमनवेल्थ खेलों की गड़बड़ी पर निर्णायक कार्रवाई से बचे तथा ऐसी स्थिति पैदा कर दी कि प्रधानमंत्री पद की गरिमा के बचाव में सुप्रीम कोर्ट को उतरना पड़ा. अगर ऐसी स्थिति इंदिरा गांधी, विश्वनाथ प्रताप सिंह और चंद्रशेखर के सामने आई होती तो वे इसे बर्दाश्त नहीं करते, या तो कार्रवाई करते या त्यागपत्र दे देते.

सुप्रीम कोर्ट सीवीसी के ऊपर सवाल उठाता है. सीवीसी अपने को स्पेक्ट्रम घोटाले की जांच से अलग रहने की बात करते हैं, लेकिन कहते हैं त्यागपत्र नहीं देंगे. पहली बार लोगों के विश्वास का पद संदेह के घेरे में आ गया है. इस पर फ़ैसला प्रधानमंत्री नहीं ले पा रहे हैं. कौन उन्हें रोक रहा है, क्या सोनिया गांधी या फिर डीएमके.

प्रधानमंत्री और सोनिया गांधी के बीच सब कुछ ठीक नहीं है. ओबामा के आने पर उन्होंने जो पार्टी दी, उसमें उन्होंने किसको नहीं बुलाया, बस एक आदमी को बुलाना भूल गए. अहमद पटेल को, जो सोनिया गांधी के राजनीतिक सचिव हैं. मैं नहीं जानता कि यह जानबूझ कर हुआ या ग़लती से, पर हुआ. सोनिया गांधी की विकास और समाज को लेकर तथा राहुल गांधी की इन्हीं सवालों को लेकर जो भाषा है, वह मनमोहन सिंह की भाषा से अलग है. इस अलग–अलग भाषा को लेकर भी प्रधानमंत्री और सोनिया गांधी के बीच अब तक कोई बात नहीं हुई है. बात होनी चाहिए.

सुप्रीम कोर्ट सीवीसी के ऊपर सवाल उठाता है. सीवीसी अपने को स्पेक्ट्रम घोटाले की जांच से अलग रहने की बात करते हैं, लेकिन कहते हैं त्यागपत्र नहीं देंगे. पहली बार लोगों के विश्वास का पद संदेह के घेरे में आ गया है. इस पर फ़ैसला प्रधानमंत्री नहीं ले पा रहे हैं. कौन उन्हें रोक रहा है, क्या सोनिया गांधी या फिर डीएमके.

प्रधानमंत्री सर्वोच्च कार्यकारी पद है. इस पद की गरिमा ही यह है कि देश में फैले संदेह के वातावरण को पहले तो पनपने ही न दे, और पनपे तो उसे दूर करे. प्रधानमंत्री की ख़ामोशी से भ्रष्टाचार देश में इस समय सबसे बड़ा मुद्दा बन गया है. कुछ लोग कह सकते हैं कि यह मध्यम वर्ग का मुद्दा है, ग़रीब को तो रोजी और रोटी चाहिए. पर यह सच्चाई से भागना माना जाएगा. देश के प्रधानमंत्री को भ्रष्टाचार से लड़ता दिखना चाहिए, जबकि भ्रष्टाचार से लड़ने का संकेत सुप्रीम कोर्ट दे रहा है. सुप्रीम कोर्ट के ये संकेत देश में चिंता पैदा कर रहे हैं. मानना चाहिए कि प्रधानमंत्री जी और सोनिया जी भी इससे चिंतित होंगी. क्योंकि अगर ये दोनों और आडवाणी जी चिंतित नहीं होते तो संसद को राजनीति का क़ब्रिस्तान बनने से कोई रोक नहीं पाएगा.

संपादक
editor@chauthiduniya.com

न्याय के लिए हम कहां जाएं

कांची कोहली

कुछ ही दिन पहले की बात है, जब सुबह–सुबह मेरे पास एक फोन आया. गुजरात के मुंद्रा समुद्र तट से मेरे एक मित्र ने फोन किया और एक ऐसा सवाल किया, जिसका जवाब हमें पहले ही मिल गया होना चाहिए था. कच्छ के मुंद्रा तटीय क्षेत्र की पारिस्थितिकीय संरचना वैसे ही कमज़ोर हो चुकी है, इसके बावजूद इस इलाक़े में 300 मेगावाट के थर्मल पावर प्लांट को ग़लत तरीक़े से एन्वॉयरोंमेंटल क्लियरेंस दे दिया गया. स्थानीय मछुआरे समुदायों ने इसके विरोध में अपनी सारी ताक़त लगा दी, लेकिन मेरे मित्र ने सूचना दी कि प्लांट को लेकर काम शुरू किया जा रहा है. उसने मुझसे यह भी पूछा कि मामले की अगली सुनवाई कब होनी है. मैंने उसे यह समझाने की भरपूर कोशिश की कि हम आज असहाय होकर क्यों रह गए हैं, लेकिन मेरा अंदाज़ा है कि ऐसी परिस्थितियों से रूबरू लोगों को समझाना खासा मुश्किल होता है, खासकर यदि वे ऐसी परियोजनाओं से सीधे तौर पर प्रभावित हो रहे हों. मैं उसे यह कैसे समझा सकती थी कि थर्मल प्लांट को पर्यावरणीय क्लियरेंस दिए जाने के ख़िलाफ़ जिस संस्थान में मामला दर्ज किया गया है, वह अब अस्तित्व में ही नहीं है. फिर उन्हें यह भी कैसे समझाया जा सकता है कि पुराने निकाय की जगह जिस नए निकाय का गठन किया जाना है और जहां इस मामले की सुनवाई होनी है, उसका गठन अभी तक नहीं किया गया है.

अब ज़रा आप इस परिस्थिति की कल्पना कीजिए. मान लीजिए कि आपके निवास स्थान के नज़दीक किसी ऐसी औद्योगिक परियोजना को मंजूरी दी जाती है, जिससे स्थानीय लोगों के रहन–सहन के पूरी तरह बदल जाने और उनकी जीविका पर बुरा असर पड़ने की आशंका है. इसके साथ ही वह परियोजना स्थानीय पर्यावरण पर भी बुरा असर डालती है. आप अपनी सारी ऊर्जा ख़र्च कर, यहां–वहां से जो मदद मिल सकती है, उसके सहारे मामले को नई दिल्ली तक लेकर आते हैं, जहां उसकी सुनवाई शुरू होती है. फिर अचानक ही केंद्र सरकार के एक फ़ैसले से आपका सारा किया–धरा पानी में चले जाने का ख़तरा पैदा हो जाता है. मैं बात कर रही हूं राष्ट्रीय पर्यावरण अपीलीय न्यायाधिकरण (नेशनल एन्वॉयरोंमेंट एपील्लेट अथॉरिटी) की, जहां औद्योगिक और आधारभूत संरचनाओं की परियोजनाओं को पर्यावरणीय क्लियरेंस को चुनौती दी जा सकती थी, लेकिन 18 अक्टूबर, 2010 को इसे समाप्त कर दिया गया. इसकी जगह वन एवं पर्यावरण मंत्रालय की महत्वाकांक्षी योजना नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एनजीटी) का गठन किया जाना था, जो एनईएए के अधीन आने वाले सभी मामलों की सुनवाई करे. लेकिन यह तो तभी संभव है, जबकि एनजीटी अस्तित्व में आए, इसके सदस्यों को नियुक्त किया जाए और इसके कामकाज से संबंधित नियम–कायदों को अंतिम रूप दिया जाए. लेकिन निराशाजनक बात यह है कि इन सब बातों के लिए कोई समय सीमा तय नहीं की गई है.

केवल गुजरात ही नहीं, बल्कि देश के अन्य हिस्सों में भी लोग एनईएए को समाप्त किए जाने और एनजीटी के गठन में हो रही देरी से परेशान हैं, क्योंकि मौक़े का फ़ायदा उठाते हुए इन परियोजनाओं पर काम शुरू किया जा रहा है. हालांकि ये परियोजनाएं तटीय क्षेत्रों की कमज़ोर पारिस्थितिकी के लिए ख़तरनाक हैं और इन्हें क्लियरेंस दिए जाने में नियम–क़ानूनों की धज्जियां उड़ाई गई हैं. एक ओर जहां स्थानीय मछुआरे आगे की रणनीति बना रहे हैं, मैं आपको एनजीटी के बारे में कुछ ऐसी जानकारियां देना चाहूंगी, जो सीधे तौर पर हमारी ज़िंदगियों से संबंधित हैं. प्रस्तावित योजना के मुताबिक़, एनजीटी का मुख्यालय नई दिल्ली में होगा और इसके पूरे देश में कम से कम चार क्षेत्रीय कार्यालय होंगे. पर्यावरण से संबंधित कई क़ानूनों के उल्लंघन के मामलों की सुनवाई का अधिकार इसके पास होगा, जिसमें प्रदूषण, वन्य क्षेत्रों का ग़ैर वन्य कार्यों के लिए इस्तेमाल और परियोजनाओं को पर्यावरणीय क्लियरेंस संबंधी मामले शामिल हैं. ग़ौरतलब है कि किसी भी परियोजना को एन्वॉयरोंमेंटल क्लियरेंस दिए जाने से पहले उसके प्रभाव के आकलन के लिए एन्वॉयरोंमेंट इंपैक्ट एसेसमेंट किया जाना ज़रूरी है. ये सारे क़ानून हमारी ज़िंदगियों को सीधे तौर पर प्रभावित करने की क्षमता रखते हैं और हमें वह ताक़त देते हैं कि हम ऐसी परियोजनाओं के ख़िलाफ़ आवाज़ उठा सकें, जिनका हमारे आसपास के पर्यावरण पर बुरा असर पड़ सकता है. लेकिन जिस तरह हत्या के ख़िलाफ़ क़ानून की मौजूदगी के बावजूद लोग इस अपराध को अंजाम देने से बाज नहीं आते, उसी तरह पर्यावरणीय क़ानूनों का उल्लंघन भी काफी आम है और इसके लिए एक विशेष न्यायाधिकरण का गठन समय की ज़रूरत है. एनजीटी के पास यह अधिकार भी होगा कि यदि कोई शोधार्थी या औद्योगिक प्रतिष्ठान किसी जैविक संसाधन या उससे संबंधित जानकारियों तक अपनी पहुंच बना लेता है और उससे होने वाले फ़ायदों को उसके वास्तविक संरक्षक के साथ नहीं बांटता तो उसके ख़िलाफ़ कार्रवाई करे. लेकिन पहली नज़र में यह प्रस्ताव जितना ही अच्छा लगे, वास्तविकता में शायद उतना अच्छा नहीं है. कई पर्यावरणीय एवं सामाजिक संस्थाओं ने कई कारणों से एनजीटी के गठन का कड़ा विरोध किया है. विरोध की सबसे बड़ी वजह यह है कि पहले यह व्यवस्था थी कि यदि किसी परियोजना को पर्यावरणीय क्लियरेंस ग़लत तरीक़े से दिया गया हो तो इसके ख़िलाफ़ उससे प्रभावित होने वाले लोग सीधे एनजीटी में अपील कर सकते थे, लेकिन नई व्यवस्था में यदि सरकार किसी परियोजना को मिले क्लियरेंस को वापस लेने का फ़ैसला करती है तो संबद्ध औद्योगिक संस्थान भी एनजीटी में दोबारा अपील कर सकता है.

दूसरी समस्या यह है कि पहले की व्यवस्था में पर्यावरण क़ानूनों के उल्लंघन की हालत में हाईकोर्ट में अपील की जा सकती थी, लेकिन एनजीटी के गठन के बाद इसके लिए नई दिल्ली स्थित इसके मुख्यालय अथवा चार क्षेत्रीय कार्यालयों में ही अपील की जा सकती है. तर्क दिए जा रहे हैं कि एनजीटी ऐसे मामलों के निपटारे के लिए विशेष रूप से गठित किया गया है और यहां मामलों की त्वरित सुनवाई होगी, लेकिन इसके पास आने वाले मामलों का स्वरूप ही कुछ ऐसा है कि उनकी पूरी जांच–पड़ताल करनी होगी और इसकी कोई गारंटी नहीं कि मामलों का हाईकोर्ट के मुक़ाबले तेजी से निष्पादन संभव हो सकेगा. इतना ही नहीं, एनजीटी प्रदूषण के चलते होने वाले नुक़सान की भरपाई के मामलों की भी सुनवाई करेगा और हर्जाने की रकम तय करने का काम इतना आसान नहीं है. एक समस्या यह भी है कि पूर्व के ख़राब अनुभव के बावजूद एनजीटी के सामने अपील दायर करने के लिए काफी कम समय दिया गया है. क्लियरेंस दिए जाने के 30 दिनों के भीतर ही फ़ैसले को चुनौती दी जा सकती है और अगले 60 दिनों के अंदर हमें ट्रिब्यूनल के सदस्यों को यह विश्वास दिलाना होगा कि परियोजना में देरी के लिए पर्याप्त कारण मौजूद हैं. हम में से कितने ऐसे लोग हैं, जिनकी पहुंच एन्वॉयरोंमेंट अथवा फॉरेस्ट क्लियरेंस से संबंधित काग़ज़ातों तक हो सकती है और इतने कम समय में अपील दायर करने में सक्षम हो सकते हैं. यह समस्या एनईएए के जमाने में भी थी और एनजीटी के गठन के बाद भी बनी रहेगी. लेकिन सच्चाई यह है कि गुजरात के मेरे मित्र और हम सभी लोगों के पास आज कोई विकल्प नहीं है. अप्रैल, 2010 में एनजीटी के गठन को संसद के दोनों सदनों की मंजूरी मिल गई थी. मेरा वन एवं पर्यावरण मंत्रालय से यही सवाल है कि नए न्यायाधिकरण के गठन से पहले पुराने न्यायाधिकरण को ख़त्म करने का भला क्या औचित्य है? गुजरात के मछुआरों और देश के अन्य हिस्सों में मौजूद प्रभावित लोगों के सवालों का जवाब कौन देगा, जो व्यवस्था की इस कमज़ोरी के चलते आज न्याय के लिए दर–दर भटक रहे हैं.

दूसरी समस्या यह है कि पहले की व्यवस्था में पर्यावरण क़ानूनों के उल्लंघन की हालत में हाईकोर्ट में अपील की जा सकती थी, लेकिन एनजीटी के गठन के बाद इसके लिए नई दिल्ली स्थित इसके मुख्यालय अथवा चार क्षेत्रीय कार्यालयों में ही अपील की जा सकती है.

(लेखिका पर्यावरणविद् हैं)

feedback@chauthiduniya.com

सदियों से न जाने कितने लोगों ने ऐसी कोशिशें की हैं, पर कामयाबी कुछ को ही हासिल हो पाई.

मनरेगा का हिसाब-किताब

नरेगा अब मनरेगा ज़रूर हो गई, लेकिन भ्रष्टाचार अभी भी ख़त्म नहीं हुआ. इस योजना के तहत देश के करोड़ों लोगों को रोज़गार दिया जा रहा है. गांव के ग़रीबों–मजदूरों के लिए यह योजना एक तरह संजीवनी का काम कर रही है. सरकार हर साल लगभग 40 हज़ार करोड़ रुपये ख़र्च कर रही है, लेकिन देश के कमोबेश सभी हिस्सों से यह ख़बर आती रहती है कि कहीं फर्जी मस्टररोल बना दिया गया तो कहीं मृत आदमी के नाम पर सरपंच–ठेकेदारों ने पैसा उठा लिया. साल में 100 दिनों की जगह कभी–कभी सिर्फ़ 70–80 दिन ही काम दिया जाता है. काम के बदले पूरा पैसा भी नहीं दिया जाता. ज़ाहिर है, यह पैसा उन ग़रीबों के हिस्से का होता है, जिनके लिए यह योजना बनाई गई है. मनरेगा में भ्रष्टाचार का सोशल ऑडिट कराने की योजना का भी पंचायतों एवं ठेकेदारों द्वारा ज़बरदस्त विरोध किया जाता है. कभी–कभी तो मामला मारपीट तक पहुंच जाता है, हत्या तक हो जाती है. अब सवाल यह है कि इस भ्रष्टाचार का मुक़ाबला कैसे किया जाए? इसका जवाब बहुत आसान है. इस समस्या से लड़ने का हथियार भी बहुत कारगर है, सूचना का अधिकार. आपको बस अपने इस अधिकार का इस्तेमाल करना है. इस बार का आवेदन मनरेगा से संबंधित है. यह आवेदन इस योजना में हो रही धांधली को सामने लाने और जॉब कार्ड बनवाने में मददगार साबित हो सकता है. हम पाठकों से अपेक्षा करते हैं कि वे गांव–देहात में रहने वाले लोगों को भी इस कॉलम के बारे में बताएंगे और दिए गए आवेदन के प्रारूप को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएंगे. सरकारी योजनाओं में व्याप्त भ्रष्टाचार से लड़ने की चौथी दुनिया की मुहिम में आपका साथ भी मायने रखता है. यहां हम मनरेगा योजना से जुड़े कुछ सवाल आवेदन के रूप में प्रकाशित कर रहे हैं. आप इस आवेदन के माध्यम से मनरेगा के तहत बने जॉब कार्ड, मस्टररोल, भुगतान, काम एवं ठेकेदार के बारे में सूचनाएं मांग सकते हैं. चौथी दुनिया आपको इस कॉलम के माध्यम से वह ताक़त दे रहा है, जिससे आप पूछ सकेंगे सही सवाल. एक सही सवाल आपकी ज़िंदगी बदल सकता है. हम आपको हर अंक में बता रहे हैं कि कैसे सूचना अधिकार क़ानून का इस्तेमाल करके आप दिखा सकते हैं घूस को घूंसा. किसी भी तरह की दिक्कत या परेशानी होने पर हम आपके साथ हैं.

हम पाठकों से अपेक्षा करते हैं कि वे गांव-देहात में रहने वाले लोगों को भी इस कॉलम के बारे में बताएंगे और दिए गए आवेदन के प्रारूप को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएंगे.

चौथी दुनिया ब्यूरो
feedback@chauthiduniya.com

यदि आपने सूचना क़ानून का इस्तेमाल किया है और अगर कोई सूचना आपके पास है, जिसे आप हमारे साथ बांटना चाहते हैं तो हमें वह सूचना निम्न पते पर भेजें. हम उसे प्रकाशित करेंगे. इसके अलावा सूचना का अधिकार क़ानून से संबंधित किसी भी सुझाव या परामर्श के लिए आप हमें ईमेल कर सकते हैं या हमें पत्र लिख सकते हैं. हमारा पता है :

चौथी दुनिया

एफ–2, सेक्टर–11, नोएडा (गौतमबुद्ध नगर) उत्तर प्रदेश, पिन –201301
ई–मेल : rti@chauthiduniya.com

आवेदन का प्रारूप

(मनरेगा के तहत जॉब कार्ड, रोजगार एवं बेरोजगारी भत्ता का विवरण)

सेवा में,
लोक सूचना अधिकारी
(विभाग का नाम)
(विभाग का पता)

विषय: *सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत आवेदन*

महोदय,
.....ब्लॉक के ग्राम.....के संबंध में निम्नलिखित सूचनाएं उपलब्ध कराएं:

1. उपरोक्त गांव से एनआरईजीए के तहत जॉब कार्ड बनाने केलिए अब तक कितने आवेदन प्राप्त हुए? इसकी सूची निम्नलिखित विवरणों के साथ उपलब्ध कराएं:
क. आवेदक का नाम व पता.
ख. आवेदन संख्या.
ग. आवेदन की तारीख.
घ. आवेदन पर की गई कार्यवाही का संक्षिप्त विवरण (जॉब कार्ड बना/जॉब कार्ड नहीं बना/विचाराधीन).
ड. यदि जॉब कार्ड नहीं बना तो उसका कारण बताएं.
च. यदि बना तो किस तारीख को.

2. जिन लोगों को जॉब कार्ड दिया गया है, उनमें से कितने लोगों ने काम के लिए आवेदन किया? उसकी सूची निम्नलिखित सूचनाओं के साथ उपलब्ध कराएं:
क. आवेदक का नाम व पता.
ख. आवेदन करने की तारीख.
ग. दिए गए कार्य का नाम.
घ. कार्य दिए जाने की तारीख.
ड. कार्य के लिए भुगतान की गई राशि व भुगतान की तारीख.
च. रिकॉर्ड रजिस्टर के उस भाग की प्रमाणित प्रति, जहां उनकेभुगतान से संबंधित विवरण दर्ज हैं.
छ. यदि काम नहीं दिया गया है तो क्यों?
ज. क्या उन्हें बेरोजगारी भत्ता दिया जा रहा है?

3. उपरोक्त गांव से एनआरईजीए के तहत रोजगार के लिए आवेदन करने वाले जिन आवेदकों को बेरोजगारी भत्ता दिया गया या दिया जा रहा है, उनकी सूची निम्नलिखित सूचनाओं के साथ उपलब्ध कराएं:
क. आवेदक का नाम व पता.
ख. आवेदन करने की तारीख.
ग. बेरोजगारी भत्ता दिए जाने की तारीख.
ड. बतौर बेरोजगारी भत्ता भुगतान की गई राशि व भुगतान की तारीख.
च. रिकॉर्ड रजिस्टर के उस भाग की प्रमाणित प्रति, जहां उनकेभुगतान से संबंधित विवरण दर्ज हैं.

मैं आवेदन शुल्क के रूप में.....रुपये अलग से जमा कर रहा/रही हूं.
या
मैं बीपीएल कार्डधारक हूं, इसलिए सभी देय शुल्कों से मुक्त हूं. मेरा बीपीएल कार्ड नंबर.....है.

यदि मांगी गई सूचना आपके विभाग/कार्यालय से संबंधित न हो तो सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6 (3) का संज्ञान लेते हुए मेरा आवेदन संबंधित लोक सूचना अधिकारी को पांच दिनों की समयावधि के अंतर्गत हस्तांतरित करें. साथ ही अधिनियम के प्रावधानों के तहत सूचना उपलब्ध कराते समय प्रथम अपील अधिकारी का नाम और पता अवश्य बताएं.

भवदीय

नाम.....
पता.....
फोन नंबर.....

संलग्नक.....
(यदि कुछ हो तो)

ज़रा हट के

साइकिल नहीं, प्लेन चलाइए

खुले आसमान में परिंदों की तरह अपने दम पर उड़ने की चाह किसे नहीं होती. सदियों से न जाने कितने लोगों ने ऐसी कोशिशें की हैं, पर कामयाबी कुछ को ही हासिल हो पाई. ऐसी ही एक कामयाबी मिली है टोरंटो यूनिवर्सिटी के टॉड रीचर्ट को. रीचर्ट ने एक ऐसा एयरक्राफ्ट बनाया है, जिसके पंख पायलट द्वारा पैडल चलाने से फड़फड़ाने लगते हैं और प्लेन हवा में उड़ने लगता है. बीते 2 अगस्त को इसका सफल ट्रायल भी हुआ, जिसमें एयरक्राफ्ट ने लगातार 20 सेकेंड तक उड़ान भरी. एविएशन के इतिहास में अपनी तरह के इस अजूबे एयरक्राफ्ट का नाम स्नोबर्ड रखा गया है. 2 अगस्त को कनाडा के टोटेनहम में ग्रेट लेक्स ग्लाइडिंग क्लब में इसने रिकॉर्ड उड़ान भरी. इस दौरान स्नोबर्ड 19.3 सेकेंड तक ऊंचाई और हवा की तेजी दोनों के साथ तालमेल बनाते हुए उड़ता रहा. इसने 25.6 किलोमीटर प्रति घंटे की औसत गति से 145 मीटर की दूरी तय की.

इस प्रोजेक्ट के हेड टॉड के मुताबिक़, स्नोबर्ड के रूप में सदियों पुराना सपना पूरा हुआ है. बीती सदियों में विभिन्न इंजीनियरों ने ही नहीं, 1485 में लियोनार्डो दा विंसी ने भी पहला ह्यूमन पावर्ड ऑर्निथॉप्टर का स्केच तैयार किया था. हालांकि जहां तक स्नोबर्ड की बात है तो इसका वजन 45 किलोग्राम है और इसके पंखों का कुल फैलाव (विंग स्पैन) 32 मीटर तक है. इसके विंग स्पैन की तुलना भले ही बोइंग 737 से की जा सकती हो, पर स्नोबर्ड का वजन बोइंग की तुलना में बहुत कम है. वैसे पायलट टॉड ने इस एयरक्राफ्ट में उड़ने के लिए ख़ुद का 8.5 किलोग्राम वजन कम किया है. टॉड एयरो स्पेस इंजीनियरिंग में ग्रेजुएट हैं और फ़िलहाल पीएचडी कर रहे हैं. स्नोबर्ड को बनाते वक़्त उन्होंने इसके डिज़ाइन, वजन और सही ढांचे पर ख़ास ध्यान दिया. ख़ास बात यह है कि स्नोबर्ड पर उनके रिसर्च में इंसानी शरीर और उसकी ताक़त के इस्तेमाल पर भी ध्यान दिया गया. इसे समझाते हुए टॉड कहते हैं कि चलते–फिरते समय या साइकिलिंग के दौरान इंसानी ताक़त का बहुत सही इस्तेमाल होता है. यह ट्रांसपोर्टेशन का बढ़िया रूप है. हालांकि स्नोबर्ड ट्रांसपोर्टेशन का प्रैक्टिकल मेथड नहीं है, पर यह दूसरों के लिए एक प्रेरणा ज़रूर है, जो बताती है कि हम अपने शरीर और दिमाग़ की क्रिएटिविटी का इस्तेमाल करके अपने सपनों को पूरा कर सकते हैं.

शेर को मिला सवा...

अभी तक आपने शेर को सवा शेर मिलने वाली घटनाएं सुनी होंगी, लेकिन इस बार शेर को सवा कुत्ता मिल गया, जिसने उसे दौड़ा–दौड़ाकर मारा. घटना अमेरिका की है. हुआ यह कि चाड स्ट्रेंज ने अमेरिका के साउथ डकोटा राज्य में स्थित पारिवारिक फ़ॉर्म पर अपने पालतू कुत्ते द्वारा ज़ोर–ज़ोर से भौंकने की आवाज़ सुनी. बाहर निकल कर उसने देखा कि कूगर प्रजाति का एक पहाड़ी शेर पेड़ की चोटी पर विराजमान था और उनका जैक रसेल नस्ल का कुत्ता नीचे बैठा हुआ था. अब आप सोच रहे होंगे कि मुक़ाबला कितना बेमेल था. इस बात का अंदाज़ा इसी से लगाइए कि पहाड़ी शेर का भार क़रीब 68 किलोग्राम था और कुत्ते का वज़न महज़ आठ किलोग्राम. इसके बाद चाड स्ट्रेंज ने अपने कुत्ते की सहायता से उस पहाड़ी शेर को दौड़ाया और फिर उसे गोली मार दी. बाद में उसने एक स्थानीय अख़बार को बताया कि उसका कुत्ता हमेशा बिल्लियों के पीछे पड़ा रहता है. उसे शायद लगा होगा कि यह भी महज़ एक बिल्ली है. कूगर प्रजाति के शेरों के जानकार प्रोफ़ेसर जोनाथन जेंक्स के मुताबिक, आमतौर पर दो–तीन कुत्ते ही पेड़ पर बैठे शेर को भगाने में कामयाब हो सकते हैं.

जेंक्स ने कहा कि शायद शेर इतना भूखा नहीं था कि वह कुत्ते पर हमला कर देता. उन्होंने कहा, हो सकता है कि शेर जंगल में रास्ता भटक गया हो और शायद इसीलिए वह पहाड़ों से उतर फ़ॉर्म में प्रवेश कर गया. शेर को मारने के लिए कुत्ते के मालिक पर कोई मुकदमा नहीं चलाया जा सकता, क्योंकि साउथ डकोटा में अगर शेर आपके या आपके पालतू जानवरों के लिए ख़तरा बने तो आप उसे गोली मार सकते हैं. फ़िलहाल मृत शेर को अध्ययन के लिए स्थानीय विश्वविद्यालय में ले जाया गया है.

चौथी दुनिया ब्यूरो
feedback@chauthiduniya.com

राशिफल

दिल्ली, 13 दिसंबर–19 दिसंबर 2010

मेष (21 मार्च से 20 अप्रैल)
दिल के मामले में ख़ुशी और शांति मिलेगी. व्यवसायिक यात्रा सफल रहेगी. वाणी पर नियंत्रण बनाएं रखें. व्यवसायिक मामलों में वास्तविकता को ध्यान में रखने की ज़रूरत है.

वृष (21 अप्रैल से 20 मई)
इस हफ्ते आपको काफी बुद्धिमानी से काम लेना होगा. समाज के कार्यों के लिए तत्पर रहेंगे. आपके नए प्रोजेक्ट परिणाम देने में कुछ समय लेंगे. ख़र्चे बढ़ेंगे. चिंता आपकी सेहत पर प्रभाव डाल सकती है. यात्रा के दौरान कोई महिला चिंता का कारण बन सकती है.

मिथुन (21 मई से 20 जून)
नई प्रॉपर्टी ख़रीदने की योजना बना सकते हैं. जिनसे आप प्यार करते हैं, वे इस बात से बहुत ख़ुश होंगे. जैसे–जैसे सप्ताह आगे बढ़ेगा, पार्टनरशिप और कम्युनिकेशन में आपकी क्षमता भी बढ़ेगी. व्यवसाय में अच्छा फ़ायदा होगा. यात्रा किसी भी हालत में टालें.

कर्क (21 जून से 20 जुलाई)
सप्ताह की शुरुआत से ही आपका मन जिस बात के लिए तैयार नहीं है, उसे भूल जाना ही बेहतर होगा. किसी अधीनस्थ कर्मचारी का सहयोग मिलेगा, जो आपकी सफलता के लिए अनुकूल होगा. आपसे प्यार करने वाले आपको सहयोग करेंगे.

सिंह (21 जुलाई से 20 अगस्त)
आप नफा–नुक़सान की परवाह किए बिना अपने काम पर ध्यान देंगे. बच्चों एवं रिश्तेदारों पर ख़र्चे बढ़ेंगे. जो आप कर रहे हैं, उस पर विश्वास ही आपके जीवन को बेहतर बना सकता है. पारिवारिक आयोजन प्रसन्नता प्रदान करेंगे. यात्रा में चिंता रहेगी.

कन्या (21 अगस्त से 20 सितंबर)
अचानक कहीं यात्रा पर जाना पड़ सकता है. मांगलिक कार्यों के लिए किया जा रहा प्रयास सफल साबित होगा. कुछ समय से पड़े हुए कार्य पूरे हो जाएंगे. सेहत के प्रति लापरवाह रवैया मांसपेशियों से संबंधित समस्याएं पैदा सकता है.

तुला (21 सितंबर से 20 अक्टूबर)
अपने भीतर की आवाज़ सुनें, इससे आप अपने लक्ष्य जल्दी पूरे कर पाएंगे. यात्रा पर ख़र्च बढ़ेगा. आपने जहां जाने की योजना बनाई है, उस जगह विशेष को लेकर परिवार में काफी जोश रहेगा. छुट्टियां बिताना मजेदार साबित होगा.

वृश्चिक (21 अक्टूबर से 20 नवंबर)
दिल के मामले में थोड़ा उलझाव महसूस करेंगे. कुछ ऐसी स्थितियां हैं, जिनसे आप बाहर आना चाहते हैं, मगर नहीं आ पा रहे हैं. काम के मामले में कोई व्यक्ति आपकी चिंता का कारण बनेगा. परिवार का कोई छोटा सदस्य आपकी सहायता करेगा.

धनु (21 नवंबर से 20 दिसंबर)
संतान के संबंध में कोई सुखद समाचार प्राप्त होगा. पेट संबंधी शिक़ायत आपको तकलीफ दे सकती है. आय के नए स्रोत बनेंगे. यात्रा आपके तनाव को कम करेगी. ईश्वर के प्रति श्रद्धा एवं विश्वास रखें.

मकर (21 दिसंबर से 20 जनवरी)
सप्ताह ख़त्म होने के साथ–साथ आर्थिक स्थिति में सुधार आएगा. अगर आप शिफ्ट कर रहे हैं तो कुछ निराशा हाथ लग सकती है. परिवार से ख़ुशी और सहयोग मिलेगा. वाहन सावधानी से चलाएं, वरना दुर्घटना होने की आशंका है.

कुंभ (21 जनवरी से 20 फरवरी)
अपने से किसी बड़े की सेहत चिंता का कारण बन सकती है. नाक, कान और गले से संबंधित समस्याओं के प्रति सावधान रहें. यात्रा सामान्य रहेगी. दूसरों को कटु वचन बोलने से बचें, अन्यथा विवाद की स्थिति पैदा हो सकती है.

मीन (21 फरवरी से 20 मार्च)
स्वास्थ्य संबंधी मामलों को लेकर ख़र्चे बढ़ेंगे. यात्रा सेहत को प्रभावित कर सकती है. नए स्थानों की यात्रा सफल रहेगी. परिवार में प्रेम बढ़ाने के लिए विशेष प्रयासों की जरूरत है.

पंडित सुदर्शन
feedback@chauthiduniya.com

आतंकवाद पाकिस्तान की विदेश नीति का एक अहम अंग है, जिसके ज़रिये वह अमेरिका और भारत को ब्लैकमेल करने की कोशिश करता है.

विकीलीक्स ने पाकिस्तान की पोल खोली

पाकिस्तान की ख़राब आंतरिक हालत पूरी दुनिया के लिए ख़तरे का संकेत है. विकीलीक्स के ख़ुलासों से यह बात और भी ज़्यादा स्पष्ट हो चुकी है कि पाकिस्तान में क़ानून का शासन नहीं है. कार्यपालिका और व्यवस्थापिका से लेकर देश की सेना में भी धार्मिक कट्टरवादी ताक़तों का वर्चस्व है और वे आतंकी संगठनों के साथ मिली हुई हैं. ये ताक़तें भारत के ख़िलाफ़ हर समय मोर्चा खोलने को तैयार बैठी हैं. भारत के लिए तो यह चिंता की बात है ही, पूरी दुनिया को इस समस्या पर गंभीरता से विचार करने की ज़रूरत है, वरना विश्व शांति पर बुरा असर पड़ सकता है.

आदित्य पूजन

भारत का पड़ोसी देश पाकिस्तान उसके ख़िलाफ़ जंग के लिए किसी भी वक़्त तैयार है. वह भारत विरोधी आतंकी संगठनों को बढ़ावा देता है, देश में अशांति फैलाने के लिए हर तरह की मदद उपलब्ध कराता है. यह बात तो हर भारतीय जानता है तो फिर इसमें नया क्या है. संवेदनशील दस्तावेजों को प्रकाशित करने वाली वेबसाइट विकीलीक्स द्वारा लीक किए गए दस्तावेजों में यदि कुछ नया है तो वह यह कि यह बात अमेरिका भी अच्छी तरह जानता है. हालांकि अमेरिका अब तक इसे सार्वजनिक तौर पर स्वीकार करने से बचता रहा है, लेकिन अमेरिकी विदेश विभाग के जो दस्तावेज विकीलीक्स ने लीक किए हैं, उससे यह बात स्पष्ट हो जाती है. साथ ही यह बात भी खुलकर सामने आती है कि आतंकवाद पाकिस्तान की विदेश नीति का एक अहम अंग है, जिसके ज़रिये वह अमेरिका और भारत को ब्लैकमेल करने की कोशिश करता है. वह वॉर अगेंस्ट टेरर के नाम पर अमेरिका से आर्थिक सहायता के रूप में बड़ी रकम तो लेता है, लेकिन अफ़ग़ानिस्तान में अपने सैनिकों को तैनात नहीं करता, क्योंकि वह भारत के सीमावर्ती क्षेत्रों से अपने सैनिकों को हटा नहीं सकता. सबसे चिंताजनक बात तो यह है कि भारत विरोधी आतंकी संगठनों को मदद देने के काम में पाक सेना और आईएसआई के अधिकारी खुले तौर पर शामिल हैं. सेना पर किसी का नियंत्रण नहीं है. देश में लोकतांत्रिक ढंग से चुनी गई सरकार मौजूद है, लेकिन सारे फ़ैसले सेना ही लेती है. राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी कितने शक्तिहीन हैं, इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि वह हर पल सेना द्वारा अपनी हत्या कर दिए जाने के ख़ौफ़ में जी रहे हैं. हत्या की हालत में वह अपनी बहन को उत्तराधिकारी घोषित करने की तैयारी भी कर चुके हैं. प्रधानमंत्री यूसुफ रजा गिलानी अपनी सत्ता बनाए रखने के लिए सैन्य तंत्र के पिछलग्गू बनकर रह गए हैं. पाकिस्तान में कमज़ोर पड़ चुकी लोकतांत्रिक व्यवस्था की जड़ में देश के राजनीतिक नेतृत्व का भ्रष्टाचार और सत्तालोलुपता है, लेकिन सबसे ज़्यादा चिंता की बात पाकिस्तान के पास परमाणु बमों का होना है. विकीलीक्स के खुलासों के मुताबिक़, एटमी हथियार जमा करने के मामले में पाकिस्तान सबसे तेज़ है, लेकिन सेना और आतंकी संगठनों के बीच घालमेल के चलते इन हथियारों का बेजा इस्तेमाल होने का ख़तरा भी हर समय मंडरा रहा है. भारत के लिए चिंता की बात इसलिए ज्यादा है, क्योंकि पाकिस्तान की सारी तैयारी भारत को ही केंद्र में रखकर होती है. उसकी कूटनीति, विदेश नीति एवं सैन्य नीति, सबके केंद्र में भारत ही है. भारत से डर का हौव्वा खड़ाकर वह दूसरे देशों से मदद हासिल करता है और फिर उसका इस्तेमाल आतंकी संगठनों को प्रोत्साहित करने के लिए करता है. पाकिस्तान जानता है कि भारत उसके ख़िलाफ़ युद्ध से बचता है, इसलिए नहीं कि वह कमज़ोर है, बल्कि इसलिए कि एक ज़िम्मेदार लोकतांत्रिक राष्ट्र होने के नाते भारत वैश्विक परिदृश्य पर पड़ने वाले असर को लेकर फिक्रमंद है. पाकिस्तान ऐसी चिंताओं से मुक्त है, क्योंकि पाक नेतृत्व भारत के नाम का सहारा लेकर राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तरों पर समर्थन जुटाने में कामयाब होता है. ये तमाम बातें भारत जानता है और समय-समय पर पूरी दुनिया को इस बारे में बताता भी रहा है. विकीलीक्स के ख़ुलासों ने भारत के दावों की पुष्टि कर दी है. सच्चाई यह है कि विकीलीक्स द्वारा लीक किए दस्तावेजों से पाकिस्तान की जो सच्चाई सामने आई है, वह भारत के लिए तो चिंता का विषय है ही, पूरी दुनिया के लिए ख़तरे का संकेत है.

लोकतांत्रिक राष्ट्र होने के नाते भारत वैश्विक परिदृश्य पर पड़ने वाले असर को लेकर फ़िक्रमंद है. पाकिस्तान ऐसी चिंताओं से मुक्त है, क्योंकि पाक नेतृत्व भारत के नाम का सहारा लेकर राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तरों पर समर्थन जुटाने में कामयाब होता है. ये तमाम बातें भारत जानता है और समय-समय पर पूरी दुनिया को इस बारे में बताता भी रहा है

विकीलीक्स के दस्तावेजों से यह भी स्पष्ट है कि पाकिस्तान अमेरिका की बात भी नहीं मानता. वह आर्थिक मदद के लिए उसके आगे हाथ फैलाने में शर्म महसूस नहीं करता, लेकिन आतंकी संगठनों को मदद न पहुंचाने की बात पर नाक-भौं सिकोड़ने लगता है. ख़ुद अमेरिकी अधिकारी भी इस बात को जानते हैं कि पाकिस्तान चार बड़े आतंकी संगठनों को मदद उपलब्ध कराता है. इनमें अफ़ग़ानिस्तान में तालिबान, पश्चिमी अफ़ग़ानिस्तान में तालिबान के सहयोगी हक्कानी और हिकमतयार का नेटवर्क तथा मुंबई हमलों में शामिल रही लश्करे तैयबा आदि हैं. अमेरिकी अधिकारी इस बात से भी अच्छी तरह वाकिफ हैं कि पाकिस्तानी सेना और आईएसआई के कई शीर्ष अधिकारी इन संगठनों के साथ जुड़े हुए हैं, लेकिन वे चाहकर भी कुछ नहीं कर सकते. विकीलीक्स के दस्तावेजों के मुताबिक़, सितंबर 2009 में पाकिस्तान में अमेरिकी राजदूत एन पीटरसन ने अफगानिस्तान, पाकिस्तान के लिए अमेरिकी रणनीति पर विचार व्यक्त करते हुए कहा था कि पाकिस्तान को दी जाने वाली मदद में बढ़ोत्तरी के बाद भी इस बात की उम्मीद नहीं है कि वह इन आतंकवादी संगठनों के प्रति अपनी नीति में बदलाव करेगा. इन दस्तावेजों से यह भी स्पष्ट है कि अमेरिका यह जानता है कि पाकिस्तान आतंकवादियों के प्रति अपनी नीति में कभी बदलाव नहीं करेगा. अमेरिकी अधिकारियों को इस बात की आशंका भी है कि पाकिस्तानी प्रशासनिक तंत्र में ऐसे लोग हैं, जो तस्करी के ज़रिये परमाणु हथियारों की सामग्री जुटा सकते हैं. परमाणु हथियारों की तस्करी और उन तक आतंकी तत्वों की पहुंच ऐसे मुद्दे हैं, जो सीधे तौर पर क्षेत्रीय और वैश्विक शांति को प्रभावित कर सकते हैं. 26-11 को मुंबई में हुए आतंकी हमले के बाद पाकिस्तान इस बात से डरा हुआ था कि भारत कहीं जवाबी कार्रवाई न करे. राष्ट्रपति आसिफ अली ज़रदारी ने सार्वजनिक तौर पर कहा था कि यदि ऐसा हुआ तो पाकिस्तान परमाणु हथियारों का इस्तेमाल नहीं करेगा. लेकिन विकीलीक्स के ख़ुलासों के मुताबिक़, पाक सेना ज़रदारी के बयान के प्रति गंभीर नहीं थी और परमाणु हथियारों का इस्तेमाल करने के लिए तैयार बैठी थी. जब देश की सत्ता पर शासन तंत्र की पकड़ इतनी कमज़ोर हो तो स्थिति की गंभीरता को आसानी से समझा जा सकता है.

भारत के विदेश मंत्री एस एम कृष्णा भले कहें कि वह इन ख़ुलासों को कोई ख़ास तवज्ज़ो नहीं देते, लेकिन सच्चाई यह है कि भारत चाहकर भी इस ख़तरे की अनदेखी नहीं कर सकता. ख़ासकर, भारत से संबंधित अमेरिका और पाकिस्तान से जुड़े जो दस्तावेज हैं, उन पर हमारे कूटनीतिक विशेषज्ञों को गंभीरता से विचार करने की ज़रूरत है. न ही विश्व समुदाय इन ख़ुलासों के बाद हाथ पर हाथ धरे बैठे रहने का ज़ोख़िम ले सकता है. शायद वह समय आ चुका है, जब पाकिस्तान पर नकेल कसने के लिए वैश्विक समुदाय एकमत होकर आगे आए. अमेरिका को भी यह समझना होगा कि आर्थिक प्रलोभनों के सहारे पाकिस्तान को पुचकारने की उसकी नीति कारगर नहीं हो सकती. विश्व शांति को बनाए रखने के लिए अब कड़े क़दम उठाने ही होंगे.

aditya@chauthiduniya.com

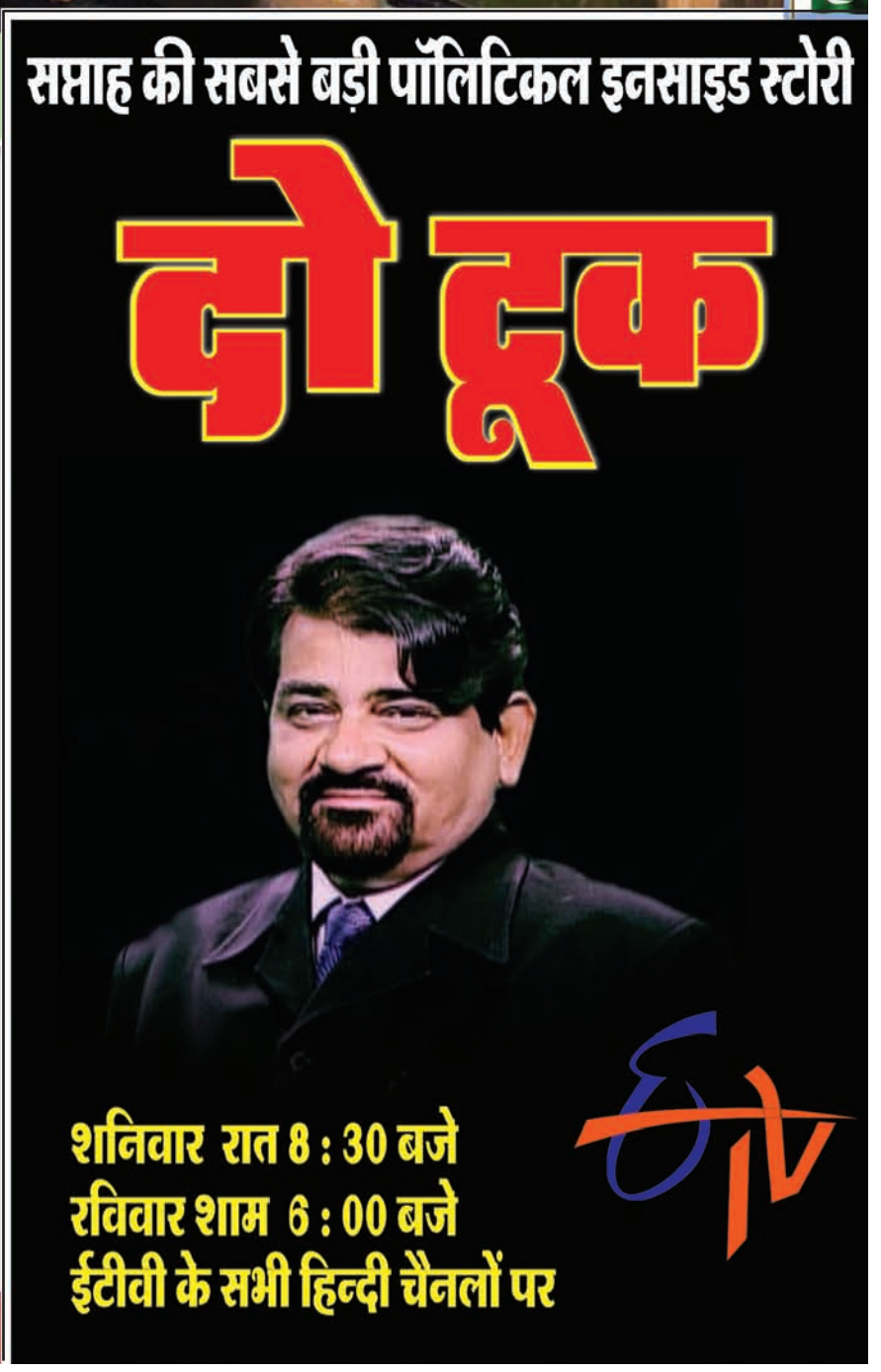

बाला बुवा सुतार

श्रीमती कुलकर्णी एवं उनके बच्चों ने उससे पूछा कि आप शिरडी के साई बाबा तो नहीं हैं? इस पर उत्तर मिला कि हम तो साई बाबा के आज्ञाकारी सेवक हैं और उनकी आज्ञा से ही आप लोगों की कुशल-क्षेम पूछने यहां आए हैं. फकीर ने दक्षिणा मांगी तो श्रीमती कुलकर्णी ने उन्हें एक रुपया भेंट किया. तब फकीर ने उन्हें उदी की एक पुड़िया देते हुए कहा कि इसे अपने पूजन में चित्र के साथ रखो. इतना कहकर वह वहां से चला गया.

आरती श्री शिरडी के साई बाबा की

आरती श्री साई गुरूवर की, परमानंद सदा सुरवर की
जाकी कृपा विपुल सुखकारी, दुख, शोक, संकट, भयहारी
शिरडी में अवतार रचाया, चमत्कार से तत्व दिखाया
कितने भक्त चरण पर आए, वे सुख शांति चिरतंन पाए
भाव धरे मन में जैसा, पावत अनुभव वो ही वैसा
गुरू की लगावे तन को, समाधान लाभत उस मन को
साई नाम सदा जा गावे, सो फल जग में शाश्वत पावे
गुरूबारसर करि पूजा सेवा, उस पर कृपा करत गुरुदेवा
राम, कृष्ण, हनुमान रूप में, दे दर्शन जानत जो मन में
विविध धर्म के सेवक आते, दर्शन से इच्छित फल पाते
जय बोलो साई बाबा की, जय बोलो अवधूत गुरू की
साईदास आरती को गावे, घर में बसि सुख मंगल पावे.

बंबई में एक बाला बुवा नामक संत थे, जो अपनी भक्ति, भजन एवं आचरण के कारण आधुनिक तुकाराम के नाम से विख्यात थे. 1917 में वह शिरडी आए. जब उन्होंने बाबा को प्रणाम किया तो वह कहने लगे कि मैं तो इन्हें चार वर्षों से जानता हूं. बाला बुवा को आश्चर्य हुआ और उन्होंने सोचा कि मैं तो पहली बार ही शिरडी आया हूं, फिर यह कैसे संभव हो सकता है. गहन चिंतन करने पर उन्हें याद आया कि चार साल पहले उन्होंने बंबई में बाबा के चित्र को नमस्कार किया था. उन्हें बाबा के शब्दों की यथार्थता का बोध हो गया और वह मन ही मन कहने लगे कि संत कितने सर्वव्यापक और सर्वज्ञानी होते हैं तथा अपने भक्तों के प्रति उनके हृदय में कितनी दया होती है. मैंने तो केवल उनके चित्र को ही नमस्कार किया था तो भी यह घटना उन्हें ज्ञात हो गई. इसलिए उन्होंने मुझे इस बात का अनुभव कराया है कि उनके चित्र को देखना उनके दर्शन के समान है.

अब हम अप्पा साहेब की कथा पर आते हैं. जब वह ठाणे में थे तो उन्हें भिवंडी दौरे पर जाना पड़ा, जहां से उनका एक सप्ताह में लौटना संभव न था. उनकी अनुपस्थिति में तीसरे दिन उनके घर एक विचित्र घटना हुई. दोपहर के समय अप्पा साहेब के घर पर एक फकीर आया, जिसकी आकृति बाबा के चित्र से ही मिलती-जुलती थी. श्रीमती कुलकर्णी एवं उनके बच्चों ने उससे पूछा कि आप शिरडी के साई बाबा तो नहीं हैं? इस पर उत्तर मिला कि हम तो साई बाबा के आज्ञाकारी सेवक हैं और उनकी आज्ञा से ही आप लोगों की कुशल-क्षेम पूछने यहां आए हैं. फकीर ने दक्षिणा मांगी तो श्रीमती कुलकर्णी ने उन्हें एक रुपया भेंट किया. तब फकीर ने उन्हें उदी की एक पुड़िया देते हुए कहा कि इसे अपने पूजन में चित्र के साथ रखो. इतना कहकर वह वहां से चला गया. अब बाबा की अद्भुत लीला सुनिए.

भिवंडी में अप्पा साहेब का घोड़ा बीमार हो गया, जिससे वह दौरे पर आगे न जा सके और उसी शाम वह घर लौट आए. घर आने पर उन्हें पत्नी द्वारा फकीर के आगमन का समाचार मिला. उन्हें मन में थोड़ी अशांति सी हुई कि मैं फकीर के दर्शनों से वंचित रह गया और पत्नी द्वारा केवल एक रुपया दक्षिणा देना उन्हें अच्छा न लगा. वह कहने लगे कि यदि मैं उपस्थित होता तो 10 रुपये से कम कभी न देता. वह भूखे ही फकीर की खोज में निकल पड़े. उन्होंने मस्जिद एवं अन्य कई स्थानों पर खोज की, परंतु उनकी खोज व्यर्थ ही सिद्ध हुई. पाठक अध्याय 32 में कहे गए बाबा के वचनों का स्मरण करें कि भूखे पेट ईश्वर की खोज नहीं करनी चाहिए. अप्पा साहेब को शिक्षा मिल गई. वह भोजन के उपरांत जब अपने मित्र श्री चित्रे के साथ घूमने को निकले, तब थोड़ी ही दूर जाने पर उन्हें सामने से एक फकीर द्रुत गति से आता हुआ दिखाई पड़ा. अप्पा साहेब ने सोचा कि यह तो वही फकीर लग रहा है, जो मेरे घर पर आया था तथा उसकी आकृति भी बाबा के चित्र के अनुरूप ही है. फकीर ने तुरंत ही हाथ बढ़ाकर दक्षिणा मांगी. अप्पा साहेब ने उसे एक रुपया दे दिया, तब वह और मांगने लगा. अब अप्पा साहेब ने दो रुपये दिए. तब भी उसे संतोष न हुआ. उन्होंने अपने मित्र चित्रे से 3 रुपये उधार लेकर दिए, फिर भी वह मांगता ही रहा. तब अप्पा साहेब ने उसे घर चलने को कहा. सब लोग घर पर आए और अप्पा साहेब ने उन्हें 3 रुपये और दिए. कुल मिलाकर 9 रुपये. फिर भी वह असंतुष्ट प्रतीत होता था और मांगे ही जा रहा था. तब अप्पा साहेब ने कहा कि मेरे पास तो 10 रुपये का नोट है. तब फकीर ने नोट ले लिया और 9 रुपये लौटाकर चला गया. अप्पा साहेब ने 10 रुपये देने को कहा था, इसलिए फकीर ने उनसे 10 रुपये ले लिए और बाबा द्वारा स्पर्शित 9 रुपये उन्हें वापस मिल गए.

उदी की पुड़िया खोलने पर अप्पा साहेब ने देखा कि उसमें फूल के पत्ते और अक्षत हैं. जब वह कालांतर में शिरडी गए तो उन्हें बाबा ने अपना एक केश भी दिया. उन्होंने उदी और केश को एक ताबीज में रखा और उसे वह सदैव हाथ पर बांधते थे. अब अप्पा साहेब को उदी की शक्ति विदित हो चुकी थी. वह कुशाग्र बुद्धि के थे. पहले उन्हें 40 रुपये मासिक मिलते थे, लेकिन बाबा की उदी और चित्र मिलने के पश्चात उनका वेतन कई गुना हो गया तथा उन्हें मान और यश भी मिला. इसके अलावा उनकी आध्यात्मिक प्रगति भी शीघ्रता से होने लगी. इसलिए सौभाग्यवश जिनके पास उदी है, उन्हें स्नान करने के पश्चात उसे मस्तक पर धारण करना चाहिए और कुछ जल में मिलाकर ग्रहण करना चाहिए.

साई बाबा की पादुकाएं

यूं तो साई बाबा हर जगह विराजमान हैं, लेकिन समय समय पर वह कई जगहों पर अपनी उपस्थिति का अहसास दिलाते रहते हैं. ऐसी ही एक कहानी है मध्य प्रदेश के हरदा की. अपने एक भक्त से प्रसन्न होकर शिरडी के साई बाबा द्वारा उसे भेंट की गई चरण पादुकाएं आज भी यहां मौजूद हैं, जिनके दर्शन और पूजन के लिए सैकडों साई भक्त हर दिन कृष्णरावपरुलकर के निवास पर आते हैं.

साई भक्त कृष्णरावपरुलकर के पोते किशोर परुलकर ने बताया कि बाबा के जीवनकाल से ही उनके दादा कृष्णरावसाई के भक्त थे तथा रात दिन साई भक्ति में लीन रहते थे. साल में कई बार वह उनसे मिलने शिरडी जाया करते थे. उस दौर में आवागमन के अधिक साधन नहीं थे. शिरडी और हरदा के बीच दूरी भी लगभग 1000 किलोमीटर थी.

भक्त कृष्णराव ने अपनी यह परेशानी जब साई बाबा को बताई तो बाबा ने लगभग 93 वर्ष पूर्व सन 1915 में अपनी चरण पादुकाएं कृष्णराव को भेंट करते हुए कहा कि अब उन्हें बार-बार शिरडी आने की ज़रूरत नहीं रहेगी और जब तक ये पादुकाएं उसके पास रहेंगी, तब तक उसके घर में उनका वास रहेगा.

किशोर ने कहा कि तब से ही साई की ये पादुकाएं उनके घर में हैं तथा घर में लगातार यह महसूस होता रहता है, जैसे साई बाबा की वहां मौजूदगी है. यह संयोग ही है कि किशोर ने अपने जीवनकाल में अब तक घर में किसी प्रकार की बाधा अथवा परेशानी नहीं देखी. वह कहते हैं कि इन पादुकाओं का वह कोई प्रचार प्रसार नहीं चाहते, लेकिन फिर भी हर दिन सैकड़ों साई भक्त उनके घर आते हैं और वह उन्हें पादुकाओं के दर्शन अवश्य कराते हैं.

चौथी दुनिया ब्यूरो
feedback@chauthiduniya.com

मैंने कहा, भगवान शंकर मुझे बनारस बुला रहे हैं. अगले दिन ही मां चल बसी. उन्हें बर्दाश्त नहीं हुआ कि बेटा बनारस चला जाएगा. मैं बनारस गया, पढ़ाई की.

टोनी ब्लेयर की जर्नी

अनंत विजय

टोनी ब्लेयर ब्रिटेन के पहले ऐसे राजनेता थे, जो बग़ैर किसी सरकारी अनुभव के सीधे प्रधानमंत्री के पद पर आसीन हुए थे. वह ब्रिटेन के लंबे लोकतांत्रिक इतिहास के दूसरे प्रधानमंत्री थे, जिनके नेतृत्व में पार्टी ने आम चुनाव में लगातार तीसरी बार जीत हासिल की थी. इसके पहले यह गौरव सिर्फ़ मारग्रेट थैचर को मिला था. विश्व युद्ध के बाद लेबर पार्टी के नौ नेताओं में सिर्फ़ तीन ने आम चुनाव में जीत हासिल की, उनमें से भी टोनी ब्लेयर एक हैं. ब्रिटेन के राजनीतिक पंडित लेबर पार्टी में आमूलचूल बदलाव और सुधारों का श्रेय भी युवा टोनी ब्लेयर को ही देते हैं. उनके मुताबिक़, एक ऐसी पार्टी, जिसकी साख लगातार गिरती जा रही थी और जो मार्क्सवाद के हैंगओवर से जूझ रही थी, उसमें ब्लेयर ने नई जान फूंकी और उसे आधुनिक यूरोपीय विचारधारा के अनुरूप ढालने की न केवल कोशिश की, बल्कि उसमें सफलता भी पाई. टोनी के इस प्रयास को लोगों के समर्थन से बल भी मिला. इसके अलावा टोनी ने ब्रिटेन की अंतरराष्ट्रीय नीतियों में भी काफी बदलाव किए. इराक पर अमेरिका का साथ देने से लेकर अंतरराष्ट्रीय निशस्त्रीकरण के ब्रिटेन के भावुकता भरे पुराने स्टैंड को बदल कर एक ऐसा स्वरूप दिया, जो ज़्यादा देशों को स्वीकार्य हो सकता था. टोनी ब्लेयर ने 1994 में लेबर पार्टी की कमान संभाली और तीन साल के अंदर पार्टी में जो बदलाव किया, उसे लेकर वहां की जनता में एक उम्मीद जगी और 1997 में ब्लेयर को अपार जन समर्थन मिला, जो ब्रिटेन के इतिहास में अभूतपूर्व था. इसने वहां 18 साल के कंजरवेटिव पार्टी के शासन का अंत कर दिया.

इसलिए जब टोनी ब्लेयर ने अपनी आत्मकथा लिखने का ऐलान किया तो बताया जाता है कि प्रकाशक ने उन्हें बतौर अग्रिम राशि पांच मिलियन पौंड की राशि दी. इतनी बड़ी अग्रिम राशि प्रकाशन जगत की एक प्रमुख घटना थी. इसके बाद जब टोनी ब्लेयर की आत्मकथा–अ जर्नी प्रकाशित हुई तो पाठकों ने उसे हाथोंहाथ लिया और प्रकाशन के चार हफ्तों के अंदर उसके छह री–प्रिंट करने पड़े और देखते–देखते एक लाख से ज़्यादा प्रतियां बिक गईं. लेकिन यहां एक बात ग़ौर करने की है कि इस किताब के छपने से पहले उत्सुकता का एक वातावरण तैयार किया गया और प्रकाशक या फिर लेखक के रणनीतिकारों ने इस आत्मकथा के रस भरे प्रसंगों के चुनिंदा अंश लीक किए, वह भी जोरदार बिक्री का आधार बना. टोनी ब्लेयर को केंद्र में रखकर पहले भी कई किताबें प्रकाशित हो चुकी हैं. टोनी की पत्नी चेरी ब्लेयर की आत्मकथा तो पूरे तौर पर टोनी के इर्द–गिर्द ही घूमती है और उनकी ज़िंदगी के कई अनछुए पहलुओं को उद्घाटित करती है. इसके अलावा उनके सहयोगी एल्सटर कैंपबेल की भी किताब आई. उनके दूसरे सहयोगी पीटर मैंडलसन की किताब–द थर्ड मैन, लाइफ एट द हर्ट ऑफ न्यू लेबर तो कई हफ्तों तक ब्रिटेन के बेस्ट सेलर की सूची में शीर्ष पर रहकर लोकप्रियता और चर्चा दोनों हासिल कर चुकी थी. सिर्फ़ राजनीतिक ही नहीं, बल्कि टोनी एवं चेरी के व्यक्तिगत और अंतरंग संबंधों का भी पहले खुलासा हो चुका है. जैसे जब चेरी और टोनी क्वीन के स्कॉटिश कैसल बालमोर में छुट्टियां बिताने जा रहे थे तो चेरी वहां गर्भ निरोधक नहीं ले जा सकीं, क्योंकि उन्हें इस बात की शर्मिंदगी थी कि नौकर–चाकर इस तरह की चीजें उनके सामान में कैसे रखेंगे. नतीजा यह हुआ कि बालमोर में चेरी के गर्भ में उनकी चौथी संतान आ गई. इस तरह के कई और प्रसंग पहले से ज्ञात हैं, लेकिन टोनी के रणनीतिकारों ने इस किताब को इस तरह प्रचारित किया कि बाज़ार ने इसे हाथोंहाथ लिया. हिंदी के लेखकों और प्रकाशकों को इससे सीख लेनी चाहिए. तक़रीबन सात सौ पृष्ठों की इस आत्मकथा में टोनी ने राजनीति में अपने प्रवेश से लेकर समकालीन विश्व राजनेताओं के साथ अपने संबंधों का भी खुलासा किया है. इसके अलावा टोनी ने एक पूरा अध्याय ब्रिटेन की अपूर्व सुंदरी प्रिंसेस डायना पर भी लिखा है. डायना पर लिखे अध्याय में टोनी ने कहा है कि वह बेहद आकर्षक थीं. टोनी ने ख़ुद को डायना का ज़बरदस्त प्रशंसक बताया है. इस अध्याय में टोनी एवं डायना द्वारा साथ की गई भारत (कोलकाता), सउदी अरब और इटली आदि की यात्रा का भी उल्लेख है. टोनी लिखते हैं, डायना एक आइकॉन थी और संभवत: विश्व की सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध महिला भी, जिसके सबसे ज़्यादा फोटोग्राफ खींचे गए थे. वह अपने समय की एक ऐसी ख़ूबसूरत महिला थी, जो अपने संपर्क में आने वाले लोगों पर अपने व्यक्तित्व की अमिट छाप छोड़ती थी. पेरिस में सड़क हादसे में डायना की मृत्यु के बाद देश में उपजे हालात और अपनी मन:स्थिति का भी विवरण टोनी ने पेश किया है.

दरअसल टोनी ने अपनी इस आत्मकथा को कालक्रम के हिसाब से

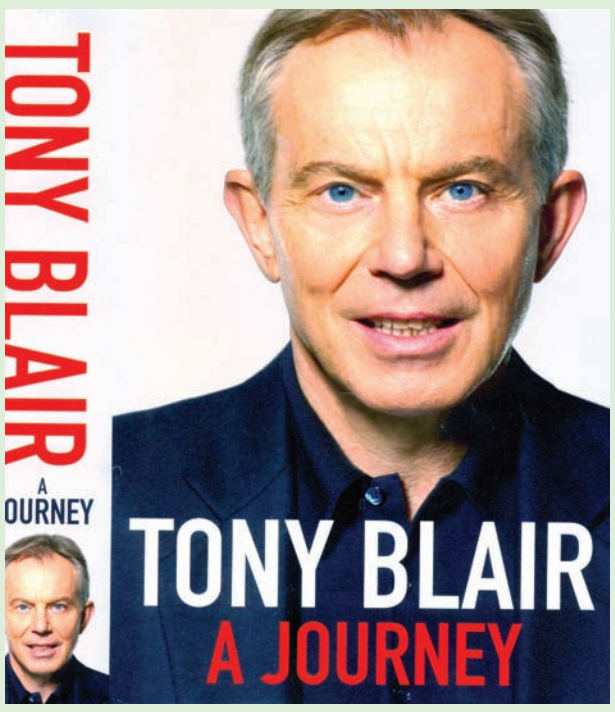

नहीं लिखा है. उन्होंने हर अध्याय को एक थीम दी है. नतीजा यह हुआ कि पूरी किताब में एक भ्रम की स्थिति बनती नज़र आती है. सांप–सीढ़ी के खेल की तरह संस्मरण भी भटकता नज़र आता है. इसके अलावा टोनी की जो भाषा है, वह भी आकर्षक नहीं है. उन्होंने सामान्य बोलचाल की भाषा उठाकर लिख दी है, जिसे लेकर पश्चिम के विद्वानों ने उनकी ख़ूब लानत–मलामत की है. चार्ल्स मूर ने कहा कि यह किताब बेहद अनाकर्षक ढंग से लिखी गई है. इसमें ऐसे वाक्यों की भरमार है, जिनमें अंग्रेजी के सामान्य व्याकरण का भी पालन नहीं किया गया. ऐसे जुमलों का प्रयोग किया गया है, जो सुनने में तो बेहतर लगते हैं, लेकिन छपकर बेहद हास्यास्पद.

टोनी ब्लेयर एवं उनके सहयोगी गॉर्डन ब्राउन के संबंधों को लेकर बहुत ज़्यादा लिखा और कहा जा चुका है. इन संबंधों पर टोनी ने विस्तार से प्रकाश डाला है और कहीं–कहीं दकियानूसी कहकर ब्राउन का मज़ाक भी उड़ाया है. टोनी के कार्यकाल में उनका सबसे विवादास्पद निर्णय रहा इराक पर हमले के लिए अमेरिका के नेतृत्व वाले 34 देशों के गठबंधन को समर्थन देना. टोनी ब्लेयर के लिए इस गठबंधन से दूर रहना आसान था. तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति जॉर्ज बुश ने टोनी से कहा भी था कि वह लंदन की मजबूरी समझ सकते हैं. टोनी ब्लेयर के सामने अपने पूर्ववर्ती प्रधानमंत्री हेरॉल्ड विल्सन का उदाहरण भी था, जिन्होंने 1964 में वियतनाम युद्ध में अमेरिका को ब्रिटेन का समर्थन देने से इंकार कर दिया था, लेकिन ब्लेयर ने लिखा है कि उन्हें यह लगा कि इराक में बाथ पार्टी की ज़्यादतियों का अंत होना चाहिए, इस वजह से उन्होंने अमेरिका का समर्थन किया. यह किताब आने के बाद टोनी के कई आलोचकों ने उन पर जमकर हमले किए. उनका तर्क है कि जब इराक पर हमले में ब्रिटेन द्वारा अमेरिका का साथ देने की जांच की जा रही है तो इस बीच उन स्थितियों के खुलासे का कोई अर्थ नहीं है. किताब के आख़िरी पृष्ठों में ब्लेयर ने लिखा है, मेरी हमेशा से राजनीति की तुलना में धर्म में ज़्यादा रुचि रही है. इस एक वाक्य के अलावा पूरी किताब में धर्म के बारे में ब्रिटेन के पूर्व प्रधानमंत्री ने न तो कुछ लिखा है और न यह बताया कि उनके हर दिन के फ़ैसलों और बड़े रणनीतिक निर्णयों को धर्म कैसे प्रभावित करता है. जो व्यक्ति यह कह रहा हो कि उसे धर्म में राजनीति से ज़्यादा रुचि है, उसकी जीवन यात्रा में धर्म का उल्लेख न मिलना हैरान करने वाला है. इसी तरह टोनी ने अपनी किताब में तेरह जगहों पर भारत का उल्लेख किया है, लेकिन कहीं भी गंभीरता से कुछ भी नहीं लिखा. लगता है, टोनी के एजेंडे में भारत था ही नहीं. लेकिन जहां लोकतंत्र और लोकतांत्रिक परंपराओं की बात आती है तो टोनी भारत का उदाहरण देते हुए कहते हैं कि लोकतंत्र सबसे बेहतर शासन पद्धति है और भारत इसका सबसे बेहतरीन उदाहरण है, जहां सर्वोत्तम रूप से लोकतंत्र कायम है. इस तरह की टिप्पणियों से टोनी ब्लेयर की जर्नी की गंभीरता ख़त्म होती है. पूरी किताब पढ़ने के बाद निष्कर्ष यह निकला कि टोनी ब्लेयर की यह आत्मकथा दरअसल उनके प्रधानमंत्रित्व काल का दस्तावेजीकरण है, लेकिन इसमें उन्होंने अपनी राजनीतिक बदमाशियों का जो जिक्र किया है, उसकी वजह से इस भारी–भरकम किताब में थोड़ी रोचकता और पठनीयता बनी रहती है.

(लेखक आईबीएन–7 से जुड़े हैं)
anant.ibn@gmail.com

पुस्तक अंश मुन्नी मोबाइल

गतांक से आगे

प्रदीप सौरभ

बस खिसक रही थी. आने वाले हर ऐतिहासिक और सामान्य, किंतु ज़रूरी जगह के बारे में विस्तार से बताया जा रहा था. विक्टोरिया स्टेशन, हाइड पार्क, लंदन म्यूज़ियम, लंदन आई, टावर ब्रिज, ऑक्सफोर्ड सर्कस, हाउस ऑफ पार्लियामेंट, न जाने कौन–कौन सी जगह से बस गुजर रही थी. सब कुछ सुंदर और अद्भुत.

ऑक्सफोर्ड रोड नाइट शापिंग के लिए मशहूर है. यहां बड़े–बड़े शोरूम हैं. इलीट एरिया है यह लंदन का. रीजेंट स्ट्रीट पर दुनिया की सबसे बड़ी खिलौनों की दुकान है. थोड़ी दूर पर ही लंदन का सबसे पुराना भारतीय रेस्त्रां है दुराईस्वामी. शायद कोई दक्षिण भारतीय इसे चलाता है, तभी इसका नाम दुराईस्वामी है. आनंद भारती के कान में अचानक गूंजता है, कैफे रायल. बताया जाता है कि आस्कर वाइल्ड अपनी शाम इसी कैफे में गुजारते थे.

ओल्ड लंदन से गुजरते हुए यह एहसास हो रहा था कि वे उसी समय में आ गए हैं. कुछ भी नहीं बदला था. अंग्रेजों ने लैंपपोस्ट से लेकर सिनेमा की पुरानी होल्डिंग्स तक सब कुछ जस की तस संजो रखी थी. उसी जमाने की इमारतें, वैसी ही सड़कें, पुराने स्टेशन. ऐसा लग रहा था कि यह हिस्सा लंदन का है ही नहीं. न्यू लंदन की गगनचुंबी इमारतें और लकदक रोशनी यहां नहीं थीं. लैंपपोस्ट पर पुराने जमाने के बल्ब जल रहे थे. इस मामले में अंग्रेजों की तारीफ़ करनी चाहिए कि वे अपनी परंपरा से ज़बरदस्त प्यार करते हैं. ओल्ड लंदन उसी चाहत का एक नमूना था. बस में बैठे–बैठे आनंद भारती को भूख लग आई थी. उन्होंने इंद्राणी मजूमदार के सामने पिकाडली सर्कस में बस छोड़ने का प्रस्ताव रखा. उसने उसे सहर्ष स्वीकार कर लिया. दोनों पिकाडली सर्कस में उतर गए. थोड़ी दूर पर उन्हें बर्गर की एक शॉप दिखी. खासी भीड़ थी. आनंद भारती ने दो

बर्गर ख़रीदे और दोनों खाते हुए आगे बढ़ने लगे. बड़े–बड़े शोरूम थे चारों तरफ़ . रोशनी से नहाए. बाज़ार में खासी भीड़ थी. क्रिसमस आने वाला था. हर शख्स ख़रीदारी में व्यस्त था. कई जगह सेल भी लगी थी. ऐसी ही एक दुकान में दोनों घुस गए. सेल्समैन इंडियन लग रहा था. पूछने पर उसने बताया कि वह चेन्नई का है. हिंदी बोलकर वह दोनों से अपना भाईचारा स्थापित कर रहा था. आनंद भारती ने एक मफलर पसंद किया. वह था तो साढ़े छह पाउंड का, लेकिन उसने उसे पांच पाउंड में ही दे दिया.पिकाडली सर्कस मेट्रो स्टेशन के बाहर दोनों खड़े थे. हाल में आतंकी हमले ने मेट्रो यात्रा पर प्रभाव डाला था. व्यस्ततम स्टेशन होने के बावजूद भीड़ ज़्यादा नहीं थी. यात्रियों में आतंकी ख़ौफ़ दबे–दबे दिख रहा था. आने–जाने वाले सभी यात्री दोनों को खास नज़रों से देख रहे थे. वे दोनों में कुछ ढूंढ रहे थे, लेकिन दोनों बेलौस बढ़ते जा रहे थे. मेट्रो स्टेशन की गैलरी में एक लड़की गिटार और उसी स्टैंड पर माउथ आर्गन लगाकर गा रही थी. बारी–बारी वह गिटार और माउथ आर्गन दोनों बजाती थी. अच्छा गा रही थी. आने–जाने वाले उसके सामने बिछे स्कार्फ में कुछ सिक्के डाल कर आगे बढ़ जाते थे. देसी भाषा में उसे भिखारी ही कहा जा सकता था. ऐसा नज़ारा लंदन मेट्रो में आम है. ट्रेन आ चुकी थी. ट्रेन में बैठकर दोनों होटल के नज़दीक स्टेशन पर उतर गए. स्टेशन से बाहर आते ही एक बुजुर्ग आनंद भारती के सामने आकर बोला, गिव मी सम क्वाइन. यह पहला पक्का भिखारी उन्हें मिला था. वे उसकी उपेक्षा कर आगे बढ़ गए. लंदन में चौराहों से लेकर मेट्रो स्टेशन तक हर जगह भिखारियों के दर्शन हो जाते हैं. कोई सिगरेट देकर पैसे मांगता है तो कोई दया के नाम पर....तीन–चार दिन लंदन में बीत चुके थे. दाल–रोटी की ललक आनंद भारती को लग रही थी. जोशी लंदन से काफी दूर रहता था, इसलिए उनसे भारतीय खाने का वह आग्रह नहीं कर सकता था. सेंट्रल लंदन से अच्छी–खासी दूरी पर साउथ हाल है. उसे मिनी इंडिया भी कहा जाता है. साउथ हाल में दाल–भात क्या, छोले–भटूरे से लेकर पूड़ी–भाजी तक सब मिलता है. दिल्ली के करोल बाग जैसा दृश्य है. पटरी पर सामान भी बिकते हुए देखा जा सकता है. पान का शौक हो तो एक पान की दुकान है. एक नया गुरुद्वारा भी बन गया है. कई लोग तो ऐसे हैं, जो वहां रहते हैं और तीनों वक़्त नाश्ते से लेकर डिनर तक वहीं करते हैं. वह भी मुफ्त, लेकिन दूरी के चलते वहां जाना संभव नहीं था.

अगले अंक में जारी...

पद्मश्री आचार्य जानकी वल्लभ शास्त्री

तिमिर गरल पिया अमृत भोर के लिए

प्रमुख सम्मान

पद्मश्री, राजेंद्र शिखर सम्मान, भारत भारती एवं शिव पूजन सहाय सम्मान.

प्रमुख कृतियां

रूप–अरूप, मेघगीत, पशानी, तमाशा, कानन, अर्पण, तीर–तरंग, अवंतिका, शिवा, राधा, हंस बलाका, कर्मक्षेत्रे–मरुक्षेत्रे, श्यामा संगीत एवं धूपतरी.

महाकवि आचार्य जानकी वल्लभ शास्त्री का साहित्य एक सुषुप्त ज्वालामुखी है, जो एक न एक दिन जनसामान्य को उद्वेलित करेगा. महाकाव्य राधा, चाणक्य एवं कालीदास जैसे उपन्यास और रूप–अरूप, तीर–तरंग, शिवा, मेघगीत, अवंतिका, कानन एवं अर्पण आदि काव्य संग्रहों के रचयिता और पद्मश्री सम्मान प्राप्त महाकवि जानकी वल्लभ शास्त्री की समस्त जीवन साधना ही उनकी साहित्य सर्जना है. उन्होंने अपनी लेखनी को किसी की बंदिनी नहीं बनने दिया. चाहे वह रायगढ़ का राज दरबार हो या मुज़फ़्फ़रपुर का राजसी संसार. भाव प्रवण एवं भाषा के प्रणेता शास्त्री जी ने सदैव अपने साहित्य में अपने जीवन को प्रतिबिंबित किया है, निचोड़ा है. भले ही वह रूप–अरूप हो या तीर–तरंग, हंस बलाका हो या कर्मक्षेत्रे–मरुक्षेत्रे एवं श्यामा संगीत हो या फिर धूपतरी. धूपतरी में उन्होंने लिखा भी है, ***ज़िंदगी निचोड़ दी अछोर के लिए, तिमिर गरल पिया अमृत भोर के लिए.***

इसी साल यानी 2010 में भारत सरकार ने आचार्य जानकी वल्लभ शास्त्री को पद्मश्री देकर सम्मानित किया है. वर्ष 1916 में बिहार के गया ज़िले के ग्राम मैगरा में जन्मे छायावादोत्तर काल के सुविख्यात कवि जानकी वल्लभ को उत्तर प्रदेश सरकार भी भारत भारती सम्मान से सम्मानित कर चुकी है. आचार्य का काव्य संसार विविध और व्यापक है. प्रारंभ में उन्होंने संस्कृत में कविताएं लिखीं, फिर महाकवि निराला की प्रेरणा से हिंदी साहित्य संसार में आए. कविता के क्षेत्र में उन्होंने कुछ सीमित प्रयोग भी किए और चालीस के दशक में कई छंदबद्ध काव्य कथाएं लिखीं, जो गाथा नामक संग्रह में संकलित हैं. इसके अलावा कई काव्य नाटकों की रचना की और राधा जैसा श्रेष्ठ महाकाव्य रचा. शास्त्री जी की सृजनात्मक प्रतिभा अपने सर्वोत्तम रूप में गीतों एवं ग़ज़लों में दिखती है. इस क्षेत्र में उन्होंने कई नए प्रयोग किए, जिससे हिंदी गीतों का दायरा व्यापक हुआ. वह न तो नवगीत जैसे किसी आंदोलन से जुड़े, न प्रयोग के नाम पर उन्होंने ताल–तुक आदि से खिलवाड़ किया. छंदों पर उनकी पकड़ ज़बरदस्त है और तुक भी अत्यंत सहज ढंग से उनकी कविता में आते हैं. केवल वह ही निराला की ऊंचाई को छू पाते हैं. शास्त्री जी लिखते हैं, मैंने ईश्वर से की है बातचीत. ईश्वर के सामने कोई बुद्धिमानी काम नहीं आती. ईश्वर समर्पण खोजता है, सहजता खोजता है. सहजता और समर्पण के साथ जो अपने उद्देश्यों को पूरा करने में लगा रहता है, ईश्वर हमेशा उसके साथ होता है. मैं पांच वर्ष का था, घर के आंगन में मंदिर के सामने पूजा कर रहा था. मां बोली, क्या कर रहे हो? मैंने कहा, भगवान शंकर मुझे बनारस बुला रहे हैं. अगले दिन ही मां चल बसी. उन्हें बर्दाश्त नहीं हुआ कि बेटा बनारस चला जाएगा. मैं बनारस गया, पढ़ाई की. रायगढ़ के राजा प्रभावित थे. उन्होंने मुझे राजकवि का सम्मान दिया. एक दिन गंगा पार करके पटना से मुज़फ़्फ़रपुर आ गया. यहीं पटना में बन गया प्रोफेसर. सेवानिवृत्ति के बाद फिर मुज़फ़्फ़रपुर आ गया और यहीं का होकर रह गया. शास्त्री जी एक जगह लिखते हैं,

ज़िंदगी की कहानी रही अनकही, दिन गुजरते रहे सांस चलती रही, अर्थ क्या शब्द ही अनमने रह गए, कोष से जो खिंचे तो तने रह गए, वेदना अश्रु–पानी बनी बह गई, धूप ढलती रही छांह छलती रही.

वह बताते हैं, मैंने अपनी ज़िंदगी में कितनी ही उमंगों एवं तरंगों को देखा और उन्हीं के साथ समय गुजारा. मैंने संघर्ष में ही सारी उम्र गुजार दी. जहां पैदा हुआ, वह विकास से कोसों दूर जंगली इलाक़ा था. 11 वर्ष की आयु में ही मैंने अपना घर छोड़ दिया था. पृथ्वीराज कपूर, राजकपूर, राम मनोहर लोहिया, जय प्रकाश नारायण और कई बड़ी–बड़ी हस्तियों ने आचार्य जी का सान्निध्य पाकर ख़ुद को गौरवांवित महसूस किया. बिहार राजभाषा परिषद की ओर से आचार्य शिवपूजन सहाय पुरस्कार के रूप में शास्त्री जी को एक लाख रुपये दिए गए थे. विधान परिषद के तत्कालीन सभापति जाबिर हुसैन ने यह पुरस्कार ख़ुद मुज़फ़्फ़रपुर आकर उन्हें प्रदान किया था. आचार्य जी के दिशा निर्देशन में 100 से अधिक लोगों ने पीएचडी की, लेकिन अधिकांश उन्हें भूल गए.

बिहार की बदहाली पर दु:ख व्यक्त करते हुए वह कहते हैं कि जहां गौतम बुद्ध एवं स्वामी महावीर आदि ने सत्य–अहिंसा का पाठ पढ़ाया था, वहां आज अपराधियों का बोलबाला हो गया है. जीवन के 94 वसंत देख चुके इस साल जब पद्मश्री सम्मान के उनके नाम की घोषणा हुई तो उन्होंने इसे लेने से इंकार कर दिया. आचार्य जी ने कहा, बरसों से कोई मेरी सुधि लेने नहीं आया. सच्चे साहित्यकार को सम्मान की भूख नहीं होती, लेकिन उपेक्षा का दंश उसे हमेशा सालता रहता है. परिवार के लोगों को भी लगता है कि आचार्य जी को कम से कम पद्मभूषण तो मिलना ही चाहिए था. बाद में सरकार के मनाने पर उन्होंने सम्मान ग्रहण कर लिया. महाकवि शास्त्री हिंदी और संस्कृत के प्रकांड विद्वान हैं. साहित्यकारों की कई पीढ़ियों ने उनके आंगन में आश्रय पाया. महाकवि से कनिष्ठ कई लोगों को पद्मश्री से बड़े पुरस्कार मिल चुके हैं. ऐसे में शास्त्री जी का दर्द जायज़ है. उन्होंने अपनी पीड़ा बयान करते हुए एक जगह लिखा भी है,

मेरा नाम पुकार रहे हो तुम
अपना नाम छिपाने को,
सहज सजा मैं साज तुम्हारा
दर्द बजा जब भी झनकारा,
पुरस्कार देते हो मुझको
अपना काम छिपाने को,
मैं जब–जब जिस पथ पर चलता
दीप तुम्हारा दिखता जलता,
मेरी राह दिखा देते तुम
अपना धाम छिपाने को.

त्रिलोक कुमार झा
feedback@chauthiduniya.com

चांदनी चौक स्थित रियांशा साड़ीज ने बॉलीवुड अदाकारा सोनल चौहान द्वारा उद्घाटन कराकर अपना नया कलेक्शन पेश किया.

बार्बी डॉल का नया रूप कैटरीना

बार्बी डॉल पेश करने के लिए ख़ुद कैटरीना कैफ आगे आईं. इस अवसर पर उन्होंने कहा कि बार्बी डॉल आज़ादी, क्रिएटिविटी और स्टाइल का संगम है, जो कैटरीना एवं बार्बी की पर्सनालिटी का हिस्सा हैं.

खिलौना बनाने वाली भारतीय कंपनी मैटेल ने हाल में बच्चों के लिए एक नया और आकर्षक खिलौना तैयार किया है. बॉलीवुड की बार्बी डॉल कैटरीना कैफ की तर्ज पर कंपनी ने बच्चों के खेलने वाली बार्बी डॉल बनाई है. कंपनी ने यह खास डॉल बार्बी की 50वीं वर्षगांठ पर बतौर तोहफा नन्हीं बच्चियों के लिए पेश किया है. यह बार्बी डॉल पेश करने के लिए ख़ुद कैटरीना कैफ आगे आईं. इस अवसर पर उन्होंने कहा कि बार्बी डॉल आज़ादी, क्रिएटिविटी और स्टाइल का संगम है, जो कैटरीना एवं बार्बी की पर्सनालिटी का हिस्सा हैं. इस खिलौने को ठीक वैसी ही ड्रेस पहनाई गई है, जैसी कैटरीना कैफ ने 2009 के लक्मे फैशन वीक में फैशन शो के दौरान पहनी थी. कैटरीना की इस ड्रेस का पूरे विश्व में सिर्फ़ एक पीस बनाया गया था, इसे तैयार करने वाले ड्रेस डिज़ाइनर विश्व प्रसिद्ध निवक्षा लुल्ला थे. उसी ड्रेस जैसी वेल फिटेड बॉडीस में बार्बी को बेहद ख़ूबसूरत बनाया गया है. बार्बी की लेयर्ड ब्राइट कलर ब्रोकेड स्कर्ट में गोल्डन ट्रिमिंग की गई है, जो उसकी ड्रेस को बेहद ख़ूबसूरत लुक देती है. मिस बार्बी की कमर पर बंधी ख़ूबसूरत बेल्ट पर स्वारोस्की क्रिस्टल भी लगे हैं. बार्बी की इस ड्रेस के लिए टियारा डॉल को चुना गया है.

खास है यह प्रोडक्ट

ये वॉलेट वाटर रेसिस्टेंट और काफी हल्के हैं. इनमें आसानी से हर तरह के प्लास्टिक एवं मेटालिक कार्ड और पैसे आ जाएंगे. फेडिंग और चिपिंग से बचाने के लिए इनमें मेटालिक कलरिंग की गई है, इनकी क़ीमत 1799 रुपये है.

शादियों के इस सीजन में लिवटेक इंडिया ने स्टाइलिश लाइफ स्टाइल प्रोडक्ट की नई रेंज बाज़ार में उतारी है. कंपनी ने पुरुषों के लिए मनी वॉलेट, पेन और वर्क ऑर्गनाइज़र जैसी चीजें पेश की हैं. फ्रांस, इटली, अमेरिका और यूके से लाए गए उक्त प्रोडक्ट लक्ज़री की निशानी भी हैं. इन्हें बतौर तोहफा दिया जा सकता है और निजी इस्तेमाल के लिए भी ख़रीदा जा सकता है. डार्क ग्रे, ब्लैक, गोल्ड, सिल्वर, ब्लू, ग्रीन लाइम, रेड, ऑरेंज, परपल और चॉकलेट जैसे ख़ूबसूरत दस रंगों में उपलब्ध ओगन वॉलेट के डिज़ाइन स्वीडन में तैयार किए गए हैं और इन्हें फ्रांस में बनाया गया है. ये वॉलेट वाटर रेसिस्टेंट और काफी हल्के हैं. इनमें आसानी से हर तरह के प्लास्टिक एवं मेटालिक कार्ड और पैसे आ जाएंगे. फेडिंग और चिपिंग से बचाने के लिए इनमें मेटालिक कलरिंग की गई है, इनकी क़ीमत 1799 रुपये है. हैंड क्राफ्टेड मोंटवर्ड पेन यूरोपियन ग्रेड के एक्रेलिक रेसिन और कार्बन फाइबर पेन है. अमेरिका के मोंटवर्ड को दुनिया में नायाब पेनों के निर्माता के रूप में जाना जाता है. इस कंपनी के कुछ खास स्टाइलिश और रॉयल पेन कई रंगों–डिज़ाइनों में उपलब्ध होंगे. भारत में इसके लिमिटेड एडिशन में फैंटेसिया और स्लीपिंग ब्यूटी पेन खास हैं, जिनकी क़ीमत 2,599 से लेकर 10,000 रुपये तक है. यूके की फिलफैक्स पर्सनल ऑर्गनाइजर्स बनाने वाली कंपनी है. फाइन इटालियन लेदर, माइक्रो फाइबर और अन्य टेक्सचर्स मैटेरियल के इस्तेमाल से तैयार होने वाले ऑर्गनाइजर्स अलग–अलग साइज़ों एवं रंगों में उपलब्ध हैं. मिनी, पॉकेट, स्लिम लाइन, पर्सनल, ए–5 और ए–4 साइज में मिलने वाले ये ऑर्गनाइजर्स टैन, ब्राउन, ब्लैक, रेड, इंडिगो, ऑरेंज एवं ब्लू आदि रंगों में उपलब्ध हैं. इनकी क़ीमत 1399 से लेकर 4999 रुपये तक है. ये देश के सभी खास गिफ्ट और लाइफ स्टाइल स्टोरों में उपलब्ध हैं.

चौथी दुनिया ब्यूरो
feedback@chauthiduniya.com

गोदरेज का इओन डिगी फ्रेश रेफ्रिजरेटर

गोदरेज एप्लाइंसेज ने इओन फ्रेश रेफ्रिजरेटर्स के लांच के साथ रेफ्रिजरेशन कंट्रोल को एक पूर्णतः नया स्वरूप प्रदान किया है. यह तकनीक रेफ्रिजरेशन के स्तर को आवश्यकतानुसार सेट करने और बदलने में सहायक होगी. गोदरेज एप्लाइंसेज ने रेफ्रिजरेटर में विकसित तकनीक की आवश्यकता महसूस की और इसकी पूर्ति करते हुए इओन डिगी फ्रेश रेफ्रिजरेटर लांच किया. गोदरेज इओन डिगी फ्रेश रेफ्रिजरेटर्स फ्रीजर डोर एवं स्वच्छ डिजिटल पैनल्स के साथ पेश किए गए हैं, जो अंदर से इन पर नियंत्रण रखते हैं. यह टच कंट्रोल तकनीक आपको अपनी आवश्यकतानुसार शीतलता (रेफ्रिजरेशन) के स्तर को देखने, सेट और परिवर्तित करने की सुविधा प्रदान करती है. इसके लिए आवश्यकता है सिर्फ़ बाहर से स्पर्श कर इसके इंटीरियर का प्रबंधन करने की. गोदरेज रेफ्रिजरेटर्स की इओन डिगी फ्रेश रेंज में यह नया विकास आपकी आशाओं के अनुकूल है, जिसके इस्तेमाल से आप अपने रसोई घर को आधुनिकता की ऊंचाइयों पर ले जा सकते हैं.

गोदरेज इओन डिगी फ्रेश रेफ्रिजरेटर की मुख्य विशेषताओं में कूल लेवल, चाइल्ड लॉक, कूल टाइमर, हॉली डे मोड आदि हैं. कूल लेवल अपनी ज़रूरत के अनुसार 7 प्रीसेट कूलिंग लेवल का चयन करने में मदद करता है. तेज कूलिंग के लिए आप टर्बो चिल का प्रयोग कर सकते हैं. चाइल्ड लॉक के तहत एक सरल सा बटन यह सुनिश्चित करता है कि आपके रेफ्रिजरेटर के साथ कोई खिलवाड़ नहीं कर सकता. कूल टाइमर से आप डिजिटल पैनल पर एक रिमाइंडर अलॉर्म भी सेट कर सकते हैं. हॉली डे मोड न्यूनतम एनर्जी मोड है, जिसके तहत आप छुट्टियों पर जाने के वक़्त रेफ्रिजरेटर को ऑन छोड़ सकते हैं. ये सब एक स्लीक डिजिटल पैनल पर दिए गए हैं. वहीं आई फ्रेश टेक्नोलॉजी अंदर रखे हुए खाद्य पदार्थों की ताज़गी लंबे समय तक बरक़रार रखती है. इसके लिए शेल्व के अंदर सिल्वर शॉवर टेक्नोलॉजी, स्पेशल सिल्वर फ्रेश जोन्स, पैलेडियम आधारित अरोमा लॉक एवं एक एफआईआर आधारित न्यूट्रा लैंप दिए गए हैं. 330 लीटर की क्षमता में उपलब्ध एक आकर्षक शेल वाइन रेड पैटर्न एवं 5 स्टार एनर्जी रेटिंग वाला यह रेफ्रिजरेटर कई विशेषताओं एवं आधुनिकतम तकनीक से युक्त है. इसकी क़ीमत 28,640 रुपये है.

परिधानों के नए कलेक्शन

रियांशा कलेक्शन के परिधानों में हाथ की कढ़ाई वाली साड़ियां और लहंगे शामिल हैं. सोनल चौहान ने कहा कि चांदनी चौक की गलियों में वह सेलिब्रिटी बनने से पहले भी आया करती थीं.

शादियों का मौसम हो और परिधानों के बाज़ार में हलचल न हो, यह संभव नहीं है. पूरे विश्व में प्रसिद्ध चांदनी चौक की दुकानें नई–नई राजसी पोशाकों से सज गई हैं. दुकानदार ग्राहकों को लुभाने के लिए नए–नए तरीक़े अपनाने लगे हैं. इन दिनों चांदनी चौक की दुकानों की रौनक देखते ही बनती है. चांदनी चौक स्थित रियांशा साड़ीज ने बॉलीवुड अदाकारा सोनल चौहान द्वारा उद्घाटन कराकर अपना नया कलेक्शन पेश किया. रियांशा साड़ीज लखनऊ की प्रसिद्ध साड़ियां तैयार कराने वाली कंपनियों में से एक है. रियांशा कलेक्शन के परिधानों में हाथ की कढ़ाई वाली साड़ियां और लहंगे शामिल हैं. सोनल चौहान ने कहा कि चांदनी चौक की गलियों में वह सेलिब्रिटी बनने से पहले भी आया करती थीं, आज बतौर सेलिब्रिटी यहां आना उनके लिए एक अनोखा अनुभव है. उन्होंने रियांशा कलेक्शन की तारीफ़ करते हुए कहा कि यहां हर उम्र की महिलाओं के लिए मौजूद परिधान काफी आकर्षक और ट्रेंडी हैं, खासकर साड़ियों का कलेक्शन.

रियांशा के निर्देशक अनिल अरोड़ा ने बताया कि राजधानी दिल्ली में यह उनका पहला शोरूम है, जो ग्राहकों की सभी ज़रूरतों को पूरा करने की कोशिश करेगा. यहां साड़ियों की क़ीमत की शुरुआत 650 रुपये से होती है. उन्होंने कहा कि वह पारंपरिक वस्त्र पसंद करने और पहनने वाले लोगों के लिए रियांशा के कलेक्शन में समय–समय पर नए–नए ट्रेंड अपनाते रहेंगे, जिससे उनके परिधान कंटेंपररी बने रहें.

विज्ञापन हेतु संपर्क करें : email : advt@chauthiduniya.com

साल 2010 उनके लिए अच्छे परिणाम लेकर आया है और उनसे उम्मीदें भी बढ़ गई हैं, लेकिन वह किसी जल्दी में नहीं हैं.

भारतीय टेनिस का नया सूर्य सोमदेव

पहले राष्ट्रमंडल खेल में सिंगल्स का स्वर्ण पदक और फिर एशियाई खेलों में सिंगल्स और डबल्स में दोहरा स्वर्ण पदक, सोमदेव देवबर्मन भारतीय टेनिस के लिए नई उम्मीद बन कर आए हैं, लेकिन उन्हें अभी लंबा सफ़र तय करना है.

भारत में टेनिस के खेल की एक खासियत रही है. यहां ऐसे खिलाड़ी कम ही पैदा हुए हैं, जो विश्व स्तर पर देश का नाम रोशन कर सकें, लेकिन हर दौर में कम से कम एक खिलाड़ी ज़रूर रहा है, जो अपनी उपलब्धियों से हमें गौरव का एहसास कराता रहा है. पहले रामनाथ कृष्णन, फिर रमेश कृष्णन एवं विजय अमृतराज और उसके बाद लिएंडर पेस एवं महेश भूपति. बीच में सानिया मिर्ज़ा भी आईं, लेकिन उनकी उम्मीदों का सितारा चमकने से पहले ही रास्ते से भटक गया. अब जबकि लिएंडर पेस एवं महेश भूपति अपने करियर के आख़िरी पड़ाव पर हैं, सानिया कोर्ट से ज़्यादा अपना परिवार बसाने में व्यस्त हैं, ऐसे में भारतीय टेनिस प्रेमियों के दिल में एक ही सवाल कौंध रहा था कि अंतरराष्ट्रीय टेनिस में भारत का अगला झंडाबरदार कौन होगा? पिछले एक साल के प्रदर्शन पर ग़ौर करें तो सोमदेव देवबर्मन ने एक नई उम्मीद पैदा की है. हालांकि एटीपी रैंकिंग में वह अभी भी टॉप 100 से बाहर हैं, लेकिन हाल के दिनों में अंतरराष्ट्रीय टूर्नामेंटों और खासकर कॉमनवेल्थ एवं एशियाई खेलों में उनके प्रदर्शन को देखते हुए यह आशा की जा सकती है कि आने वाले दिनों में भारतीय टेनिस नायकविहीन नहीं रहेगा.

25 वर्षीय सोमदेव देवबर्मन को टेनिस जगत में पहली बार ख्याति तब मिली, जब वह अमेरिका के यूनिवर्सिटी ऑफ वर्जीनिया में लगातार तीन बार एनसीएए सिंगल्स चैंपियनशिप में जगह बनाने में कामयाब रहे और लगातार दो बार खिताब अपने नाम किया. टूर्नामेंट के 124 सालों के इतिहास में यह उपलब्धि हासिल करने वाले वह केवल तेरहवें खिलाड़ी थे. पेशेवर टेनिस में उनका पहला पड़ाव न्यूयॉर्क का रोसेस्टर फ्यूचर्स टूर्नामेंट था, जिसमें सिंगल्स और डबल्स (ट्रीट हुई के साथ मिलकर) खिताब उन्होंने जीता. इसके एक सप्ताह बाद ही पिट्सबर्ग फ्यूचर्स टूर्नामेंट में भी वह सिंगल्स और डबल्स चैंपियन बने. साल 2009 के चेन्नई ओपन में वह पहली बार किसी एटीपी टूर्नामेंट के फाइनल में पहुंचने में कामयाब रहे, हालांकि खिताबी मुक़ाबले में उन्हें क्रोशिया के मारिन सिलिक से मात खानी पड़ी. इसके बाद साल 2009 के अधिकांश टूर्नामेंटों में उनका प्रदर्शन उम्मीदों पर खरा नहीं उतर पाया. अधिकांश ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंटों तो वह मुख्य ड्रॉ में भी जगह नहीं बना पाए. साल 2010 की शुरुआत भी उनके लिए कुछ खास नहीं रही. फ्रेंच ओपन और यूएस ओपन के पहले राउंड में ही उन्हें पराजित होना पड़ा, हालांकि जोहान्सबर्ग में हुए साउथ अफ़्रीका ओपन के क्वार्टर फाइनल तक पहुंचने में वह सफल रहे.

सोमदेव के खेल का असली रंग तब देखने को मिलता है, जब वह भारत का प्रतिनिधित्व कर रहे होते हैं. इसकी पहली झलक 2009 के डेविस कप में देखने को मिली, जब उन्होंने चाइनीज ताइपे के ख़िलाफ़ भारत को जीत दिलाने में अहम भूमिका निभाई. इस मुक़ाबले के रिवर्स सिंगल्स में उन्होंने एटीपी रैंकिंग में 59वें स्थान के खिलाड़ी येन हसून लू को हराया. साल 2010 में ब्राजील के ख़िलाफ़ डेविस कप मुक़ाबले में भारतीय टीम की जीत में भी उन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई. इस साल अक्टूबर में हुए राष्ट्रमंडल खेलों की सिंगल्स स्पर्धा में उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के ग्रेग जोन्स को सीधे सेटों में हराकर स्वर्ण पदक जीता. उनकी इस जीत को ज़्यादा अहमियत नहीं दी गई, क्योंकि शीर्ष स्तर के अधिकांश खिलाड़ी इन खेलों से नदारद थे. लेकिन सोमदेव ने इसकी कसर ग्वांगझू में हुए एशियाई खेलों में दोहरा स्वर्ण पदक जीतकर पूरी कर दी. उन्होंने पहले सनम सिंह के साथ मिलकर पुरुष डबल्स का स्वर्ण पदक जीता और इसके अगले ही दिन उजबेकिस्तान के डेनिस इस्तोमिन को हराकर सिंगल्स का स्वर्ण पदक भी अपने नाम कर लिया. एशियाड की जीत इसलिए ज़्यादा महत्वपूर्ण थी, क्योंकि एशियाई देशों के सभी शीर्ष खिलाड़ी इसमें भाग ले रहे थे और सोमदेव ने ख़ुद से ऊंची रैंकिंग के खिलाड़ियों को पराजित कर स्वर्णिम ताज हासिल किया. ख़ुद सोमदेव भी मानते हैं कि जब देश के प्रतिनिधित्व की बात आती है तो उनके प्रदर्शन का स्तर बढ़ जाता है. सोमदेव यदि रमेश कृष्णन, विजय अमृतराज और लिएंडर पेस जैसे खिलाड़ियों के नक्शेकदम पर चलना चाहते हैं तो उनके सामने चुनौतियां बड़ी हैं. अपने करियर के शीर्ष पर रमेश कृष्णन एटीपी रैंकिंग में 23वें स्थान तक पहुंचे थे, जबकि विजय अमृतराज 16वें स्थान तक पहुंचने में कामयाब रहे थे. इन दोनों खिलाड़ियों ने केवल डेविस कप में ही नहीं, बल्कि ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंटों में भी शीर्ष स्तरीय खिलाड़ियों को कई बार हराया था. इंडियन एक्सप्रेस के नाम से मशहूर लिएंडर पेस और महेश भूपति हालांकि सिंगल्स से ज्यादा सफल डबल्स में रहे हैं और एटीपी की डबल्स रैंकिंग में विश्व के शीर्ष खिलाड़ियों में शामिल रहे हैं, लेकिन पेस अपने करियर के शुरुआती दिनों में सिंगल्स मुक़ाबलों में भी प्रभावशाली प्रदर्शन करने में कामयाब रहे थे. रमेश कृष्णन और लिएंडर पेस जूनियर रैंकिंग में विश्व के नंबर एक खिलाड़ी रह चुके हैं. इनके मुकाबले सोमदेव सिंगल्स में 94वें स्थान तक पहुंचने में ही सफल रहे हैं. वह इस रैंकिंग को भी ज्यादा दिनों तक बनाए नहीं रख सके और जल्द ही शीर्ष 100 यिों की सूची से बाहर हो गए. उन्हें यदि इन महान खिलाड़ियों की तर्ज पर अंतरराष्ट्रीय टेनिस में खास मुकाम हासिल करना है तो उन्हें खेल के सभी क्षेत्रों में अपनी क्षमता को बढाना होगा. टेनिस कोर्ट में उन्हें रक्षात्मक शैली का खिलाड़ी माना जाता है और उन्हें अपनी आक्रामकता बढानी होगी. अपनी सर्विस में सुधार के साथ-साथ अलग-अलग कोर्ट पर खेलने में महारत हासिल करनी होगी.

हालांकि साल 2010 उनके लिए अच्छे परिणाम लेकर आया है और उनसे उम्मीदें भी बढ़ गई हैं, लेकिन वह किसी जल्दी में नहीं हैं. उनका मानना है कि उनका काम मेहनत करना है और इसमें वह कोई कसर नहीं छोड़ना चाहते, बाकी चीजें काफी हद तक क़िस्मत पर निर्भर करती हैं. इससे यह पता चलता है कि कामयाबी के बावजूद उनके पैर ज़मीन पर हैं. युवा खिलाड़ी अक्सर शुरुआती कामयाबियों के बाद अपने रास्ते से भटक जाते हैं, क्योंकि सफलता के साथ आने वाले पैसे, प्रतिष्ठा और दबाव को बर्दाश्त करने के लिए वह मानसिक रूप से तैयार नहीं होते. हम सानिया मिर्ज़ा का हश्र देख चुके हैं. भारत की टेनिस प्रेमी जनता को सोमदेव से काफी उम्मीदें हैं. हालिया सफलताओं के बाद भारतीय टेनिस को आगे ले जाने की बड़ी ज़िम्मेदारी उनके कंधों पर है. उन्हें ग़लतियों से बचना होगा और लगातार कड़ी मेहनत करनी होगी. यदि वह ऐसा करने में कामयाब हुए तो सोमदेव वास्तव में भारतीय टेनिस के अगले सूर्य हो सकते हैं.

सोमदेव के खेल का असली रंग तब देखने को मिलता है, जब वह भारत का प्रतिनिधित्व कर रहे होते हैं. इसकी पहली झलक 2009 के डेविस कप में देखने को मिली, जब उन्होंने चाइनीज ताइपे के ख़िलाफ़ भारत को जीत दिलाने में अहम भूमिका निभाई.

आदित्य पूजन
aditya@chauthiduniya.com

देश का पहला इंटरनेट टीवी
हर दिन 50,000 से ज़्यादा दर्शक
दो टूक–संतोष भारतीय के साथ
ब्लैक एंड व्हाइट रोज़ाना 1 बजे
पॉलिटिकल हिस्ट्री ऑफ इंडिया
स्पेशल रिपोर्ट
नायाब हैं हम–उर्दू के मशहूर शायरों, गीतकारों के साथ मुलाक़ात
साई की महिमा

एफ-2, सेक्टर-11, नोएडा-201301 www.chauthiduniya.tv

Postal Regn. No. DL/ND-11/6139/2009-11, RNI No. DELHIN/2009/30467

हॉट एवं सेक्सी छवि होने के बाद भी कंगना को बॉलीवुड में सफलता नहीं मिल सकी. उनका मानना है कि ऐसा उनके द्वारा लिए गए कुछ ग़लत फ़ैसलों के कारण हुआ.

समीरा द स्ट्रीट फाइटर

एक बेहतरीन क्लासिकल डांसर और ऐक्टिंग में विविधता प्रदर्शित करने वाली अभिनेत्री समीरा रेड्डी ने बॉलीवुड में अच्छी-ख़ासी पहचान बना ली है. सिर्फ़ एक म्यूज़िक वीडियो करने के बाद ही उनकी स्क्रीन एपीयरेंस को तुरंत नोटिस कर लिया गया था और केवल चार सालों में उन्होंने पंद्रह फिल्में कर डालीं. उन्होंने ख़ुद के मल्टी टैलेंटेड होने का सबूत दिया और सफलता की कई पायदानों पर पैर रखा. 2007 के टोरंटो फिल्म फेस्टिवल में समीरा के खाते से दो स्वतंत्र फिल्में प्रदर्शित की गईं. पहली फिल्म मीरा नायर द्वारा बनाई गई माइग्रेशन थी, जिसमें उन्होंने किसी भयंकर रोग से पीड़ित एक हाउस वाइफ का किरदार निभाया था और दूसरा बुद्धदेव दास गुप्ता की द वायर्स. फैशन, सेक्स और ख़ूबसूरती की मिसाल कहलाने वाली समीरा कई मैगजीन कवर्स पर भी छाईं. बीबीसी ने उन्हें कैजुएल्टी नामक प्रसिद्ध सीरीज में गेस्ट एक्टर के तौर पर मौक़ा दिया. समीरा की उपलब्धियां बॉलीवुड की अन्य अभिनेत्रियों से ज़्यादा ख़ास हैं. वह बॉलीवुड की पहली ऐसी अभिनेत्री हैं, जिन पर वीडियो गेम बनाया गया. इस मोबाइल वीडियो गेम का नाम है समीरा: द स्ट्रीट फाइटर. समीरा का यह वीडियो गेम उनके लाखों प्रशंसकों द्वारा मोबाइल पर डाउनलोड किया गया और ख़ूब पसंद भी किया गया. समीरा सड़कों-फुटपाथों पर रहने वाले बच्चों के कल्याण में सक्रिय संगठन क्रेयांस और ड्रीम्स होम्स के लिए काम करती हैं. स्वभाव से वह शर्मीली और मूडी हैं, उन्हें आम लड़कियों की तरह सॉफ्ट टॉयज पसंद हैं और वह फाइव स्टार रेस्टोरेंट में खाने के बजाय छोटे रेस्त्रां में खाना पसंद करती हैं.

नई राह पर सेलिना

सेलिना जेटली ने हाल में अपना जन्मदिन मनाया. अपने बहुत खास दोस्तों के अलावा वह किसी अन्य को अपनी बर्थ डे पार्टी में शामिल करना पसंद नहीं करती हैं. सेलिना बर्थ डे रीजॉल्यूशन में यक़ीन नहीं रखतीं और अपनी विश लिस्ट बढ़ाने के बजाय जो भी मिला है, उसके लिए भगवान का शुक्रिया अदा करती हैं. आने वाले नए साल के लिए भी सेलिना कोई रीजॉल्यूशन नहीं बना रही हैं. इस बार नए साल पर वह दिल्ली में 35 हज़ार लोगों के सामने अपना शो करने वाली हैं, इस लिहाज़ से आने वाला साल उनके लिए ख़ास है. उन्हें अपने जीवन से कोई शिक़ायत नहीं है. वह अपने काम और निजी ज़िंदगी को लेकर ख़ुश हैं. वह मानती हैं कि सफलता के लिए वक़्त की कोई बाध्यता नहीं होती. पूरा जीवन एक सफर है, इसलिए हमेशा बेहतर प्रदर्शन करना चाहिए, सफलता अपने आप मिलने लगती है. इस बार वह कैरो फिल्म फेस्टिवल में जूरी मेंबर बनकर काफी उत्साहित हैं, क्योंकि वहां बेहतरीन फिल्में देखने का मौक़ा मिलता है. उन्हें फिल्म फेस्टिवल बेहद पसंद है. कैरो उनके ड्रीम डेस्टिनेशन में शामिल है. सेलिना इन दिनों अनीस बज्मी की फिल्म थैंक्यू की शूटिंग में व्यस्त हैं. इसमें उनके साथ अक्षय कुमार, सोनम कपूर, बॉबी देओल, सुनील शेट्टी, इरफान खान एवं रिमी सेन आदि हैं. फिल्म की शूटिंग भारत के अलावा वैनकुव, कनाडा और टोरंटो में हुई है. रोमांटिक कॉमेडी जॉनर इस फिल्म को रोनी स्क्रूवाला ने प्रोड्यूस किया है.

भूमिका की समझदारी

दिल्ली की कुड़ी भूमिका चावला अपने सैन्य अधिकारी पिता की ज़िम्मेदार बेटी हैं. देश के विभिन्न हिस्सों में पोस्टिंग होने के बावजूद भूमिका को अपने पिता के पेशे से कोई शिक़ायत नहीं है. उन्होंने अपने पिता की इस जॉब का फ़ायदा उठाया और देश की विभिन्न संस्कृतियों का क़रीब से अध्ययन किया. भूमिका ने अपनी स्कूली पढ़ाई दिल्ली में पूरी की और 1997 में मुंबई चली गईं. उसके बाद वह एड फिल्मों और म्यूज़िक वीडियो में काम करने लगीं. आत्मनिर्भरता और अनुशासन का पाठ जो उन्होंने अपने पिता से सीखा, उसे बख़ूबी अपने जीवन में भी उतार लिया. पांड्स टेल्कम पाउडर के ऐड कैम्पेन से उन्हें खासी पहचान मिली और उसके बाद उनके पास फिल्मों के ऑफर आने शुरू हो गए. उनकी पहली फिल्म तेलुगु थी, जो साल 2000 में आई. इस इंडस्ट्री में पहचान उन्हें फिल्म ख़ुशी से मिली, जिसके लिए बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड भी मिला. पंजाबी रंग-ढंग वाले परिवार में पली भूमिका ने दक्षिण की भाषाओं पर काफी मेहनत करके ख़ुद को स्थापित करने की कोशिश की.

लगभग 25 दक्षिण फिल्मों में काम करने के बाद 2003 में वह सुपर स्टार सलमान खान के साथ फिल्म तेरे नाम में मुख्य भूमिका निभाकर बॉलीवुड में भी छा गईं. उसके बाद उन्होंने अपने प्रेमी एवं योग इंस्ट्रक्टर भरत ठाकुर के साथ शादी करके पंजाबी फिल्मों की ओर रुख़ कर लिया. पंजाबी फिल्म यारीयां में उन्होंने गुरुदास मान के अपोजिट मुख्य भूमिका निभाई. निजी जीवन और करियर को एक समान प्राथमिकता देते हुए भूमिका इन दिनों अपनी आने वाली फिल्मों की शूटिंग में व्यस्त हैं. उनकी लगभग आधा दर्जन फिल्में कतार में हैं.

बिंदास कंगना

कंगना इन दिनों ख़ूब चर्चाएं बटोर रही हैं. कभी उनके फैशन स्टेटमेंट के चर्चे होते हैं तो कभी उनके अंगों की सर्जरी के, लेकिन वह अपने अभिनय से भी ख़ूब पहचान बना रही हैं. फिल्म इंडस्ट्री में और क्या चाहिए, जब किसी एक्ट्रेस को उसकी फिल्मों, फैशन और फंडे के लिए जाना जाने लगे. बी टाउन में सक्सेसफुल होने के ये सारे फैक्ट सच हैं. कंगना अपने परिधानों के ब्राइट कलर्स से पूरी पार्टी को अपना दीवाना बनाती हैं तो कभी पार्टी में मस्ती करते हुए अपनी बिंदास अदाओं के जलवे दिखाती हैं. कंगना डाउन टू अर्थ हैं, इसका प्रमाण उन्होंने हाल में एक पार्टी में दिया, जब उन्होंने सुष्मिता सेन की उतारी हुई टी-शर्ट पहन कर मस्ती की. यह किसी मजबूरी वश नहीं था, बल्कि उन्होंने ऐसा सिर्फ़ मस्ती करने के लिए किया. आने वाली फिल्म नो प्रोब्लम के सेट पर साथ रहते हुए दोनों के बीच काफी अच्छी दोस्ती हो चुकी थी. सुश ने सेट पर कंगना को बिल्कुल छोटी बहन की तरह ट्रीट किया और उनका नाम भी मिनी माउस रख दिया था, क्योंकि कंगना सेट पर ढेर सारी हेयर क्लिप लगाकर और पोनीटेल बनाकर घूमती रहती थीं. इतनी प्यारी दोस्ती के बाद आई लव सेक्स एंड द सिटी इबारत वाली टी-शर्ट पहन कर जब सुष्मिता सेन पार्टी में आईं तो कंगना वहां पहले से मौजूद थीं. कंगना ने जब सुश को उनके फेवरिट सीरियल के कोटेशन वाली टी-शर्ट पहने देखा और तारीफ़ की तो सुष्मिता ने फटाफट अपनी टी-शर्ट उतार कर कंगना को दे दी. कंगना मानती हैं कि सुष्मिता मैजिकल हैं और उनके चेहरे की तरह उनका मन भी बेहद ख़ूबसूरत है.

पायल ने ग़लती मानी

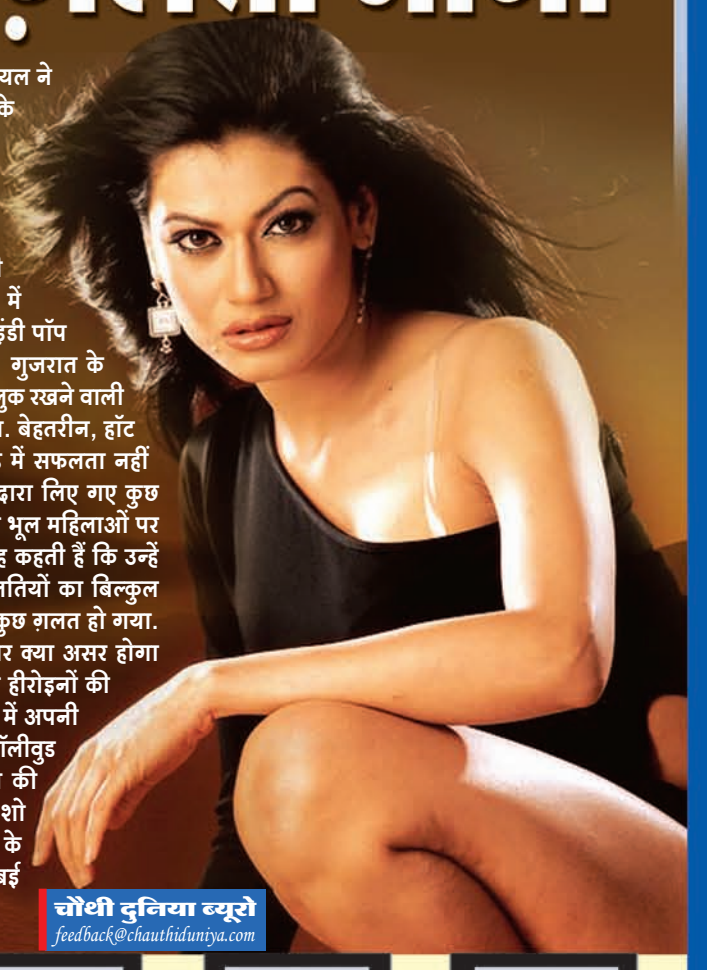

कंप्यूटर इंजीनियरिंग में डिग्री लेकर पायल ने अपना लक बॉलीवुड में आजमाने के लिए सोचा. फेमिना मिस इंडिया कॉन्टेस्ट में अंतिम नौ ख़ूबसूरत लड़कियों में पायल भी शामिल थीं, उन्हें साउथ अमेरिका में मिस टूरिज्म वर्ल्ड का खिताब मिला. अमूल, निरमा, कैडबरी और नेसकैफे जैसी कुछ अच्छी एड फिल्मों के ज़रिए वह स्क्रीन पर नज़र आने में सफल हुईं. उसके बाद उन्होंने सिल्क रूट और इंडी पॉप एलबम आर्टिस्ट केके के साथ भी काम किया. गुजरात के अहमदाबाद के एक मध्यमवर्गीय परिवार से ताल्लुक रखने वाली पायल ने हाल में अपना 26वां जन्मदिन मनाया. बेहतरीन, हॉट एवं सेक्सी छवि होने के बाद भी उन्हें बॉलीवुड में सफलता नहीं मिल सकी. उनका मानना है कि ऐसा उनके द्वारा लिए गए कुछ ग़लत फ़ैसलों के कारण हुआ. उनकी सबसे बड़ी भूल महिलाओं पर बनने वाली फिल्मों में एक्सपोज करना रहा. वह कहती हैं कि उन्हें फिल्म मेकिंग और प्रेजेंटेशन में होने वाली ग़लतियों का बिल्कुल अंदाज़ा नहीं था, जिसकी वजह से उनसे बहुत कुछ ग़लत हो गया. उन्हें पता नहीं था कि इन प्रोजेक्ट्स का उन पर क्या असर होगा और अपनी मार्केटिंग उन्हें कैसे करनी है. दूसरी हीरोइनों की तरह अब वह भी सीखने लगी हैं कि इस इंडस्ट्री में अपनी जगह किस तरह बनाई जाए. पायल की पहली बॉलीवुड फिल्म है-ये क्या हो रहा है? यह हैरी बावेजा की फिल्म है. पिछले दिनों वह टेलीविजन रियलिटी शो बिग बॉस से चर्चा में आई थीं. पायल करियर के अलावा समाज सेवा में भी ध्यान देती हैं. वह मुंबई के एनजीओ जीवनधारा से भी जुड़ी हैं.

चौथी दुनिया ब्यूरो
feedback@chauthiduniya.com

प्रीव्यू

तेरा क्या होगा जॉनी

यंग एंड हैंडसम नील नितिन मुकेश और ग्लैमरस सोहा अली खान स्टारर फिल्म तेरा क्या होगा जॉनी भारत में रिलीज के लिए अर्से से तरस रही थी. 2008 में ही दुबई फिल्म फेस्टिवल में शो केस होने के बाद भारत में रिलीज से पहले ही यह फिल्म कंट्रोवर्सी में उलझ चुकी है, जिसका असर रिलीज की तारीख़ पर पड़ा. काफी अटकलों के बाद अब यह फिल्म 17 दिसंबर को रिलीज होने वाली है. इसमें दो फिल्मकार बतौर अभिनेता नज़र आने वाले हैं, अनुराग कश्यप और आदित्य भट्टाचार्य. इनके साथ के के मेनन और करण नाथ भी नज़र आएंगे. निर्देशन सुधीर मिश्रा ने किया है. क्राइम थ्रिलर जॉनर की यह फिल्म टूटू शर्मा, मनु कुमारन और ख़ुद सुधीर मिश्रा ने प्रोड्यूस की है.

फिल्म मुंबई में सड़क पर चाय बेचने वाले एक बच्चे की कहानी पर आधारित है. यह किरदार बाल कलाकार सिकंदर ने अदा किया है. इंडिया शाइनिंग के सपने का हिस्सा बनने वाले परवेज यानी नील नितिन मुकेश मुंबई के रहने वाले हैं. उनके जीवन में एक जंग सी छिड़ी होती है. परिवार के प्रति ज़िम्मेदारियों और प्रेमिका दिव्या यानी शहाना गोस्वामी के साथ शादी करने की ख्वाहिश ने उन्हें परेशानी में डाल रखा है. दिव्या की शादी एनकाउंटर के लिए मशहूर भ्रष्ट पुलिस अफसर चिपले से हो जाती है. चिपले का किरदार के के मेनन ने निभाया है. परवेज अपने परिवार को अच्छी ज़िंदगी देने के लिए जल्द से जल्द अमीर बनना चाहता है, लेकिन ऐसा कैसे हो, उसे समझ में नहीं आता. वह एक फ्लैट की ख़रीद-फरोख्त के दौरान चिपले के पैसों को चुराने के लिए जुगत भिड़ाता है, जिसमें सड़क किनारे चाय बेचने वाला सिकंदर भी शामिल हो जाता है. इस काम से न सिर्फ़ उसकी भावनाओं को ठेस पहुंचती है, बल्कि उसकी जान पर भी बन आती है.

भारत में कोई और फिल्म निर्माता इतने सशक्त तरीक़े से जीवन की सच्चाई और बर्बरता को पर्दे पर उतारने में सफल नहीं हुआ. सुधीर मिश्रा वक़्त के साथ समाज में हो रहे परिवर्तनों को स्क्रीन कैरेक्टर और रिश्तों के ज़रिए पेश कर पाने में लगातार सफल हुए हैं. फिल्म तेरा क्या होगा जॉनी में प्रीति यानी सोहा अली खान और विशाल यानी करण नाथ की भी कहानी है. वह एक स्ट्रगलर मॉडल है, जो वक्त के साथ अपनी लड़ाई लड़ रही है और विशाल अपने बड़े-बड़े सपने पूरे करने के लिए कोकीन के धंधे में उतर कर अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर लेता है. उसका रुझान अपराधों की तरफ़ हो जाता है. ड्रग डीलर विजय मौर्य उर्फ छुट्टा विशाल के इस ट्रेड को कॉरपोरेटाइज करने की कोशिश करता है, जिसमें उसकी मां और दूसरे धनी लोग भी शामिल हो जाते हैं.

चौथी दुनिया

उत्तर प्रदेश
उत्तराखंड

दिल्ली, 13 दिसंबर–19 दिसंबर 2010

www.chauthiduniya.com

यह जनता का पैसा है

केंद्र–राज्य संबंध में विवाद कोई नई बात नहीं. कांग्रेस कहती रही कि बिहार का विकास केंद्र के भेजे पैसे से हुआ. नतीजा क्या निकला, सबको पता है. अब उत्तर प्रदेश में भी कांग्रेस यही कह रही है. इस आरोप के साथ कि यहां तो विकास भी नहीं हुआ. मायावती कांग्रेस पर हमले कर रही हैं. बयानबाज़ी चरम पर है. लेकिन इस सब के बीच नुक़सान उत्तर प्रदेश का हो रहा है, यहां की जनता का हो रहा है. सोनिया गांधी या मायावती यह भूल गई हैं कि यह पैसा उनका नहीं, जनता का है और इसे जनता के लिए ही ख़र्च किया जाना चाहिए.

फोटो–*प्रभात पाण्डेय*

प्रभात रंजन दीन

धन चाहे केंद्र का हो या राज्य का, किसी पार्टी का नहीं होता. केंद्र में सत्ता संभालने वाली पार्टी जिस तरह केंद्र सरकार के धन पर दलीय अभिमान नहीं जता सकती, उसी तरह राज्य की सत्ता संभालने वाली पार्टी या उसके नेता का भी सरकारी धन पर पार्टीगत या व्यक्तिगत अधिकार नहीं होता और न ही उस धन के अपव्यय का उस पार्टी को कोई विधिक अधिकार होता है. बिहार में विकास को लेकर केंद्र के धन के इस्तेमाल पर नीतीश और सोनिया गांधी में जिस तरह दावे–प्रतिदावे हुए, उसी तरह उत्तर प्रदेश में भी मायावती और सोनिया गांधी के बीच खींचतान तेज हो गई है. चुनाव जैसे–जैसे नजदीक आता जाएगा, यह खींचतान और धार पकड़ती जाएगी. लेकिन बिहार और उत्तर प्रदेश का मौलिक फर्क यह है कि केंद्र के धन का बिहार में सार्थक इस्तेमाल हुआ और उत्तर प्रदेश में बेजा. लिहाज़ा, सोनिया गांधी और मायावती के बीच की खींचतान की बिहार परिप्रेक्ष्य में समीक्षा नहीं हो सकती. इस खींचतान की उत्तर प्रदेशीय समीक्षा होगी. अभी पिछले दिनों अपने संसदीय क्षेत्र रायबरेली आईं सोनिया गांधी ने उत्तर प्रदेश में केंद्र के धन के बेजा इस्तेमाल पर एक बार फिर उंगली उठाई और इस मसले पर फिर से बहस तेज हो गई. मायावती ने अपने स्वभाववश तीखी प्रतिक्रिया जताई और राज्य के प्रति केंद्र की उपेक्षा का अपना पुराना डायलॉग दोहराया. बुंदेलखंड को लेकर केंद्र की उपेक्षा का आरोप भी फिर से ताजा किया गया और ज़मीनी सच की समीक्षा के बजाय सोनिया गांधी और मायावती के तर्क–प्रतितर्क की राजनीतिक समीक्षा होकर रह गई. दोनों के निहितार्थ भले ही राजनीतिक हों, लेकिन ज़मीनी असलियत के आधार पर सरकारी धन के इस्तेमाल पर नुक्ताचीनी हो सकती है, चाहे वह धन केंद्र सरकार का हो या राज्य सरकार का. रायबरेली में सड़कों की जर्जर हालत पर सोनिया गांधी की स्वाभाविक प्रतिक्रिया थी कि सरकारी धन का आखिर इस्तेमाल कहां हो रहा है? इस एक सवाल ने कई जवाब सामने रख दिए. सार्वजनिक मंच पर भी सोनिया गांधी ने यह बात दोहराई और कहा कि प्रदेश सरकार को इसका हिसाब तो देना ही होगा कि सरकारी धन किन–किन मदों पर ख़र्च हुआ. राजनीतिक नज़रिए के बजाय सामाजिक दृष्टिकोण से देखें तो इसका व्यवहारिक महत्व समझ में आता है और आम आदमी को धरातल पर दिखने वाले व्यवहारिक महत्व से ही मतलब होना चाहिए.

स्मारकों, पत्थरों और मूर्तियों के अंधाधुंध विकास के लिए अपनी ख़ास और अनोखी शिनाख्त दर्ज़ करने वाले उत्तर प्रदेश में सरकारी धन के इस्तेमाल के आधिकारिक आंकड़े सामने रखें तो विकास की असली परिभाषा और सियासत की असलियत समझ में आती है. उत्तर प्रदेश में पत्थरों और मूर्तियों की स्थापना के ड्रीम प्रोजेक्ट पर अब तक 17 हज़ार करोड़ रुपये लगाए जा चुके हैं और यह क्रम लगातार जारी है. उत्तर प्रदेश सरकार का सालाना निर्धारित ख़र्चा 34 हज़ार करोड़ रुपये है, जबकि सालाना राजस्व आमद 33 हज़ार करोड़ रुपये ही है. ऐसे में सवाल उठता है कि फिर कैसे चल रहा है उत्तर प्रदेश? फिर प्रदेश को चलाने के लिए धन कहां से आ रहा है? इस धन के इस्तेमाल के तौर–तरीक़ों पर क़ानूनी अंकुश और जांच ज़रूरी है कि नहीं? चाहे वह धन केंद्र से आया हो या राज्य सरकार का हो. इन सवालों के जवाब राजनीतिक बयानबाज़ियों से समझ में नहीं आने वाले. राजनीतिक बयान जवाब तलाशने की कोशिशों को भ्रमित करने और लक्ष्य से भटकाने के लिए ही सोच–समझ कर जारी किए जाते हैं. केंद्र के धन पर गुमान करने वाली कांग्रेस का बिहार में क्या हश्र हुआ, इससे कांग्रेस को सीख लेनी चाहिए. विकास के मसले पर बिहार में हुए मतदान ने जो रास्ता दिखाया है, वह अब जल्दी ही उत्तर प्रदेश में भी अपनाया जाने वाला है. धन का गुमान हो या मूर्तियां खड़ी करने का अभिमान, सबको विकास के पैमाने पर तौला जाना है. उत्तर प्रदेश की बहुजन समाज पार्टी की सरकार भ्रष्टाचार में डूब–उतरा रही है, केंद्र में कांग्रेस का भी वही हाल है, लिहाज़ा परीक्षा दोनों पार्टियों को देनी है. कांग्रेस भले ही यह दावा करती हो कि 1989 में उत्तर प्रदेश सरकार पर 250 करोड़ रुपये का क़र्ज़ था और आज उत्तर प्रदेश की सरकार दो लाख 20 हज़ार करोड़ रुपये के क़र्ज़ में डूबी है, लेकिन अकेले 2–जी स्पेक्ट्रम घोटाला कितने हज़ार करोड़ रुपये का है, इसे देखें तो 1989 की कांग्रेस सरकार और 2010 की मायावती सरकार के क़र्ज़ का फ़र्क सामने दिखने लगता है. भ्रष्टाचार किसी भी चुनाव का मुद्दा नहीं बनता, विकास मुद्दा ज़रूर बनता है. लिहाज़ा विकास के नज़रिए से भी हम विश्लेषण करें तो पत्थर लगाने के नाम पर अकेले निर्माण निगम द्वारा दो साल में ही जो 4,450 करोड़ रुपये फूंक डाले गए और परिकल्प भवन के सामने वीआईपी रोड के एक छोटे से हिस्से के निर्माण पर जो 872 करोड़ रुपये ख़र्च किए गए, वह पेशानी पर बल देने के लिए काफ़ी है. विकास के बरक्स भ्रष्टाचार जिस तरह प्रतिद्वंद्वी बनकर सामने खड़ा है और धन को सुरसा की तरह खा रहा है, वह उत्तर प्रदेश के मतदाताओं को निश्चित रूप से समझ में आना चाहिए. केंद्र के धन के अपव्यय पर सोनिया गांधी की टिप्पणी के बाद उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री मायावती ने केंद्र द्वारा राज्य की उपेक्षा किए जाने का जिक्र करते हुए फिर से बुंदेलखंड का हवाला दिया. उन्होंने कहा कि बुंदेलखंड और पूर्वी उत्तर प्रदेश को विशेष पैकेज देने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने केंद्र से कई बार आग्रह किया, लेकिन केंद्र ने कोई मदद नहीं दी. मुख्यमंत्री मायावती के इस बयान के परिप्रेक्ष्य में आप केंद्र सरकार द्वारा आहूत की जाने वाली बैठकों में मुख्यमंत्री मायावती की उपस्थिति की आधिकारिक सूचनाओं का जायजा लें तो इन बयानबाज़ियों का सच साफ़–साफ़ समझ में आता है. बुंदेलखंड को लेकर केंद्र द्वारा बुलाई गई एक भी बैठक में मुख्यमंत्री मायावती शामिल नहीं हुईं. इसके बावजूद केंद्र सरकार ने बुंदेलखंड पैकेज के लिए 7000 करोड़ रुपये जारी किए. उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री ही देश की अकेली ऐसी मुख्यमंत्री हैं, जो केंद्र की किसी भी बैठक में नहीं जातीं. वह चाहे राष्ट्रीय विकास परिषद की हो या योजना आयोग की या सुरक्षा जैसे संवेदनशील मसलों पर केंद्र सरकार की ओर से आहूत की जाने वाली बैठक हो. मायावती सरकार ने बुंदेलखंड और पूर्वी उत्तर प्रदेश के लिए 80 हज़ार करोड़ रुपये मांगे थे, लेकिन जब उत्तर प्रदेश सरकार से इस मांग के समानांतर मैचिंग ग्रांट का ब्योरा मांगा गया तो उसका कोई जवाब नहीं दिया गया. बाद में सरकार की तरफ़ से स्पष्ट कहा गया कि इस मांग के एवज में राज्य सरकार की कोई मैचिंग ग्रांट है ही नहीं. इसके बावजूद केंद्र ने सात हज़ार करोड़ रुपये जारी कर दिए. उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा महज स्मारकों के रखरखाव के लिए रखा गया 367 करोड़ रुपये का बजट बुंदेलखंड की भुखमरी और बीमारग्रस्त पूर्वी उत्तर प्रदेश के पिछड़ेपन पर करारा तमाचा है. केंद्र और राज्य सरकार के बीच राजनीति जो भी हो रही हो, इसका ख़ामियाजा तो प्रदेश को ही भुगतना पड़ रहा है.

उत्तर प्रदेश में विकास कार्यों की गिनती में गंगा एक्सप्रेस–वे का भी जिक्र किया जाता है, लेकिन इस बात का जिक्र नहीं किया जाता कि एक्सप्रेस–वे का कोई आधिकारिक प्रस्ताव सरकार के समक्ष पेश ही नहीं किया गया था तो इसकी मंजूरी कैसे मिल गई? और जेपी समूह को इसका ठेका कैसे मिल गया? सौ करोड़ के बने–बनाए अंबेडकर उद्यान प्रोजेक्ट को ध्वस्त कर फिर से बनाने का दलित स्वाभिमान की रक्षा का बसपाई तर्क प्रदेश के उन दलितों को समझ में नहीं आ रहा, जिन्हें मायावती सरकार के कारण सौ रुपये कम पेंशन मिल रही है. केंद्र और राज्य सरकार का हिस्सा (50–50 रुपये) मिलाकर प्रदेश के दलितों को पहले सौ रुपये पेंशन मिलती थी. तक़रीबन साल भर पहले केंद्र की ओर से प्रस्ताव किया गया कि दो–दो सौ रुपये दोनों सरकारें दें तो दलितों की पेंशन बढ़कर 400 रुपये हो सकती है, लेकिन उत्तर प्रदेश की मायावती सरकार इसके लिए राजी नहीं हुई. केंद्र सरकार ने अपनी तरफ़ से पेंशन की राशि बढ़ाकर दो सौ रुपये कर दी, लेकिन राज्य सरकार अपनी तरफ से सौ रुपये ही दे रही है. इस तरह उत्तर प्रदेश के दलितों को तीन सौ रुपये ही पेंशन मिल रही है, जबकि अन्य प्रदेशों में दलितों की पेंशन राशि चार सौ रुपये है. बुंदेलखंड क्षेत्र की भुखमरी अब अंतरराष्ट्रीय स्तर पर चर्चित हो चुकी है. भुखमरी और ग़रीबी के कारण यहां से लोगों का लगातार पलायन हो रहा है, लेकिन इसी क्षेत्र के नेता कैसे फल–फूल रहे और समृद्ध होते जा रहे हैं, इस पर ध्यान दिलाना भी राजनीतिक–सामाजिक अनिवार्यता है. नसीमुद्दीन सिद्दीकी और बाबू सिंह कुशवाहा जैसे बसपा के कई ताकतवर नेता बुंदेलखंड इलाक़े से ही आते हैं. इस इलाक़े में पहाड़ों से चट्टानों की बेतहाशा खुदाई और नदियों से बालू का अनाप–शनाप दोहन नेताओं के लिए सोना और पर्यावरण के सहारे जीने वाले आम लोगों के लिए रोना दे रहा है. उत्तर प्रदेश में सोने और रोने का यह फ़र्क आगामी विधानसभा चुनाव में बिहार के नीतीश कुमार और उत्तर प्रदेश की मायावती के बीच का फ़र्क साबित होने वाला है.

feedback@chauthiduniya.com

भातखंडे संगीत संस्थान में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की ओर से निर्धारित मानकों के अनुरूप सत्र 2001-02 से शास्त्रीय संगीत की विभिन्न विधाओं में बीपीए, एमपीए और पीएचडी स्तर की शिक्षा प्रारंभ की गई.

बसपा भी कूटयुक्ति भिड़ाकर कांग्रेस की रणनीतिक धार को कुंद कर देना चाहती है. अगर उत्तर प्रदेश के सियासी ज़मीन की पड़ताल की जाए तो तस्वीर बड़ी रोचक बनती दिख रही है.

खिलाड़ियों का पूर्वांचल

विजय यादव

चोलापुर के नीमा गांव में जन्मे नरसिंह यादव, आजमगढ़ के ओंकार सिंह, बनारस में लोहता के रामआसरे यादव, काशी के ही राम सिंह, बास्केट बॉल की सिंह सिस्टर्स, नामों की यह लिस्ट काफ़ी लंबी है. खेल की दुनिया के यह जगमगाते सितारे पूर्वांचल का जगमगाता वर्तमान है. अतीत और भी शानदार है. जरा ग़ौर फरमाइए मो. शाहीद, विवेक सिंह और राहुल के नामों पर. आंखों के सामने ओलंपिक का नज़ारा आ जाता है. भारतीय हॉकी टीम की शान रहे यह तीनों ही स्टार पुरबिया माटी में पले बढ़े और देश के मान–सम्मान को ऊंचाइयों तक पहुंचाया. लेकिन आज उसी पूर्वांचल में भारतीय हॉकी की दुर्दशा किसी से छिपी नहीं है. यह स्थिति अकेले हॉकी की ही नहीं है बल्कि अन्य खेलों के हालात भी कम बदतर नहीं हैं. वह तो खिलाड़ियों का जज्बा और मेहनत है जो उन्हें मेडल दिला देती है. बनारस की अगर बात करें तो देश को तीन–तीन ओलंपियन देने वाले इस शहर में हॉकी की खस्ताहाल स्थिति चिंताजनक है. खेल के साथ मजाक करते हुए सरकारी कर्णधारों ने एस्ट्रोटर्फ स्टेडियम का निर्माण बनारस की सीमा से सटे लालपुर में कराया. यह शहर से इतना दूर है कि नियमित अभ्यास के लिए रोजाना वहां पहुंच पाना खिलाड़ियों की पहुंच से बाहर है. ग़रीब खिलाड़ी किसी तरह हॉकी स्टिक और बॉल का इंतजाम करने के बाद अपनी ख़ुराक पूरी कर पाते हैं, उस पर लंबी दूरी को तय करके स्टेडियम तक आने–जाने का भारी भरकम ख़र्च, उनके वश में नहीं है. डॉ. भीमराव अंबेडकर की याद में बनाया गया यह स्टेडियम करोड़ों रुपए ख़र्च होने के बाद दुर्दशा का शिकार हो गया. हालात भांपकर सरकार ने इस स्टेडियम की हालत सुधारने के लिए एक बार फिर धन की व्यवस्था की है. लेकिन इस बार भी सरकारी धन की बर्बादी नहीं हो, यह अभी तक तय नहीं किया जा सका है. जब खिलाड़ी नहीं होंगे तो यहां अभ्यास कौन करेगा, इस सवाल का जवाब खेल विभाग के अधिकारियों के पास नहीं है. स्टेडियम के नए सिरे से तैयार होने के बाद यहां नियमित अभ्यास कराने की योजना बनाई गई या नहीं लेकिन इन सबके बीच एक पहल ज़रूर हुई है. राज्य खेल निदेशालय की दिलचस्पी के बाद हॉकी का हॉस्टल यहां स्थानांतरित किया जा चुका है लेकिन इतने भर से हालात सुधरने वाले नहीं हैं. हॉकी के खिलाड़ी पहले के शानदार दिनों को याद करके आज के हालात पर अपना नाराज़गी जाहिर करते हैं. बनारस के युवा खिलाड़ियों का कहना है कि वह भी क्या जमाना था जब हॉकी की राष्ट्रीय टीम में पूरब के खिलाड़ियों की संख्या छह से सात तक होती थी. इनमें भी अधिकांश खिलाड़ी बनारस के होते थे लेकिन अब पहले जैसी स्थिति नहीं रह गई है. इस समय हॉकी की जूनियर टीम में ही पूर्वांचल की हिस्सेदारी है. जूनियर टीम में बनारस के प्रमोद कुमार और गोरखपुर के दिवाकर राम पूर्वांचल का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं. पूर्वांचल में हॉकी जिंदा रहे, इसके लिए गाजीपुर के करमपुर और अठगावां में निजी अकादमी काम कर रही है. इन दोनों ही अकादमी को साई से हर संभव मदद भी मिल रही है. इन प्रयासों से पूरब की माटी में हॉकी की चपलता तो बरकरार है लेकिन खिलाड़ी अब राष्ट्रीय टीम का हिस्सा नहीं बन पा रहे हैं. इन हालात में उनका मनोबल गिर रहा है. हॉकी की इस दुर्दशा पर पूर्वांचल के बुद्धिजीवी व खेल प्रेमी ख़ासे चिंतित हैं. इन लोगों का कहना है कि खेल की व्यवस्था को नौकरशाही के चंगुल से निकाल कर उसे खिलाड़ियों के हाथों में सौंपना होगा, तभी कुछ भला हो सकेगा. हॉकी की इस गिरती दशा के बीच हाल ही में हुए कॉमनवेल्थ गेम्स में पूर्वांचल के खिलाड़ियों के दमदार प्रदर्शन ने उम्मीद की एक नई किरण दिखाई है. चोलापुर के नीमा गांव में जन्म लेने वाले नरसिंह यादव ने कॉमनवेल्थ में फ्री स्टाइल कुश्ती का स्वर्ण पदक जीता. वहीं आजमगढ़ में जन्मे सेना के निशानेबाज़ ओंकार सिंह ने कॉमनवेल्थ गेम्स में भारत को दोहरी स्वर्णिम क़ामयाबी दिलाकर पूर्वांचल का गौरव बढ़ाया था. बनारस में लोहता के भट्ठी गांव के राम आसरे यादव ने इसी वर्ष सिंगापुर में हुए कॉमनवेल्थ जूडो चैंपियनशिप में भारत के लिए स्वर्ण पदक जीतकर पुरबिया माटी को गौरवान्वित किया. बनारस के ही मैराथन धावक राम सिंह कॉमनवेल्थ गेम्स में पदक से भले ही चूक गए हों लेकिन उनमें भविष्य के अच्छे खिलाड़ी होने के सभी गुण हैं. इनके अलावा एथलीट प्रियंका पटेल (स्टीपल चेज), पोल वाल्टर गजानन उपाध्याय, गोला प्रक्षेपक चंद्रोदय नारायण सिंह, मैराथन धावक प्रीति राव पूर्वांचल की माटी की ही देन हैं. पुरबिया माटी में ही जन्मे मुक्केबाज़ छोटेलाल यादव एशियाड टीम में पहले से ही शामिल हैं. कामरान अकमल, आईपीएल में राजस्थान रॉयल्स की ओर से खेल कर सुर्खियां बटोर चुके हैं, वह अभी उत्तर प्रदेश की रणजी टीम का हिस्सा हैं. जौनपुर के शिवाकांत शुक्ला, वाराणसी के आशीष यादव भी इसी टीम के प्रमुख सदस्यों में शामिल हैं. सीनियर महिला फुटबॉल टीम में बनारस की पूनम चौहान अग्रिम पंक्ति की कमान संभाल रही हैं तो कामना गुप्ता और शमामा इकबाल राष्ट्रीय स्तर पर कैरम में नाम रौशन किया है. वाराणसी के शिवम श्रीवास्तव और आदर्श श्रीवास्तव की शतरंज में उपलब्धियां हर कोई जानता है. बास्केटबॉल की राष्ट्रीय टीम में पूर्वांचल की सिंह सिस्टर्स दिव्या, प्रशांति, आकांक्षा और प्रतिमा से कौन परिचित नहीं है. नामी–गिरामी खिलाड़ियों के नामों की यह लिस्ट काफ़ी लंबी चौड़ी है. लेकिन उस लिहाज़ से यहां सुविधाएं नहीं हैं. नतीजा खिलाड़ी प्रशिक्षण के लिए दूसरे राज्यों का मुंह ताकने को विवश होते हैं. हाल ही में कॉमनवेल्थ गेम्स में पुरबिया माटी के जिन खिलाड़ियों ने अपनी धरती का नाम रौशन किया, वह उनकी अपनी मेहनत और लगन का ही नतीजा रहा. सरकारी सुविधाओं के भरोसे रहते तो शायद ही उनके हाथ पदक लग पाता. ग़रीबी के बीच जीवन यापन करते हुए खेल को जीने का जज्बा ही उनकी जीत का महत्वपूर्ण कारक बना. पूर्वांचल की बहुत सी प्रतिभाएं पलायन करने को मजबूर हैं लेकिन राज्य के खेल महकमे के आला अधिकारी इससे तनिक भी चिंतित नहीं दिखते हैं. पूर्वांचल के बनारस को उत्तर प्रदेश की सांस्कृतिक राजधानी तक कहा जाता है लेकिन यह सब कहने भर के लिए ही है. विदेशी पर्यटकों का पसंदीदा शहर गंगा घाटों और बाबा विश्वनाथ के अलावा खिलाडिय़ों के लिए भी जाना जाता रहा है फिर भी सरकार यहां खेलों की आधारभूत सुविधाएं मुहैया कराने के प्रति सजग नहीं है. वजह चाहे जो भी लेकिन खेल के साथ खेल की यह नीति उत्तर प्रदेश की प्रतिभाओं का बंटाधार करने के लिए काफ़ी है.

बनारस के युवा खिलाड़ियों का कहना है कि वह भी क्या जमाना था जब हॉकी की राष्ट्रीय टीम में पूरब के खिलाड़ियों की संख्या छह से सात तक होती थी. इनमें भी अधिकांश खिलाड़ी बनारस के होते थे लेकिन अब पहले जैसी स्थिति नहीं रह गई है.

feedback@chauthiduniya.com

उत्तर प्रदेश की सियासत पर बिहार की आंच

पिछले दिनों इलाहाबाद में सोनिया गांधी की रैली और उनका बहुजन समाज पार्टी पर जमकर वार करना यह बताने के लिए काफ़ी है कि राजनीतिक तकरार का यह सिलसिला अब थमने वाला नहीं है. भ्रष्टाचार में डूबी कांग्रेस भ्रष्टाचार के ही पलटवार से बसपा को लहूलुहान करना चाहती है, वहीं सत्ता में दोबारा वापसी के लिए बसपा भी कांग्रेस की रणनीतिक धार को कुंद कर देना चाहती है.

अरविंद जयतिलक

बिहार विधानसभा चुनाव परिणाम की तपिश से अब उत्तर प्रदेश की सियासत भी गरमाने लगी है. अब सबको विकास की चिंता सताने लगी है. जो कल तक अगड़े–पिछड़े, ऊंच–नीच और हिंदू–मुस्लिम का कार्ड उछाल कर सत्ता तक पहुंचने की राह तलाशते थे, वही अब समतामूलक समाज के निर्माण की दलीलें गढ़ने लगे हैं. अचानक बिहार चुनाव परिणाम ने ऐसा क्या जादू कर दिया कि पांच दशक से चली आ रही चुनाव जीतने की जातीय वैमनस्यता और धार्मिक उन्माद फैलाने वाली राजनीतिक सोच अब स्याह पड़ने लगी है. बिहार में जातियों की गोलबंदी के सहारे सत्ता हासिल करने वाले व्यूहकारों के अहंकार और दर्प का पिंड पिघलने के बाद ऐसा होना लाज़िमी था. कल तक सोशल इंजीनियरिंग के बूते सियासी करामात दिखाने वाले भी अब तमाम आशंकाओं से घिरने लगे हैं. स्मारकों के बूते इतिहास में अमरत्व का ख्याल अब उन्हें मानसिक संताप देने लगा है. इसकी वजह 2012 में उत्तर प्रदेश में होने जा रहा विधानसभा का चुनाव है. पिछले दिनों इलाहाबाद में सोनिया गांधी की रैली और उनका बहुजन समाज पार्टी पर जमकर वार करना यह बताने के लिए काफ़ी है कि राजनीतिक तकरार का यह सिलसिला अब थमने वाला नहीं है. भ्रष्टाचार में डूबी कांग्रेस भ्रष्टाचार के ही पलट–तीर से बसपा को लहुलूहान करना चाहती है, वहीं सत्ता में दुबारा वापसी के लिए बसपा भी कूटयुक्ति भिड़ाकर कांग्रेस की रणनीतिक धार को कुंद कर देना चाहती है. अगर उत्तर प्रदेश में राजनीतिक दलों के सियासी ज़मीन की पड़ताल की जाए तो तस्वीर बड़ी रोचक बनती दिख रही है. सबसे पहले बात कांग्रेस की. उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की सियासी फितरतों को देखकर तो यही लग रहा है कि वह चाहे जितना भी जोर लगा ले, फिलहाल मिशन 2012 के ख्वाब को पर लगना मुश्किल है. क्योंकि कांग्रेस पार्टी जनाधार बढ़ाने के बजाय सोनिया गांधी और राहुल गांधी के करिश्मे पर ही आश्रित दिख रही है. कांग्रेस को समझ में नहीं आ रहा है कि लड़ाई जीतने के लिए करिश्माई नेतृत्व के साथ–साथ समर्पित कार्यकर्ताओं की सेना की भी ज़रुरत पड़ती है. सिर्फ मोर मुकुट श्रीकृष्ण वाले राहुल की पोस्टरबाजी और सोनिया गांधी को लेकर किए जाने वाले महिमामंडन से नतीजों को अपने पक्ष में नहीं किया जा सकता है. उत्तर प्रदेश लोकसभा चुनाव में एक हद तक ठीक–ठाक प्रदर्शन के बाद कांग्रेस के रणनीतिकारों को लगने लगा था कि सोनिया और राहुल का आभा मंडल उन्हें सत्ता का रसपान करा सकता है. लेकिन उत्तर प्रदेश उप–चुनावों में कांग्रेस उम्मीदवारों की करारी हार और बिहार विधानसभा चुनाव में सूपड़ा साफ़ हो जाने से साबित हो गया है कि जनतंत्र में वंश आबाद करने के बजाय जनतंत्र जिंदाबाद का नारा ही काम आ सकता है. पिछले दिनों बुंदेलखंड के विकास और दलित उत्पीड़न को लेकर कांग्रेस और बसपा दोनों एक दूसरे के ख़िलाफ़ ज़हर उगल रहे थे. अब कांग्रेस पार्टी ने बसपा सुप्रीमो मायावती के कभी ख़ास रहे कुलीन नौकरशाह पीएल पुनिया को अपना राजनीतिक औजार बना लिया है. उन्हें अनुसूचित जाति जनजाति आयोग का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाकर माया सरकार के बरक्स दलित हित चिंतक साबित करने की कांग्रेस की कोशिशें जनरुझान पैदा करती नहीं दिख रही हैं. कांग्रेस नेतृत्व राज्य संगठन को लेकर ही परेशान है. सोनिया या राहुल का गुप्त उत्तर प्रदेश दौरा और गुप्त तरीक़े से कार्यकर्ताओं की मीटिंग भी कांग्रेसियों के लिए संजीवनी नहीं बन पा रही है. ऐसे में मिशन 2012 को कांग्रेस पार्टी कैसे क़ामयाब बनाएगी, कहना मुश्किल है.

पिछले दिनों बुंदेलखंड के विकास और दलित उत्पीड़न को लेकर कांग्रेस और बसपा दोनों एक दूसरे के ख़िलाफ़ ज़हर उगल रहे थे. अब कांग्रेस पार्टी ने बसपा सुप्रीमो मायावती के कभी ख़ास रहे कुलीन नौकरशाह पीएल पुनिया को अपना राजनीतिक औजार बना लिया है.

दूसरी ओर जनाधार के मामले में उत्तर प्रदेश में लगातार फिसड्डी साबित होती जा रही भारतीय जनता पार्टी बसपा सरकार की नाक़ामी और केंद्रीय सरकार की ग़लत आर्थिक नीतियों के कारण उपजी महंगाई, भ्रष्टाचार और राष्ट्रीय सुरक्षा को मुद्दा बनाकर अपनी बात जनता तक पहुंचाना तो चाहती है, लेकिन इस सियासी दिखावेपन को भी वह कारगर ढंग से नहीं निभा पा रही है. उत्तर प्रदेश भाजपा में किस हद तक बिखराव है, इसी से समझा जा सकता है कि पिछले दिनों राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन गडकरी के लखनऊ आगमन पर भी उसके कद्दावर कहे जाने वाले नेता आपसी बैर भुलाकर एक होते नहीं दिखे. दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी अभी भी सत्तारूढ़ बसपा सरकार के ख़िलाफ़ प्रमुख प्रतिद्वंद्वी दल के रुप में ख़ुद को स्थापित नहीं कर पा रही है. बिहार के चुनाव परिणाम ने भाजपा को उत्साहित ज़रूर किया है, लेकिन केवल उत्साह से काम बनने वाला नहीं है. उत्तर प्रदेश में भी नीतीश और मोदी बन कर दिखाने की क्षमता उत्तर प्रदेश के भाजपा नेताओं में नहीं दिख रही है.

प्रदेश की मुख्य विपक्षी पार्टी समाजवादी पार्टी की स्थिति भी अंदरूनी मार झेल रही है. सपा सुप्रीमो मुलायम सिंह यादव की राजनीतिक पैंतरेबाज़ी से समाजवादी पार्टी की साख़ और विश्वसनीयता को लेकर आमजन में संदेह उपजा है. कभी कांग्रेस पार्टी की बगलगीरी तो कभी कल्याण सिंह जैसे हाशिए पर खड़े लोगों के साथ राजनीतिक युगलबंदी ने उनकी सियासी सलाहियत को कमजोर किया है. पिछले दिनों न्यायालय द्वारा सुनाए गये अयोध्या फ़ैसले पर उनके हैरतअंगेज और ग़ैर वाज़िब बयान को लेकर भी लोगों में नाराज़गी बढ़ी है. मुस्लिम मतों के ध्रुवीकरण में जुटी समाजवादी पार्टी आजम ख़ान को पुचकार कर अपने पाले में तो ज़रूर ला रही है लेकिन उनकी वापसी समाजवाद को किस हद तक ताक़त देगी यह तो आने वाला वक्त ही तय करेगा. आजम की वापसी को लेकर भी सपा के तमाम मुस्लिम विधायकों में बग़ावती बीज पनपने लगे हैं. क्या पता कि मिशन 2012 नजदीक आते–आते टिकट बंटवारे को लेकर एक बार फिर सुर, लय और ताल बिगड़ते नज़र आएं.

feedback@chauthiduniya.com

अब तो ग़रीबी में आटा भी नहीं गीला होता

कमला प्रसाद गुप्त

ग़रीबी में आटा गीला हो गया. यह जुमला आम बातचीत में अक्सर ही इस्तेमाल होता रहा है लेकिन महंगाई के इस दौर में लोग अब यह कहने भर से ही डरते हैं. महंगाई ने ग़रीब आदमी की रसोई में इतना आटा ही नहीं छोड़ा है कि वह गीला हो सके. आम आदमी की यह दुर्दशा देखकर ही सुप्रीमकोर्ट ने कहा था कि अनाज गोदामों में पड़ा सड़ रहा है, इसलिए सरकार को चाहिए कि वह इसे ग़रीबों में बांट दे. केंद्र सरकार ने इस पर अमल तो नहीं किया, उल्टे प्रधानमंत्री डॉ. मनमोहन सिंह ने टिप्पणी की कि सुप्रीमकोर्ट नीति निर्धारण के मामलों में दखल न दे. इस मामले में सरकार को ही निर्णय लेने दे. मनमोहन सिंह यह भी कह गए कि तेंदुलकर समिति के मुताबिक़ देश में ग़रीबों की संख्या कुल आबादी का 37 प्रतिशत है. ऐसे में सबको मुफ्त अनाज देना संभव नहीं है. सुप्रीमकोर्ट को प्रधानमंत्री के इस टके से जवाब के बाद ग़रीब की क्या मजाल जो वह राज्य सरकार, ज़िला आपूर्ति अधिकारी या फिर कोटेदार से यह पूछ सके कि उसके हिस्से का सरकारी राशन कहां जाता है? जेब में अगर पैसा हो तो ग़रीब बाज़ार से महंगा राशन ख़रीदकर परिवार का पेट पालता है, अन्यथा पानी पीकर हरि भजन करता है.

ग़रीबों को राशन बांटने की व्यवस्था में काफ़ी गड़बड़झाला है. सरकारी तंत्र वर्ष 1991 की जनगणना के आधार पर ही एपीएल, बीपीएल और अंत्योदय कार्डधारकों की लिस्ट तैयार करता है. वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार उस समय उत्तर प्रदेश की आबादी 16 करोड़ 60 लाख 52 हज़ार 859 थी. इनमें 87,466, 301 पुरुष और 78,586,558 महिलाएं शामिल थीं. वहीं वर्ष 1991 की जनगणना में उत्तर प्रदेश की जनसंख्या 13 करोड़ 19 लाख 98 हज़ार 804 थी. वर्ष 1991 से 2001 के बीच उत्तर प्रदेश की आबादी में क़रीब साढ़े तीन करोड़ का इज़ाफ़ा हुआ. अब वर्ष 2010 ख़त्म होने को है. 2001 से 2010 के बीच आबादी में चार से पांच करोड़ की बढ़ोतरी होना तय है. लेकिन सरकार को यह दिखाई नहीं देता है. यह संवेदनहीनता उस समय है जबकि सुप्रीमकोर्ट भी स्वीकार कर चुका है कि बीस वर्षों में देश की जनसंख्या 75 फ़ीसदी बढ़ी है. जाहिर है कि बीपीएल परिवारों की संख्या भी बढ़ी है. ऐसे में बढ़ी हुई जनसंख्या के आधार पर बीपीएल परिवारों का चयन होना चाहिए. उच्चतम न्यायालय गंभीर है लेकिन सरकार और नौकरशाह बेअंदाज़ हैं. उन्हें ग़रीबों की कोई चिंता नहीं है जिनके वोटों की बदौलत वह ऐश करते हैं और सत्ता की मलाई खाते हैं. ग़रीब बेचारे को जूठन तक नसीब नहीं होने देते.

उदाहरण के तौर पर उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ ज़िले को ही लें तो यहां वर्ष 1991 की जनगणना के आधार पर ही सरकारी राशन बांटने की व्यवस्था है. इसके तहत ज़िले भर में एपीएल कार्ड धारकों की संख्या छह लाख 48 हज़ार 501 है. बीपीएल कार्ड धारक एक लाख 70 हज़ार 736 और अंत्योदय कार्ड धारक एक लाख पांच हज़ार 783 है. वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार आजमगढ़ की जनसंख्या 39 लाख 50 हज़ार 808 थी जबकि वर्ष 1991 में आजमगढ़ की आबादी 32 लाख 53 हज़ार 572 थी. इन दस सालों में आजमगढ़ की आबादी में क़रीब सात लाख का इज़ाफ़ा हुआ. जाहिर है कि वर्ष 2001 से 2010 के बीच आबादी इसी रफ्तार से बढ़ी है. लेकिन ग़रीबों के सरकारी आंकड़े का राग वर्ष 1991 की जनगणना की ताल पर ही अलापा जा रहा है. सरकार बीपीएल कार्ड धारकों को 35 किलोग्राम राशन मुहैया कराती है. इसमें गेहूं 4.65 रुपए प्रति किलोग्राम और चावल 6.15 रुपए प्रति किलोग्राम मिलता है. वहीं एपीएल कार्ड धारकों को ग्रामीण इलाक़े में 6.60 रुपए प्रति किलोग्राम और शहरी क्षेत्र में 8.95 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से गेहूं मिलता है. एपीएल कार्डधारकों को चावल 8.80 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से मुहैया कराने की सरकारी व्यवस्था है. इसी तरह अंत्योदय कार्डधारकों को दो रुपए प्रति किलोग्राम की दर से गेहूं और तीन रुपए प्रति किलोग्राम की दर से चावल देने का प्रावधान है. लेकिन यह सब काग़ज़ों में है. पहले एपीएल परिवारों को चावल दिए जाने की कोई व्यवस्था नहीं थी. साल 2010–11 में एपीएल परिवारों को भी गेहूं के साथ चावल दिलाए जाने की व्यवस्था की गई. आजमगढ़ के ग़रीबों का दुर्भाग्य है कि एपीएल, बीपीएल और अंत्योदय कार्ड होने के बाद भी उन्हें सरकारी राशन नहीं मिल पाता है. यह हाल केवल आजमगढ़ का नहीं है बल्कि प्रदेश के सभी जनपदों में ग़रीबों के सरकारी राशन वितरण की यही हक़ीक़त है. ग़रीब आदमी अपना काम धंधा छोड़कर जब कोटेदार के पास राशन लेने जाता है तो उसे दुकान पर एक बोर्ड टंगा दिखाई देता है. इस बोर्ड पर लिखा होता है कि कोटेदार गोदाम पर राशन लेने गए हैं. सरकारी राशन के चक्कर में उसकी दिनभर की दिहाड़ी भी मारी गई और गेहूं–चावल के बग़ैर लौटना पड़ा. दोबारा सरकारी दुकान जाने पर फिर तख्ती ही टंगी मिलती है जिस पर लिखा होता कि अभी राशन नहीं आया है. इस तरह ग़रीब केवल दुकान के चक्कर ही काटता रह जाता है. किस्मत से अगर दुकानदार मिल भी गया तो उसे साफ़ तौर पर कह दिया जाता है कि अभी शासन से ही अनाज नहीं मिला है. ऐसे में वह (कोटेदार) अपने घर से तो गेहूं–चावल बांटने से रहा. ग़रीब जब ज़िला आपूर्ति कार्यालय जाता है तो उसे वहां से भी सही जानकारी नहीं मिलती. अधिकारी–कोटेदार का मजबूत गठजोड़ ग़रीब के पेट पर लात मारता रहता है. सरकारी राशन गोदाम से सीधे खुले बाज़ार पहुंचा दिया जा रहा है. मार्केट से इसी सरकारी राशन को ग़रीब महंगे दाम पर ख़रीदने के लिए विवश हैं.

एक जनवरी, 2009 से 31 मार्च 2010 के 15 महीनों में ग़रीबों को तक़रीबन छह माह का गेहूं नहीं मिल पाया था. इसी तरह अप्रैल, 2010 से अक्टूबर, 2010 की तस्वीर देखी जाए तो आजमगढ़ नगर के एपीएल परिवारों को मई और जून माह में प्रति कार्ड 6.60 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से सात किलो गेहूं, तथा सितंबर, 2010 में 8.95 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से सात किलो गेहूं मुहैया कराया जा सका है. अप्रैल, जुलाई, अगस्त, सितंबर तथा अक्टूबर माह का 6.60 रुपए प्रति किलो मिलने वाला ग़रीबों के हिस्से का गेहूं तथा जुलाई, अगस्त तथा अक्टूबर माह का 8.95 रुपए प्रति किलो मिलने वाला अतिरिक्त गेहूं कहां गया, यह बताने वाला कोई अधिकारी नहीं है. एपीएल परिवारों को अब तक किलोग्राम में तो दूर दाने में भी सरकारी राशन का दर्शन नहीं हो सका है. यह एक गंभीर मामला है. इसलिए इसकी जांच होनी चाहिए. मजेदार बात तो यह है कि आजमगढ़ ज़िले की दूसरी नगरपालिका मुबारकपुर में हर माह का अनाज ग़रीबों को दिलाया गया. क्योंकि उस क्षेत्र के एक वरिष्ठ बसपा नेता ने मुबारकपुर नगर के ग़रीबों के हक़ को दिलाने में अपने कद का इस्तेमाल किया लेकिन अन्य जनप्रतिनिधि ऐसा नहीं कर सके. ग़रीबों को राशन नहीं मिलने के बाबत आवाज़ उठाने से विधायक व सांसद परहेज करते हैं. महंगाई की मार से आम आदमी बुरी तरह से त्रस्त है. पहले लोग कुछ नुक़सान होने पर कह लेते थे कि ग़रीबी में आटा गीला हो गया लेकिन महंगाई के इस दौर में रसोई में आटा ही नहीं है, फिर वह गीला कैसे होगा.

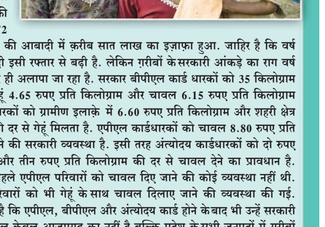

feedback@chauthiduniya.com

वर्ल्ड म्यूज़िक की ग्लोबल सिटी लखनऊ

भारत में संगीत की विद्यालीय शिक्षण परंपरा शुरू करने का श्रेय बीसवीं शताब्दी में दो महान संगीतज्ञों महर्षि पंडित विष्णु दिगंबर पलुस्कर व पंडित विष्णु नारायण भातखंडे को जाता है. वर्ष 1926 में लखनऊ में तत्कालीन संगीत रसिक राय उमानाथ बली, राय राजेश्वर बली व अन्य संगीत प्रेमियों के सहयोग से पंडित विष्णु नारायण भातखंडे ने एक संगीत संस्था की नींव डाली.

हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत की झंकार हो और शहर–ए–अदब लखनऊ का जिक्र न आए, यह कतई मुमकिन नहीं है. लखनऊ अब वर्ल्ड म्यूजिक (विश्व संगीत) की ग्लोबल सिटी के तौर पर अपनी पहचान बनाने जा रहा है. लखनऊ को यह गौरव दिलाने का श्रेय भातखंडे संगीत संस्थान सम विश्वविद्यालय को जाता है, जो वर्ष 1926 से हिंदुस्तानी संगीत का अनवरत प्रचार–प्रसार कर रहा है. इस संस्थान में पद्मभूषण बेगम अख्तर, पद्मभूषण उस्ताद रहीमुद्दीन खां डागर, उस्ताद युसूफ अली खां, पद्मभूषण उस्ताद अहमद जान थिरकवा तथा प्रो. वीजी जोग जैसे ख्यातिलब्ध संगीतज्ञ शिक्षक के रूप में कार्यरत रहे हैं. भारत में संगीत की विद्यालीय शिक्षण परंपरा शुरू करने का श्रेय बीसवीं शताब्दी में दो महान संगीतज्ञों महर्षि पंडित विष्णु दिगंबर पलुस्कर व पंडित विष्णु नारायण भातखंडे को जाता है. वर्ष 1926 में लखनऊ में तत्कालीन संगीत रसिक राय उमानाथ बली, राय राजेश्वर बली व अन्य संगीत प्रेमियों के सहयोग से पंडित विष्णु नारायण भातखंडे ने एक संगीत संस्था की नींव डाली. आज़ादी के बाद 26 मार्च, 1966 को राज्य सरकार ने इस संस्था को अपने अधिकार में लेते हुए इसका नामकरण भातखंडे हिंदुस्तानी संगीत महाविद्यालय किया. 24 अक्टूबर, 2000 को इस संस्थान को समविश्वविद्यालय घोषित किया गया. विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की अधिसूचना के अनुसार अब इसे विश्वविद्यालय के रूप में मान्यता प्राप्त है. उस दौर में कोठेवालों के पास सबसे अधिक बंदिशें होती थी जिनके पास जाकर, उनकी मनुहार करके पंडित विष्णु नारायण भातखंडे ने बंदिशों का संग्रह किया और फिर उन्हें स्वरबद्ध कर प्रकाशित किया. यहां न केवल भारत के विभिन्न प्रांतों बल्कि नेपाल, श्रीलंका, मॉरीशस, जर्मनी, जापान, भूटान, फ्रांस, अफ़ग़ानिस्तान से विद्यार्थी हिंदुस्तानी संगीत की शिक्षा लेने आते हैं.

संस्थान प्रयास कर रहा है कि वर्ष 2011 से यहां वर्ल्ड म्यूजिक (विश्व संगीत) की शिक्षा शुरू की जा सके. देश–विदेश के छात्रों के यहां आने से वर्ल्ड म्यूजिक के कॉन्सेप्ट की ज़रूरत काफ़ी समय से महसूस की जा रही थी. इसके जरिए छात्रों को पूर्वी व पश्चिमी देशों के संगीत की थोड़ी–थोड़ी जानकारी दी जाएगी ताकि वह अपनी प्रतिभा में और निखार ला सकें. संगीत के जरिए रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने का श्रेय इस संस्थान को ही जाता है. यहां से विभिन्न विधाओं में बीपीए, एएमपीए और पीएचडी व अन्य डिग्री हासिल कर छात्र–छात्राएं विभिन्न स्कूल–कॉलेजों में संगीत शिक्षक के रूप में नौकरी पा रहे हैं तो संगीत के क्षेत्र में स्वतंत्र रूप से अपना करियर बना रहे हैं. इनमें प्रसिद्ध भजन गायक अनूप जलोटा, गायिका सपना अवस्थी व मालिनी अवस्थी, रवि नागर, श्रीमती पूर्णिमा पांडे, श्रीमती दिलराज कौर व कई हस्तियां शामिल हैं, जिन्होंने यहां से संगीत का सारेगामा सीखने के बाद अपनी एक अलग पहचान बनाई. साथ ही दौलत व शोहरत भी हासिल की. यहां जो संगीत को अपना करियर नहीं बना पाते, वह मंचीय कलाकार भले न बन सकें लेकिन मंचीय कलाकारों की कला का रसपान बखूबी करते हैं जो अन्य आम श्रोता के लिए संभव नहीं होता.

भातखंडे संगीत संस्थान में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की ओर से निर्धारित मानकों के अनुरूप सत्र 2001–02 से शास्त्रीय संगीत की विभिन्न विधाओं में बीपीए, एमपीए और पीएचडी स्तर की शिक्षा प्रारंभ की गई. संगीत की प्रदर्शनात्मक कलाओं को सीखने के लिए कम आयु वर्ग के विद्यार्थियों की सुविधा के मद्देनज़र पहले से संचालित पाठ्यक्रमों की कक्षाओं को भी संस्थान में यथावत चलाने का निर्णय लिया गया ताकि जो विद्यार्थी बीपीए व एमपीए के लिए निर्धारित अर्हताएं पूरी न करते हों, उन्हें भी संगीत की शिक्षा प्राप्त करने में दिक्कत न हो. भारतीय संगीत को और अधिक लोकप्रिय व उपयोगी बनाने के लिए सत्र 2004–05 से इसके पाठ्यक्रम में सुधार किया गया. बीपीए व एमपीए का पाठ्यक्रम विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के निर्देशों के अनुरूप लागू करने का निर्णय लिया गया. छात्रों की रुचि को ध्यान में रखते हुए एमपीए के पाठ्यक्रम में उन्हें व्यावसायिक कलाकार, संगीत शास्त्री व संगीत शिक्षक और संगीत रचनाकार के रूप में अपनी कला के निखार का अवसर भी प्रदान किया गया. वर्तमान समय में संस्थान में 1350 छात्र–छात्राएं संगीत के सुर, लय व ताल की शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं.

संस्थान से जुड़े कई बड़े नाम

- पद्म भूषण श्री कृष्ण नारायन रातंजनकर
- बड़े आगा
- उस्ताद आबिद हुसैन खां
- मृदंगाचार्य पंडित सखाराम जी
- उस्ताद युसूफ अली खां
- पद्मश्री बेगम अख्तर
- पद्मश्री श्री विष्णु गोविंद जोग
- उस्ताद इलियास खां
- श्री गोविंद नारायन नातू
- उस्ताद रहीमउद्दीन दागुर
- उस्ताद सखावत हुसैन खां
- पद्मभूषण उस्ताद अहमद जान थिरकुवा
- पंडित केजी गिंडे (ध्रुपद धमाल गायन)
- एससीआर भट्ट
- दिनकर कायकेणी
- सुमति मोटाटकर
- चिदानंद नगरकर
- श्रीमती दिलराज कौर
- भजन गायक अनूप जलोटा
- सपना अवस्थी
- श्रीमती पूर्णिमा पांडे
- श्रीमती मालिनी अवस्थी

चौथी दुनिया ब्यूरो
feedback@chauthiduniya.com

वरुणा नदी वाराणसी शहर के मध्य से होकर गुज़रती है. एक तरफ़ पुराना तो दूसरी तरफ़ नया शहर बसा है.

लुप्त होतीं नदियां

अस्सी और वरुणा की करुण कथा

बनारस की पहचान है गंगा. हो सकता है कि अस्सी और वरुणा जैसी नदियों के नाम से आप परिचित न हों. ये दोनों ऐसी नदियां हैं जो सदियों से बनारस को बाढ़ और सूखे से बचाती रही हैं, लेकिन आज ये ख़ुद को बचाने के लिए संघर्ष कर रही हैं. इनके किनारे इमारतों और पांच सितारा होटलों का निर्माण हो रहा है. इसकी चिंता न तो सरकार को है और न ही जनता इस बारे में जागरूक हैं. ज़रूरी है कि सरकार इनकी करुण पुकार को जल्द से जल्द सुने.

- **वरुणा नदी के पानी में ऑक्सीजन की मात्रा लगातार घट रही है**
- **जबकि इसके पानी में फ्लोराइड की मात्रा लगातार बढ़ती जा रही है**
- **वरुणा और अस्सी नदी में सीवर और नाले का गंदा पानी गिरता है**
- **इनके किनारों पर होटल और बड़ी इमारतों का निर्माण हो रहा है**

प्रियंका प्रियम तिवारी

मोक्ष की नगरी काशी में गंगा के अलावा भी दो छोटी नदियां बहती हैं. ये नदियां है अस्सी और वरुणा. काशी का नाम वाराणसी शहर के मध्य बहने वाली दो पौराणिक नदियों वरुणा एवं असि (अस्सी) को मिलाकर ही बना है. ये गंगा में कभी कभार आने वाले बाढ़ के पानी से नगर की रक्षा करती है. वर्षों से गंगा की बाढ़ से नगर की रक्षा करने वाली इन नदियों का अस्तित्व ख़तरे में है.

अस्सी नदी तो भू–माफियाओं के लालच की भेंट चढ़ गई. अतिक्रमण करके अस्सी नदी को भरकर मकान और होटल बना दिया गया है. साथ ही इससे क्षेत्र के सारे सीवर और नाले जुड़े हुए हैं. जिससे यह नदी मात्र एक गंदे नाले में तब्दील हो कर रह गई है. अस्सी की राह पर अब वरुणा नदी भी है. वरुणा नदी इलाहाबाद के संगम के मैलहन झील से निकलकर काशी में गंगा में समाहित होती है. इलाहाबाद से काशी तक के सफ़र में यह नदी कितने ही लोगों को रोजगार मुहैया कराती थी. इसके पानी से लोग छोटे मोटे कृषि कार्य करते थे. फल–फूल और सब्जियां उगाकर बेचते थे जो उनके जीविकोपार्जन का मुख्य साधन था. पर अब इस नदी के सूखने से उनके जीवन यापन पर भी सवालिया निशान खड़ा हो गया है. इस नदी का ऐतिहासिक महत्व है, माना जाता है कि यह नदी भगवान विष्णु के चरणों से निकली है. देवताओं ने वरुण देवता के नाम पर इस नदी का नाम वरुणा रखा. यह नदी अथर्ववेद में वरुणावती, महाभारत के भीष्म पर्व में वाराणसी, मत्स्यपुराण में वाराणसी एवं तीर्थचिंतामणि में वाराणसी के नाम से जानी जाती है. साथ ही बौद्ध ग्रंथ, कुर्म पुराण, पद्म पुराण, अग्निपुराण में भी इस नदी का जिक्र मिलता है.

वरुणा नदी वाराणसी शहर के मध्य से होकर गुजरती है. एक तरफ़ पुराना तो दूसरी तरफ़ नया शहर बसा है. बढ़ती जनसंख्या और पर्यावरण के प्रति उदासीनता के चलते वरुणा नदी सूखने लगी है. ग्रामीण क्षेत्रों के साथ ही पूरे शहरी क्षेत्रों के सीवेज और और छोटे बड़े कई नाले आकर इस नदी में मिल जाते हैं. साथ ही प्रतिदिन पशुओं के शव और कसाईखाने के अवशेष, होटलों के अवशिष्ट पदार्थ वरुणा में ही आकर गिरते हैं. वरूणा के किनारे स्थित होटलों, चिकित्सालयों एवं रंगाई वाले फैक्ट्रियों के रंग भी इसी में बहते हैं. वरुणा के पानी में प्रदूषण का यह आलम है कि अब इसके पानी में मछलियां भी नहीं रहती. पशु, पक्षी इस नदी के आस पास नहीं दिखते. शोध से पता चला है कि वरुणा के जल में अब ऑक्सीजन की मात्रा नहीं रह गई है.

भारत सरकार के पर्यावरण मंत्रालय ने इस नदी को (डेड रिवर्स) मृत नदियों की सूची में शामिल कर लिया है. वरुणा का पानी इतना प्रदूषित है कि टॉक्सिक लिंक के द्वारा वरुणा तट पर स्थित लोहता और शिवपुर में उगाई जा रही सब्जियों के अध्ययन से यह निष्कर्ष प्राप्त हुआ है कि इनमें जिंक, क्रोमियम, मैग्नीज निकेल कैडमियम कॉपर लेड की मात्रा विश्व स्वास्थ्य संगठन के मानक से अत्यधिक है जो मानव जीवन के लिये अत्यंत घातक है. नदी के तटवर्ती इलाक़ों में पेट, आंत, लीवर संबंधी बीमारियों के साथ–साथ चर्म रोग आम बात है. नदी के सूखने से आस पास के क्षेत्रों में भू–जल स्तर की समस्या बढ़ रही है. इसे जिंदा रखने के लिए नहरों से पानी छोड़ा गया, लेकिन पानी कम और सिल्ट ज़्यादा आने लगी. नदी की सफ़ाई न होने से सिल्ट नदी में हर तरफ़ जमा हो गई. इससे वरुणा काफ़ी उथली हो गई. परिणामत: अब झील और नदी में बरसाती पानी भी एकत्र नहीं हो पाता. नतीजतन, वाराणसी, भदोही और जौनपुर में भूजल काफ़ी तेजी से नीचे जा रहा है. यह नदी राजघाट से लेकर फुलवरिया के लगभग 20 किमी क्षेत्र तक बदबूदार गंदे नाले में तब्दील हो गई है. मात्र इसके बीस किलोमीटर के क्षेत्र में बड़े–बडे सीवर, ड्रेनेज बह रहें हैं.

नदी के किनारे जीवन का आनंद लेने के लिए और पर्यटकों को लुभाने के लिए इस नदी के किनारे पंचसितारा होटल, कालोनियां और बड़े इमारतों का निर्माण हो रहा है. इसके लिए वरुणा को पाटा जा रहा है. साथ ही इनका कूड़ा और नाले इसी में बहाए जाते है. हमारी वरुणा के सह संयोजक सूर्यभान जी कहते हैं कि जब सरकार ही इसे गंदा करने पर तुली है तो क्या कहा जाए. नगर निगम ने तो वरुणा के तट को कूड़ाघर ही बना डाला है. गंगा की सफ़ाई की बात तो होती है पर वरुणा कि तरफ़ किसी का ध्यान भी नहीं है. गंगा को साफ़ रखना है तो वरुणा को भी साफ़ रखना ही होगा. क्योंकि वरुणा गंगा में ही जाकर मिलती है. फिर गंगा को साफ़ करने का क्या फ़ायदा. सरकार का आदेश है कि किसी भी नदी के एक ख़ास दायरे में आवास का निर्माण नहीं होनी चाहिए. पर इस आदेश का यहां खुलेआम उल्लंघन हो रहा है, कुछ दूरी पर ही जनपद मुख्यालय और प्रशासनिक अधिकारियों के आवास हैं लेकिन उनकी इस पर कही भी नज़र नहीं है. सरकार इस तरफ़ से निरंतर चेतनाशून्य बनी बैठी है.

बड़ी नदियों के बावजूद छोटी नदियों का भी महत्व है. बड़ी नदियों में कभी कभी आने वाले बाढ़ के पानी को ये छोटी नदियां ख़ुद में एकत्र कर लेती है और बाढ़ से आनेवाली संकट को टालती है. वरुणा बचाओं आंदोलन के संयोजक डॉ. व्योमेश चित्रवंश कहते है कि वरूणा नही रहेगी तो काशी भी नहीं रहेगी. काशी को बचाने के लिए गंगा के साथ ही वरुणा को भी बचाना होगा. वरुणा गंगा की कटान को रोककर नगर के भूमिगत जलस्तर को संतुलित रखती है. गंगा और वरुणा की महत्ता उसके जल की मात्रा, गुणवत्ता व वेग से है. दोनों में इन तीनों का आनुपातिक अंतर लगभग 30 गुना है. यही आनुपातिक अंतर ही एक दूसरे को बचाने का काम करती हैं. गंगा के डाउन स्टीम में दोनों का संगम 75 से 80 डिग्री का कोण बनाती है जो गंगा के कटान को रोकने में सहायक साबित होती है. यहां गंगा के किनारे के जल का आवेग और वरुणा के बीच का आवेग टकराने के बाद संगम क्षेत्र के जल प्रवाह को वेग शून्य कर देती है. लिहाज़ा संगम तट पर जहां वरुणा द्वारा मिट्टी जमाव की क्रिया आरंभ हो जाती है वहीं वेग शून्यता के चलते गंगा की मिट्टी की कटाव की प्रक्रिया समाप्त हो जाती है. हालांकि वरुणा को बचाने के लिए कई बड़े नाम जुड़े पर सबने राजनीतिक रोटी ही सेंका. वरुणा अपनी गतिशीलता के अनुपात में गंगा के किनारे–किनारे मिट्टी का मेड़ बनाकर उसके जलस्तर को बढ़ाने का काम करती है. ऐसे में वरुणा का जल जैसे जैसे दूषित और गतिहीन होता जाएगा गंगा का किनारा असुरक्षित, दूषित और शहर के भूजल व मृदा क्षरण का वेग उसी अनुपात में गंगा की ओर बढ़ता जाएगा. इससे साफ़ जाहिर है कि यहां गंगा किनारे की स्थिरता वरुणा ही प्रदान करती है. आज गंगा के किनारे बढ़ती गहराई और कटान की वजह वरुणा के आवेग का दिनोंदिन घटना है. लिहाज़ा गंगा–वरुणा में जल की क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों को समान रूप से बचाने की ज़रूरत है. तभी शहर को बचाया जा सकेगा. डॉ. पीके मिश्रा के अनुसार इस क्षेत्र में भूजल में फ्लोराइड की मात्रा मिली है. वरुणा के दोनों किनारों पर फुलवरिया से सलारपुर के बीच 30 स्थानों से सैंपल लिए गए. लैब में इनकी जांच की गई तो दो मिलीग्राम प्रतिलीटर से अधिक के हिसाब से फ्लोराइड मिला है. उन्होंने बताया कि लगभग तीन सौ फीट नीचे से पानी का सैंपल लिया गया था. यह सैंपल कोटवा, फुलवरिया, पुरानापुल, सलारपुर, रुस्तमपुर, लेढ़ूपुर आदि से सैंपल लिए गए थे. फ्लोराइड स्वास्थ्य के लिए ख़तरनाक है. इससे दांत और हड्डियां कमजोर हो जाती हैं. रक्त संबंधी बीमारियां भी होती हैं साथ ही इससे कैंसर भी हो सकता है.

आज से बीस साल पूर्व तक वरुणा नदी काफ़ी गहरी हुआ करती थी. सालो भर जल से भरी रहती थी. आस–पास के ग्रामवासी खेती, पेयजल, दैनिक क्रियाकलाप, श्राद्ध तर्पण और पशुपालन के लिए इस पर निर्भर रहते थे. इसके तट पर कई प्रकार के वनस्पतियों जैसे नागफनी, घृतकुमारी, सेहुड़, पलाश, भटकैया, पुनर्नवा, सर्पगंधा, चिचिड़ा, शंखपुष्पी, ब्राह्मी, शैवाल, पाकड़ की बहुतायत मात्रा हुआ करती थी. जिससे वरुणा के पानी में विषहारिणी शक्ति होती थी, और यह पानी एंटीसेप्टिक का कार्य करती थी.

feedback@chauthiduniya.com

वरुणा सिर्फ़ गंगा के कटाव क्षेत्र को भरने का ही काम नहीं करती, वरन् गंगा की ओर भूमिगत जल प्रवाह को अपनी ओर खींच कर रिसाव के दबाव को कम करने का भी काम करती है. वरुणा अपनी गतिशीलता के अनुपात में गंगा के किनारे-किनारे मिट्टी की मेड़ बनाकर उसके जलस्तर को बढ़ाने का काम करती है.

चौथी दुनिया

बिहार झारखंड

दिल्ली, 13 दिसंबर-19 दिसंबर 2010

www.chauthiduniya.com

अफसरशाही पर

नीतीश नकेल कसेंगे

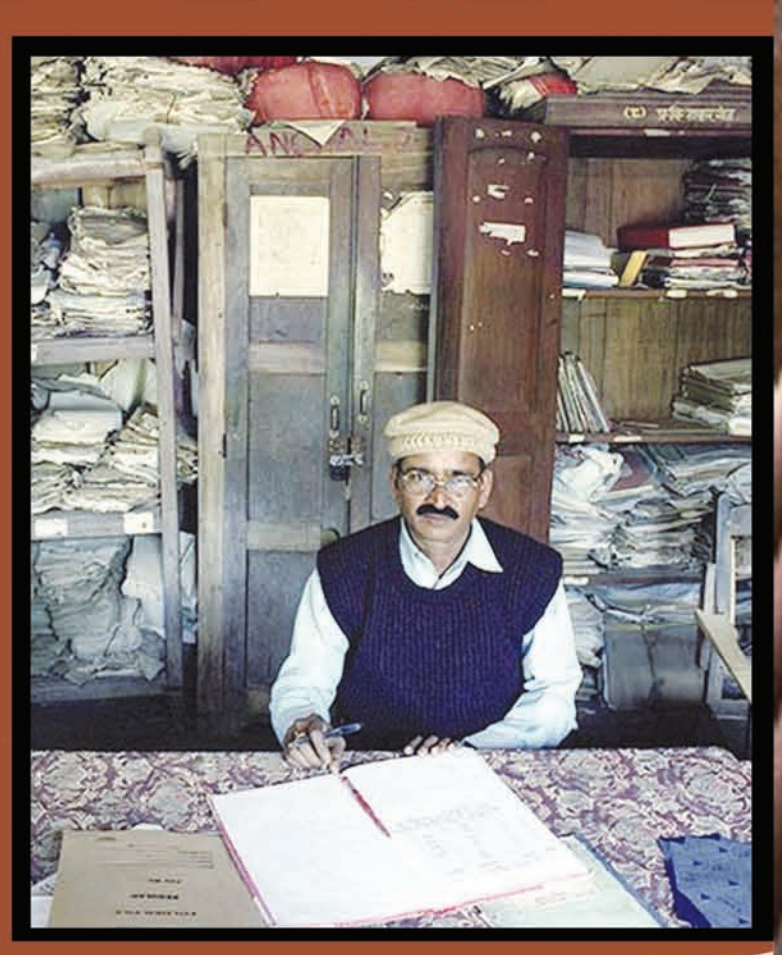

नीतीश समझ चुके हैं कि जनता ने उन्हें प्रचंड जनादेश किस लिए दिया है. सो, कुर्सी संभालते ही लापरवाह अफसरों पर शिकंजा कसने की योजनाओं पर काम शुरू हो गया है. राइट टू सर्विस एक्ट की घोषणा हो गई है. आने वाले दिनों में इसके दूरगामी परिणाम दिखेंगे.

सरोज सिंह

नीतीश कुमार जनता से प्रचंड जनादेश पाने के बाद एक बड़ा कदम उठाने जा रहे हैं. बेलगाम अफसरशाही पर नकेल कसना उनकी पहली प्राथमिकता बन गया है. हालांकि नीतीश कुमार बार-बार यह कहते रहे हैं कि राज्य में कहीं अफसरों का बोलबाला नहीं है और सरकारी अधिकारी जनता के हित में उनकी भावनाओं को ध्यान में रखकर फ़ैसले लेते रहे हैं. लेकिन इस बार चुनाव प्रचार के दौरान और इससे ठीक पहले की यात्राओं में उन्हें जनता एवं अपने कार्यकर्ताओं से अफसरशाही के ख़िलाफ़ जो फीडबैक मिला, उससे वह इस मसले पर सोचने को तैयार हुए और जल्द ही समस्या निपटाने के लिए कार्ययोजना को अमलीजामा पहनाने की तैयारी शुरू हो गई. इस बार उनकी पंचलाइन है, अफसरों को जनता के प्रति पूरी तरह ज़िम्मेदार बनाना. इन योजना में सरकारी कार्यालयों में भ्रष्टाचार और छोटे-छोटे कामों में लेटलतीफी को दूर करना शामिल है. जनता एवं कार्यकर्ताओं का भरोसा बरकरार रखने के लिए नीतीश कुमार इस काम को ज़मीन पर उतारने के लिए जुट गए हैं.

दरअसल नीतीश कुमार जहां भी गए, कार्यकर्ताओं ने उनसे यही कहा कि सब कुछ ठीक है, पर अफसर हमारी बात नहीं सुनते हैं. जैसा जनादेश मिला है, उसके मुताबिक कार्यकर्ताओं एवं जनता की भावनाओं को तवज्ज़ो देना ज़रूरी है. इसलिए सत्ता संभालते ही नीतीश कुमार ने ऐलान कर दिया कि सरकारी दफ्तरों की कार्य संस्कृति बदली जाएगी और भ्रष्टाचार को जड़ से ख़त्म किया जाएगा. जनता को छोटे-मोटे कामों के लिए अब महीनों अधिकारियों के आगे-पीछे चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे और समय पर सारे काम पूरे होंगे. जनता से जुड़ी हर सेवा के लिए विभागों में समय सीमा तय कर दी जाएगी. इन कामों के लिए सरकार राइट टू सर्विस एक्ट को अपना हथियार बनाने जा रही है. इस एक्ट के माध्यम से सर्विस डिलीवरी सिस्टम को पटरी पर लाया जाएगा, जिससे जनता का हर काम तय समय सीमा के अंदर होगा. समय पर सेवा न दे पाने वाले अधिकारियों से जुर्माना भी वसूला जाएगा. नीतीश कुमार ने महसूस किया कि आम लोगों को सबसे ज़्यादा तकलीफ दफ्तरों के चक्कर काटने में होती है. इससे छुटकारा दिलाने के लिए नीतीश कुमार ने प्रशासनिक सुधार की दिशा में पहल कर क़ानून की रूपरेखा तय करने का निर्देश दे दिया है.

संभावना है कि सरकार अगले सत्र में यह क़ानून लागू कर देगी. राइट टू सर्विस एक्ट के लागू हो जाने से अफसर किसी भी काम को अधूरा छोड़ने लिए बहाना नहीं बना पाएंगे. समय पर काम करना उनकी मजबूरी हो जाएगी, नहीं तो उन्हें भारी जुर्माना भरना होगा. इसी तरह अफसरों के भ्रष्टाचार के ख़िलाफ़ सरकार का अभियान पंचायती राज संस्थाओं और शहरी निकायों से शुरू होने जा रहा है. इन संस्थाओं में भ्रष्टाचार की शिकायतों की जांच और कार्रवाई के लिए सरकार एक स्वतंत्र एजेंसी का गठन करने जा रही है. स्थानीय निकायों के खातों के संचालन और ख़र्च पर नज़र रखने के लिए इलेक्ट्रॉनिक प्रणाली विकसित की जा रही है. इससे विकास योजनाओं में केंद्र और राज्य के हिस्से की राशि पांच दिनों में ही निकायों को मिल जाएगी. सरकार की सोच है कि अगर निचले स्तर पर भ्रष्टाचार पर क़ाबू पा लिया गया तो काम आसान हो जाएगा. ज़िला परिषद, पंचायत समिति, ग्राम पंचायत एवं शहरी निकायों के जन प्रतिनिधियों, अधिकारियों और कर्मचारियों के कामों पर भी नजर रखी जाएगी. सरकार नगरपालिकाओं और नगर निगमों में संपत्ति कर की दरों के निर्धारण और वसूली के लिए राज्यस्तरीय संपत्ति कर बोर्ड का भी गठन करने जा रही है.

सरकार को बार-बार यह शिकायत भी मिलती रहती थी कि कुछ बड़े अधिकारी पटना के बजाय दिल्ली में अपना समय ज़्यादा बिताते हैं. कुछ का हाल यह था कि वे शुक्रवार की शाम दिल्ली चले जाते थे और फिर सोमवार को आते थे. इन्हीं शिकायतों को दूर करने के लिए सरकार ने आईएएस अधिकारियों के बार-बार दिल्ली जाने पर रोक लगा दी है. नए नियम के तहत अब मुख्यमंत्री की अनुमति के बाद ही अधिकारी एक महीने में एक से अधिक बार दिल्ली जा सकेंगे. अधिकारियों को गांव में जाकर लोगों से मिलने के लिए कहा गया है. सरकार ने जो आदेश जारी किए हैं, उनमें कहा गया है कि बैठकों के सिलसिले में अधिकारियों के दिल्ली या राज्य से बाहर जाने से काम प्रभावित होता है. इसलिए कोशिश हो कि महीने में एक बार से ज़्यादा बाहर न जाया जाए. अगर बेहद ज़रूरी हो तो मुख्य सचिव के माध्यम से मुख्यमंत्री का अनुमोदन अनिवार्य होगा. दूसरे बार की इजाज़त तभी मिलेगी, जब अधिकारी इस दौरान गांवों में जाकर सरकारी कार्यक्रमों की समीक्षा कर आएंगे. उस अधिकारी को समीक्षा से संबंधित रिपोर्ट भी सौंपनी होगी. दरअसल सरकार का मक़सद अधिकारियों को सीधे जनता के दरबार में भेजना है. सरकार सोचती है कि अगर बड़े अधिकारी गांवों में जाकर योजनाओं की समीक्षा करेंगे तो उसके दो फ़ायदे होंगे. पहला यह कि लेटलतीफी दूर होगी और दूसरा यह कि इस तरह के विभागों से जुड़ा भ्रष्टाचार क़ाबू में रहेगा. पटना से अधिकारी अगर राज्य के गांवों में जाएंगे तो स्थानीय अधिकारियों पर भी अंकुश रहेगा. इसके अलावा सरकारी कर्मचारियों के लिए दंड एवं पुरस्कार की नीति भी लागू की जा रही है. पहले और बाद में आने वाले कर्मचारी का नाम बोर्ड पर रोजाना नोट होगा. समय पर कामों का निपटारा कराने के लिए कर्मचारियों एवं लिपिकों की हर माह कम से कम दो बैठकें कराने का निर्देश दिया गया है. हर सोमवार को सप्ताह की कार्ययोजना पर विचार होगा और बीते सप्ताह के क्रियाकलापों पर चर्चा होगी. माह में सबसे बेहतर काम करने वाले सर्वश्रेष्ठ कर्मचारी घोषित किए जाएंगे. मतलब सरकार का इरादा साफ़ है कि सचिव से लेकर चपरासी तक की ज़िम्मेदारी तय कर दी जाए. अगर कोई अपनी ज़िम्मेदारी से भागेगा तो उसके लिए दंड का प्रावधान सख्ती से लागू किया जाएगा. लेकिन जो अपनी ज़िम्मेदारियों को समय सीमा में या समय से पहले निपटाएंगे, उन कर्मचारियों को सरकार इनाम भी देगी. ऐसी व्यवस्था की जा रही है कि किसी के साथ कोई भेदभाव न होने पाए और हर कर्मचारी के काम पर सरकार की पूरी नज़र रहे, ताकि किसी को ग़लत फीडबैक का नुक़सान न हो. सरकार यह भी महसूस कर रही है कि यह काम आसान नहीं है. इस काम में आने वाली व्यवहारिक दिक्कतों से कैसे निपटना है, इसके लिए आवश्यक रणनीति बनाई जा रही है. सरकारी कार्यालयों की कार्य संस्कृति बदलने की इस मुहिम में सरकार ने जनता को भी भागीदार बनाने का फ़ैसला किया है. जनता से यह अपेक्षा की जा रही है कि वह अफसरों को परेशान करने वाला कोई काम न करे. उचित कामों को लेकर ही वह अधिकारियों के पास जाए. किसी ग़लत काम के लिए सरकारी कर्मचारियों पर दबाव न डाला जाए. सरकार की यह समझ है कि अगर सब कुछ योजना के मुताबिक़ चला तो जल्द ही बिहार की तस्वीर बदली हुई नज़र आएगी. सरकार को भरोसा है कि जिस तरह का जनादेश नीतीश कुमार को मिला है, उसमें यह काम जरूर होगा. आखिर यह जनादेश तो विकसित बिहार के लिए ही मिला है और इसे अफसर भी समझ रहे हैं और जनता भी.

feedback@chauthiduniya.com

नीतीश कुमार की योजना में अफसरों को जनता के प्रति पूरी तरह ज़िम्मेदार बनाना, सरकारी कार्यालयों में भ्रष्टाचार और छोटे-छोटे कामों में लेटलतीफी को दूर करना शामिल है. जनता का भरोसा बरकरार रखने के लिए नीतीश कुमार इस काम को ज़मीन पर उतारने के लिए जुट गए हैं.

गोयल मार्केट में तीन चार ऐसे खाद के व्यवसायी हैं जिनके गोदाम लंबे समय से नकली खाद के भंडारण एवं बिक्री के मुख्य केंद्र बने हुए हैं.

पश्चिम चंपारण की नौ सीटों में सात पर एनडीए ने क़ब्ज़ा जमाया जबकि सिकटा और लौरिया में निर्दलीय ने बाजी मारी.

एक नज़र इधर भी

जीना मरना भाजपा के साथ

दिल दिया है जान भी देंगे की तर्ज पर बिहार विधानसभा चुनाव 2010 में महनार विधानसभा क्षेत्र में भाजपा के एक सक्रिय नेता ने अपने कैरियर को ही लात मार दिया. कहते हैं कि दिल दिया है जान भी देंगे ऐ बीजेपी तेरे लिए. ज्ञात हो कि इस चुनाव में टिकट न मिलने से नाराज नेताओं ने रिकॉर्ड तोड़ तमाशा किया. इसी तरह महनार में भी बीजेपी के टिकट के लिए काफ़ी जोड़– तोड़ हुए. बकौल दिलीप कुमार महनार क्षेत्र से पार्टी द्वारा पैनल में डॉ. अच्युतानन्द, दिलीप कमार व एक अन्य का नाम दिल्ली भेजा गया लेकिन टिकट अच्युतानन्द को मिला. इस बीच दिलीप सिंह को कई दलों से टिकट के लिए ऑफर आया लेकिन उन्होंने कह दिया कि पार्टी उन्हें ज़िंदा रखे या मार दे, लेकिन रहेंगे तो बीजेपी में ही.

– अंजुम परवेज

क्षमता से अधिक सवारी

महेशखूंट–सहरसा मार्ग को जोड़ने वाले पुल की हालत क्या बिगड़ी दो पहिया वाहनों पर बोझ अधिक बढ़ गया. यह हम नहीं कह रहे हैं, यह स्कूटर पर सवार लोगों का दृश्य बयां कर रहा है. खगड़िया ज़िले के बेलदौर प्रखंड अंतर्गत उसरी गांव के समीप महज़ कुछ वर्ष पूर्व ही बने बीपी मंडल पुल में बिहार विधानसभा चुनाव के ठीक पहले दरार आना शुरू हो गई. स्थिति की विकटता को देखकर ज़िला प्रशासन के द्वारा तत्काल वाहनों के आवागमन पर रोक लगाते हुए दरार निरोधी कार्य किए जाने लगे. लाखों रुपये ख़र्च करने के बाद भी पुल को बचाया नहीं जा सका. इस पार से उस पार पैदल जाने की इजाज़त मिलने के बाद लोग आने जाने लगे. चार पहिया वाहन मालिकों की चांदी कटने लगी. दो पहिया वाहन वालों ने भी कमाने की सोच ली. नतीजतन अब दो पहिए वाहन वाले भी एक साथ चार से पांच लोगों को गंतव्य तक पहुंचाने लगे हैं.

– मणिचंद परवाना

कोई नहीं है सहारा

वक़्त बुरा जब आता है तो साया भी साथ छोड़ जाता है, यह बात पूरी तरह तब सत्य साबित हुई, जब खगड़िया ज़िले के मानसी थाना अंतर्गत राजाजान गांव के 50 वर्षीय वृद्ध रामदीप यादव एक गहरे ज़ख्म का शिकार हो गए. बाद में उनके जख्म में इंफेक्शन हो गया. इस स्थिति के बाद घर वालों ने उनका साथ छोड़ दिया. कुछ दिनों तक अपने गांव में ही इधर–उधर भटककर किसी तरह ज़िंदगी गुज़ारने लगे. गांव वालों ने जब रामदीप के घरवालों को कोसना शुरू किया तो घर वालों ने उन्हें खगड़िया सदर अस्पताल में भगवान भरोसे भर्ती करा दिया. चिकित्सकों ने उनकी गंभीर स्थिति को देखते हुए इन्हें पीएमसीएच रेफर कर दिया लेकिन घर वाले भाग खड़े हुए. अस्पताल के फर्श पर इस वृद्ध को लावारिस हालत में देखकर भले ही लोगों को रोना आ जाता हो, लेकिन अब तो डॉक्टर भी इलाज करने से परहेज करने लगे हैं. लावारिस हालत में इस वृद्ध को देखकर लोगों के मुंह से यह बरबस निकल रहा है कि जब वक़्त बुरा आता है तो साया भी साथ छोड़ जाता है.

– सूर्यनारायण भारती

लाखों का किसान भवन बेकार

गया ज़िले के जीटी रोड पर स्थित डोभी प्रखंड मुख्यालय के सामने स्थित लाखों रुपये के ख़र्च से एक साल पहले बना किसान भवन बेकार हो गया है. इस भवन का निर्माण किसानों के हित मे चलाए जा रहे कार्यक्रमों के लिए किया गया है, लेकिन इस भवन का उपयोग प्रखंड व अंचल कार्यालय के लोग अन्य कार्यों के लिए करते हैं. घटिया निर्माण के चलते इस भवन के करीब दो दर्जन स्थानों पर दरारें आ गईं हैं. इन दरारों को छिपाने के लिए पुन: प्लास्टर तथा रंग रोगन कर दिया गया है. इसका उपयोग किसानो के लिए न किये जाने से स्थानीय लोगो मे रोष भी है.

–राजेश कुमार केसरी

खेती के गुर

मक्का सहित अन्य फसलों की उपज के मामले में अन्य इलाकों को पीछे छोड़ देने वाले खगड़िया के किसानों को खेती के बेहतर तरीके अपनाने का गुर टीडीएच जर्मनी के सहयोग से किसान विकास ट्रस्ट के द्वारा दिया जा रहा है. स्थानीय प्राथमिक विद्यालय चकला मुसहरी अमनी सहित अन्य जगहों पर चलाए जा रहे इस प्रशिक्षण कार्यक्रम में किसानों की अच्छी खासी भीड़ देखकर यह अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि किसानों में फसलों की अच्छी पैदावार करने की कितनी भूख है. बतौर प्रशिक्षक कृषि वैज्ञानिक निरंजन हजारी, कृशि विशेषज्ञ ब्रज भूषण झा, उन्नाव (यूपी) के पुतुल सहित अन्य के द्वारा छोटे एवं पर्चाधारी किसानों को वैकल्पिक एवं श्रीविधि खेती का प्रशिक्षण दिया जा रहा है. किसान विकास ट्रस्ट के कृष्ण मोहन सिंह, अंबिका जी, अजय कुमार, गीता देवी आदि की उपस्थिति में किसानों का कहना था कि सरकारी हुक्मरानों के द्वारा भले ही इस तरह का प्रशिक्षण नहीं दिया जाता हो, लेकिन किसान विकास ट्रस्ट ने किसानों के लिए एक ऐसा प्लेटफॉर्म तैयार कर दिया है कि किसान अब निराशर नहीं बैठेंगे.

– घनश्याम

लाल बाबू को महंगा पड़ा

मढ़ौरा से पिछला चुनाव निर्दलीय के रूप में जीतकर विधान सभा पहुंचने वाले पूर्व विधायक लालबाबू राय को जदयू में जाना महंगा पड़ा. उन्हा चुनाव के कुछ ही महीने पूर्व जदयू की सदस्यता ग्रहण की थी. जदयू ने उन्हें मढ़ौरा से अपना प्रत्याशी बनाया था मगर उन्हें राजद के युवा उम्मीदवार जीतेंद्र राय से मात खानी पड़ी.

– अरुण सिंह

चौथी दुनिया ब्यूरो
feedback@chauthiduniya.com

दिल व ख़ज़ाना दोनों खोले केंद्र : भीम सिंह

ग्रामीण कार्य विभाग का कार्यभार संभालने के साथ ही लगता है डॉ. भीम सिंह में छात्र राजनीति के वक़्त का जोश भर आया है. बिना आराम के काम का मंत्र ख़ुद पढ़ रहे हैं और अपने विभाग के अधिकारियों को भी पढ़ा रहे हैं. पूछने पर कहते हैं कि जनता ने इतना भारी जनादेश देकर हमलोगों को चुनौतियों से लाद दिया है. इसलिए दिन रात काम करना बेहद ज़रूरी है. चुनाव के कारण सड़कों का निर्माण प्रभावित हुआ, इसके अलावा केंद्र सरकार की उपेक्षा ने भी कार्यगति पर ब्रेक लगाएं हैं. यही वजह है कि मेरे विभाग का टास्क बेहद चुनौतीपूर्ण हो गया है. अपनी कार्ययोजना पर इन्होंने ढेर सारी बातें कहीं, प्रस्तुत है कुछ ख़ास अंश.

➪ ग्रामीण कार्य विभाग जनसरोकार से जुड़ा विभाग है. जनता की अपेक्षाओं को आप किस तरह पूरा करेंगे?

नीतीश सरकार ने तमाम बाधाओं के बावजूद अपने पिछले कार्यकाल में भी प्रदेश में सड़कों का जाल बिछाने का काम किया. केंद्र सरकार की अड़चनों के कारण बहुत सारे काम अधूरे रह गए. लेकिन मेरा प्रयास रहेगा कि हर हाल में गांवों में अच्छी सड़कें समय पर बनें. मैंने फ़ैसला लिया है कि कामों को समय सीमा के भीतर निपटाया जाएगा. नीतीश कुमार ने पांच सौ आबादी के गांवों के लिए मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना लागू की है. इस योजना को गति देने के लिए दिन–रात काम किया जाएगा.

➪ केंद्र सरकार की तरफ़ से आ रही बाधाओं से आप कैसे निपटेंगे?

मेरा मानना है कि राजनीतिक कारणों से बिहार के लोगों का अहित नहीं होना चाहिए. चुनाव ख़त्म हो गए हैं और अब तो काम का समय है. इसलिए केंद्र सरकार को अपना दिल व ख़जाना दोनों बिहार के लिए खोलना चाहिए. कुछ सड़कों का निर्माण इस कारण रुका पड़ा है कि केंद्र ने इसके लिए आवंटित धन जारी नहीं किया है. गांव में भी कहावत है कि कमाने वाले बेटे को बाप ज़्यादा दुलार करता है. बिहार तो कमाने वाला बेटा है, इसलिए केंद्र सरकार को चाहिए कि बिहार को उसका वाज़िब हक़ तो दे ही, इसके अलावा प्रावधान से इतर भी कुछ धन दे ताकि बिहार देश का नंबर वन राज्य बन सके.

➪ समय पर सड़कों का निर्माण हो जाए ताकि इसकी लागत नहीं बढ़े इसके लिए क्या कर रहे हैं.

समय पर सड़कों का निर्माण मेरी पहली प्राथमिकता है. मैं यह बता देना चाहता हूं कि सड़कों का निर्माण समय पर ही होगा और इसकी गुणवत्ता पर भी पूरा ध्यान दिया जाएगा. विभाग के लोगों को मैंने साफ़ कह दिया है कि गांवों तक अच्छी सड़क पहुंचाने के लिए टीम वर्क के साथ काम करना है और कोई भी दिक्कत आती है तो इसके समाधान के लिए मैं 24 घंटे उपलब्ध हूं. मैं अपने स्तर पर सड़क निर्माण की गहन समीक्षा करूंगा, ताकि कोई भी संवेदक या अधिकारी काम में कोई कोताही न बरत सके. मेरे विभाग का हर आदमी पहले ही दिन से काम में जुट गया है. इसलिए मुझे पूरी उम्मीद है कि जनता के सपनों को हम समय सीमा से पहले ही साकार कर देंगे.

➪ भ्रष्टाचार कहीं न कहीं सड़कों की सेहत को ख़राब करता है. इससे आप कैसे निपटेंगे?

आप जानते ही हैं कि नीतीश कुमार ने भ्रष्टाचार के ख़ात्मे का संकल्प ले रखा है. इसलिए यह बीमारी तो हर हाल में दूर करनी ही है. कई क़ानून भी बनाए गए हैं, कई भ्रष्टाचारी पकड़े भी गए हैं. मैं बिहार के लोगों को यह भरोसा दिला सकता हूं कि भ्रष्टाचार से जुड़े लोग बहुत जल्द हाशिये पर नज़र आएंगे. जनता का पैसा जनता के काम में लगेगा. कोई इसमें सेंधमारी की कोशिश करेगा तो उसको सज़ा मिलनी तय है.

➪ नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में सड़कों का निर्माण हमेशा से सरकार के लिए चुनौती रही है. आपकी क्या कार्ययोजना है.

आप जनादेश तो देखिए, सभी लोग विकास चाहते हैं. नक्सलियों की अपील को उन्होंने ख़ारिज़ कर दिया. सभी समझने लगे हैं कि विकास ही वह मूल मंत्र है जो जीवन को आगे ले जा सकता है. इसलिए सभी इलाकों में काम होगा और युद्धस्तर पर होगा.

➪ आपको मंत्री बनने की उम्मीद थी, ज़िम्मेदारी संभालने के बाद आप कैसा महसूस कर रहे हैं.

मैं तो पार्टी का एक साधारण कार्यकर्ता हूं. नीतीश जी ने मेरे कंधे पर इतनी बड़ी ज़िम्मेदारी दी, इसके लिए मैं उनका आभार प्रकट करता हूं. इसके साथ ही साथ उन्हें यह भरोसा दिलाना चाहता हूं कि दिन रात मेहनत करके उनके और बिहार के लोगों के सपनों को साकार करने की कोशिश करूंगा. अभी क्या खुशी होगी, जब कुछ कर लेंगे और राज्य की जनता आशीर्वाद देगी तब खुशी होगी.

➪ क्या आपको लगता था कि विपक्ष की इतनी करारी शिकस्त होगी और आप प्रचंड बहुमत से जीतेंगे?

नीतीश कुमार की विकास करने वाली छवि को विपक्ष समझ नहीं पाया. नीतीश कुमार ने जो काम किया उससे जनता में यह संदेश गया कि बिहार के विकास का सपना अब जल्द ही पूरा होने वाला है. दूसरी तरफ विपक्ष जाति–पात की राजनीति से उबर नहीं पाया. वह यह नहीं समझ पाया कि बिहार की जनता अब जाति–पात के बजाय विकास को अहम मानती है. यही कारण है कि आज विपक्षी पार्टियों का यह हाल है. न्याय के साथ विकास नीतीश सरकार का मूलमंत्र है और हम इसी पर आगे बढ़ रहे हैं.

सरोज सिंह
feedback@chauthiduniya.com

एजेंडा

एप्रोच रोड जल्द बनवाएंगे : डॉ. रंजू गीता

सीतामढ़ी के बाजपट्टी से पहली बार चुनकर आईं डॉ. रंजू गीता की खुशी का तो ठिकाना ही नहीं है. जनता का आशीर्वाद पाकर वह खुद को भाग्यशाली मानती हैं. कहती हैं कि जनता ने सेवा का मौका दिया है, मैं पीछे नहीं हटूंगी. जी जान से मेहनत करूंगी ताकि क्षेत्र का ज़्यादा से ज़्यादा विकास हो. एप्रोच रोड बनाना तथा महिलाओं के उत्थान के लिए काम करना पहली प्राथमिकता है. वह दावा करती हैं कि जल्द ही बाजपट्टी विकास के मानचित्र पर काफ़ी आगे नज़र आएगा.

अनुमंडल बनवाना पहली प्राथमिकता : अन्नू शुक्ला

लालगंज से जीतकर आईं अन्नू शुक्ला का एक परिचय यह भी है कि वह मुन्ना शुक्ला की पत्नी है. लेकिन विधानसभा पहुंचकर उन्होंने ख़ुद को स्थापित करना शुरू कर दिया है. लालगंज की जनता का आभार जताते हुए उन्होंने कहा कि अनुमंडल बनवाना उनकी पहली प्राथमिकता है. इसके अलावा पेयजल व महिला सशक्तिकरण पर उनका ख़ासा ध्यान रहेगा. अन्नू शुक्ला मानतीं हैं कि बेहतर काम के लिए जनादेश मिला है और दिन रात काम करके वह जनता की परेशानियों को दूर करेंगी. उनका दावा है कि जल्द ही आपको बदला हुआ लालगंज दिखाई देगा.

– रौशन कुमार

काम के लिए मिला है जनादेश : रत्नेश

सोनवर्षा से जदयू के टिकट पर पहली बार चुने गए रत्नेश सदा का मानना है कि जनता खुश रहेगी तभी मेरी खुशी है. शिक्षा, बिजली और बाढ़ से सुरक्षा को अपनी पहली प्राथमिकता बताते हुए कहते हैं कि जनता का जनादेश काम के लिए हैं इसलिए बैठने का समय एकदम नहीं है. दिन रात काम करके दिखाना है. रत्नेश सदा की इच्छा है कि बिहार का ऐसा विकास हो जिसे देखकर दुनिया अचंभित हो. उनकी राय में बाढ़ नियंत्रण पर विशेष ध्यान देने की ज़रूरत है ताकि कोसी की विनाशलीला से बचा जा सके.

जाम से दिलाएंगे छुटकारा : आलोक

सहरसा से पहली बार चुने गये आलोक रंजन का कहना है कि उनका दिल रोमांच से भर गया है. जनता की सेवा का जो जुनून मैंने पाल रखा था, उसके लिए जनता के आर्शीवाद से उचित मंच मिल गया है. कहते हैं कि उनके सामने कड़ी चुनौती है लेकिन पूरा भरोसा है कि सहरसा की जनता की उम्मीदों पर खरा उतरूंगा. शहर को जाम की समस्या से मुक्त कराना पहली प्राथमिकता है. बाईपास चालू कराने की बात भी आलोक रंजन कर रहे हैं. उनके मुताबिक़ वह सहरसा में ड्रेनेज सिस्टम को पूरी तरह ठीक करेंगे ताकि शहरवासियों को कोई परेशानी न हो. साथ ही सहरसा विधानसभा के लोगों के लिए उनका दरवाजा हमेशा खुला है. लोग कभी भी अपनी परेशानियों से मुझे अवगत करा सकते हैं.

चौथी दुनिया ब्यूरो
feedback@chauthiduniya.com

बंगाल से नेपाल तक

नकली खाद का कारोबार

नीरज कुमार सिंह

सरकार किसानों के हित से जुड़ीं कल्याणकारी योजनाओं को लेकर चाहे लाख दावे पेश करे, लेकिन सच्चाई यही है कि यह योजनाएं सही मायनों में धरातल पर उतरती नजर नहीं आ रही हैं. सीमांचल में किसानों को नकली मिलावटी रासायनिक खाद परोसी जा रही है. इससे अच्छी उपज की आस लगाए किसानो की उम्मीदों पर तुषारपात हो रहा है. लागत के अनुसार फसल उपज नहीं होने से किसान भूखों मर रहे हैं. सदर थाना प्रभारी सुनील कुमार सिंह के नेतृत्व में डगरुआ थाना प्रभारी अरविंद कुमार व एसआई अशोक कुमार ने सिसोबाड़ी में बंद पड़ी प्लाई मिल के गोदाम से लगभग 450 बोरी मिलावटी खाद बरामद की. इस मौके पर ही टेलर पर लोड मिलावटी खाद की लगभग 165 बोरियों के साथ ड्राईवर की भी गिरफ्तारी हुई. मौके पर पहुंचे जिला कृषि पदाधिकारी चंद्रशेखर सिंह ने खाद को पूरी तरह से अमानक बताया. हालांकि थाना प्रभारी को मिलावटी खाद के कई गोदामों की सूचना मिली थी लेकिन छापामारी की खबर मिलावट खोरों को लग गई और कई लोग सतर्क हो गये. बाद में सुनील कुमार सिंह, अरविंद कुमार व जिला कृषि पदाधिकारी ने नकली कीटनाशक तैयार करने वाली फैक्ट्री पर छापामारी कर मौके से थाइमेट, फौरेट बनाने वाली कई नामी कंपनियों के बोरे में बंद रेपर और कच्चा माल बरामद किया. कृषि पदाधिकारी ने मिलावटी खाद व नकली कीटनाशक तैयार करने वालों के विरुद्ध दो प्राथमिकी 358/2010 एवं 360/2010 सदर थाने में दर्ज की. प्रथम प्राथमिकी 358/2010 में मो. सादिक, मो. शब्बीर, भरत भगत, राजकुमार का नाम दर्ज कराया गया. ट्रैक्टर ड्राइवर का कहना था कि सादिक नाम के व्यक्ति ने खाद को गोयल मार्केट ले जाने को कहा था और गोयल मार्केट स्थित गोदाम में उतारा जाना था.

ग़ौरतलब है कि गोयल मार्केट में तीन चार ऐसे खाद के व्यवसायी हैं, जिनके गोदाम लंबे समय से नकली खाद के भंडारण एवं बिक्री के मुख्य केंद्र बने हुए हैं. यहां नकली खाद के अवैध धंधेबाज देखते ही देखते लखपति हो गए, वहीं इन खादों का इस्तेमाल करने वाले किसान खाकपति हो गए. गोयल मार्केट के ही एक व्यवसायी का माल पिछले पांच सालों से कहीं ना कहीं पकड़ा जाता है और लेबोरेट्री टेस्ट में भी अमानक का रिजल्ट आता है, लेकिन कृषि विभाग के अधिकारी इतने मेहरबान हैं कि उनका कुछ भी नहीं बिगड़ता. नहीं तो अभी तक उस व्यवसायी का लाइसेंस रद्द हो जाता जिसकी खाद पूर्णिया के सदर थाने में ज़ब्त पड़ी है. अगर किसी का लाइसेंस रद्द भी हो गया तो वह किसी दूसरे के नाम से लाइसेंस निर्गत करा लेते हैं. गुलाबबाग पर प्रशासन की नज़र कड़ी होने के कारण विगत कुछ वर्षों से नकली और मिलावटी खाद के कारोबारी कसबा, दालकोला (बंगाल बिहार) के बॉर्डर का रुख़ कर रहे हैं. इधर किशनगंज, पूर्णिया का बायसी अनुमंडल, कटिहार का बारसोई अनुमंडल में धड़ल्ले से हो रहे इस कारोबार को देखने वाला कोई नहीं है. बंगाल से खाद मंगाकर आसानी से यहां बेची जाती है. वैसे पूरे सीमांचल में बंगाल की खाद ख़ूब बेची जाती है. हो सकता है बंगाल से ही मिलावटी खाद बिहार के बाज़ारों में उतारी जाती हो. गुलाबबाग में प्रशासनिक दबिश के चलते नकली खाद के धंधेबाजों ने कसबा को नया ठिकाना बना रखा है. यहां से मिलावटी खाद फारबिसगंज, अररिया से लेकर नेपाल तक पहुंचती हैं. पूर्णिया के कृषि विभाग अधिकारी कसबा पर इतने मेहरबान हैं कि कभी भी जांच के लिए यहां छापा नहीं मारते. अगर कभी छापा मारना भी पड़ा तो विभागीय साठगांठ से उनको पहले ही सूचना पहुंचा दी जाती है. इसीलिए आज कसबा और गुलाबबाग के कई व्यवसायी करोड़ों में खेल रहे हैं. और किसान दाने–दाने को मोहताज हैं. भला हो पूर्णिया सदर के थाना प्रभारी सुनील कुमार सिंह का, जिन्होंने किसानों के हित में इस रैकेट का पर्दाफाश किया. वैसे सिसोबाड़ी में जो मिलावटी खाद तैयार करने वाली फैक्ट्री का उद्भेदन हुआ है वहां इंडियन पोटाश लिमिटेड के एमोनियम सल्फेट फास्फोरस को नवरत्ना 12/12 (एन.पी.के.) के साथ मिलाकर डीएपी खाद तैयार की जा रही थी. सामान्यत: नवरत्न 12/12 एन. पी. के. की कीमत बाज़ार में 300 रुपये प्रति बोरे के आस पास है, वहीं डीएपी खाद की कीमत 600 रुपये प्रति बोरे के आसपास है. विभागीय सूत्र से मिली जानकारी के अनुसार प्राथमिकी दर्ज कराने को लेकर कृषि विभाग के अधिकारियों के पास कुछ लाचारी भी है, क्योंकि दूसरे ज़िले में स्थानांतरण होने के बाद दर्ज प्राथमिकी के मामले में उन्हें कोर्ट में गवाही के लिए उपस्थित होना पड़ता है. इसी परेशानी से बचने के लिए वे प्राथमिकी दर्ज कराने से बचते हैं. अगर इस संबंध में सरकार क़ानून में कुछ संशोधन करे तो इस दिशा में सकारात्मक नतीजे मिल सकते हैं.

कृषि पदाधिकारी ने मिलावटी खाद व नकली कीटनाशक तैयार करने वालों के विरुद्ध दो प्राथमिकी 358/2010 एवं 360/2010 सदर थाने में दर्ज की है.

feedback@chauthiduniya.com

भ्रष्टाचार और लूट की होड़

देवघर

झारखंड में विकास के नाम पर जो लूट, भ्रष्टाचार और घोटालों का कीर्तिमान बना, उसमें देवघर ज़िले की भी ज़बरदस्त भागीदारी रही. शायद ही कोई विभाग बचा हो जहां यह बीमारी न पहुंची हो. आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने के मामले में जेल में बंद ज़िले के निवासी पूर्व मंत्री हरि नारायण राय एवं आरइओ विभाग में पदस्थापित इंजीनियर पारस सिंह ने अपने सहयोगियों के साथ मिलकर जिस तरह से सरकारी ख़ज़ाना लूटकर अकूत संपत्ति का रिकॉर्ड बनाया, उसे देख शायद दूसरे ईमानदार पदाधिकारियों का भी मन डोल जाए.

केंद्र सरकार की इंदिरा आवास योजना में जिले के मोहनपुर, देवीपुर एवं करौं सहित कई प्रखंड विकास पदाधिकारी, पंचायत सेवक सहित दर्जनों सरकारी कर्मी लाभुकों से 4000 से 5000 रुपए बतौर घूस लेने के मामले में पकड़े गए हैं. कई जगहों पर लाभुकों को मिलने वाली योजना की आधी राशि ही बिचौलियों के माध्यम से गटक गए. नतीजतन सिर्फ दीवारें हैं छत नहीं.

ऐसा ही एक मामला ज़िले के मोहनपुर प्रखंड के रांगामोदीचक गांव में तब पकड़ा गया, जब पैसे के अभाव में नरेगा मज़दूर की मौत हो गई. जब जांच की गई ता पता चला कि बैंक प्रबंधक एवं डाकपाल ने भी ग़रीब मज़दूरों के पैसे का गबन किया. कई प्रखंड विकास पदाधिकारियों ने अपने सहयोगियों के साथ मिलकर फ़र्ज़ी मास्टर रोल एवं जॉब कार्ड बनाकर बैंक प्रबंधक व डाकपाल के मिलीभगत से लाभुकों के नाम बैंको व डाकघरों में खाते खोले और पैसे लूटे.

इन मामलों में मोहनपुर एवं अन्य प्रखंडों में पदस्थापित डाकपाल व बैंक प्रबंधक पकड़े गए. प्रखंडों में बीडीओ व सरकारीकर्मियों का प्राइवेट ऐजेंट बिचौलिया है, जिसके माध्यम से बिना गांव का भ्रमण किए ही सारी फर्जी सूची, लेन देन सब आराम से टेबल पर पहुंच जाता है. गत दिनों ज़िले के उपायुक्त मस्तराम मीणा ने दर्जनों शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों के आंगनबाड़ी केंद्रों का औचक निरीक्षण किया, जिसमें भारी अनियमितताएं पाई गईं. सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों में स्कूलों की दयनीय स्थिति भी किसी से छिपी नहीं है. ज़िले के मोहनपुर, सारठ, पालाजोरी, देवीपुर, करौं सहित कई प्रखंडों के स्कूलों में विद्यार्थियों की नामांकन पंजी में फ़र्ज़ी नाम भरने का मामला सामने आ चुका है. मध्याह्न भोजन सामग्री की पूरी राशि फ़र्ज़ी नामांकन के अनुसार संबंधित शिक्षक लेते रहे हैं. हाल ही में मोहनपुर प्रखंड के तपोवन मध्य विद्यालय में बच्चों को परोसे गए मध्याह्न भोजन में मरी हुई छिपकली पाई गई. इसको खाने से कई बच्चे बीमार पड़ गए. मामले की जांच की गई और चेतावनी देकर छोड़ दिया गया. सबसे आश्चर्य वाली बात यह रही कि तत्कालीन सिविल सर्जन डॉ. पी एन झा ने जांच के बाद पत्रकारों से कहा कि इस क्षेत्र में पाई जाने वाले छिपकली ज़हरीली नहीं होती है, इसलिए यह मामला गंभीर नहीं है.

मस्तराम मीणा

पिछले महिने ही कृषि विज्ञान केंद्र के समन्वयक पी के सान्निग्रही एवं उनके तकनीकी सहायक ललन सिंह को हाइटेक नर्सरी, वृक्षारोपण एवं तालाबों की सतह में बिछाने हेतु पॉलिथिन ख़रीद में 11 लाख रुपये से अधिक के घोटाले में बरखास्त किया गया. जाँच में 5 प्रतिशत ही काम धरातल पर पाए गए जबकि पूरी राशि डकार ली गई. सवाल यह है कि मुख्यालय से लेकर प्रखंड तक चल रहे भारी घोटालों, भ्रष्टाचार एवं अनियमितताओं की ज़िम्मेवारी किसकी है? क्या ज़िम्मेवार ज़िले के पदाधिकारियों को सज़ा मिलेगी या कनीय पदाधिकारी व कर्मी ही सज़ा काटेंगे? बच्चों के मध्याह्न भोजन, ग़रीबों के बिना छत आवास के साथ जनता के लिए सरकार की अन्य सुविधाएं आज के हालातों में क्या कभी मिलेंगी, शायद इसका जवाब किसी के भी पास नहीं है.

रणजीत झा
feedback@chauthiduniya.com

ये रहे आपके विधायक

स्थिति बदली तो बदले विधायक

वर्ष 2005 में सात स्थानों पर दूसरे पायदान पर रहने वाला राजग गठबंधन ने 2010 के विधानसभा चुनाव में राजद–लोजपा से अपना हिसाब चुकता कर लिया और इसे आठों सीटों पर दूसरे स्थान पर फेंक दिया. दरभंगा ज़िले के दस विधानसभा क्षेत्रों में नीतीश कुमार के विकास की लहर रही और दस में से आठ सीट पर भाजपा–जदयू गठबंधन ने जीत हासिल कर सबको चौंका दिया. राजद का गढ़ माने जाने वाले दरभंगा ज़िले में जहां राजद को 2 सीट मिलीं, वहीं लोजपा और कांग्रेस का पत्ता साफ़ हो गया. कांग्रेस के दस में से नौ प्रत्याशियों की ज़मानत ज़ब्त हो गई. 2005 के चुनाव में ज़िले की नौ विधानसभा सीटों में राजद को 6, भाजपा को 2 एवं लोजपा को 1 सीट मिली थी. वहीं समस्तीपुर ज़िले के सिंधिया विधानसभा सीट के अधिकांश मतदाता दरभंगा ज़िले के थे, इसलिए वोट की गिनती दरभंगा में हुई थी, जहां से कांग्रेस के डॉ. अशोक राम ने जीत दर्ज की थी. इस बार नौ सीट से बढ़कर दस सीट हुए दरभंगा ज़िले में राजद का माय समीकरण पर राजग का महादलित समीकरण भारी पड़ गया और इसके आठ में से छ: प्रत्याशी चुनाव हार गए. वहीं लोजपा ने दो सीट पर प्रत्याशी खड़े किए थे, जिसमें दोनों हार गए. राजद के प्रदेश अध्यक्ष विधायक अब्दुलबारी सिद्दकी ने नये परिसीमन से बने अलीनगर एवं राजद के पूर्व राज्यमंत्री विधायक ललित कुमार यादव ने दरभंगा ग्रामीण सीट से जीतकर राजद की डूबती नैया को सहारा दिया. इन दोनों सीटों पर राजद का माय समीकरण काम कर गया.

–मीनाक्षी

सीवान में जातीय समीकरण चकनाचूर

सीवान में भी इस बार चुनाव परिणाम चौंकाने वाला रहा. ज़िले के आठों विधानसभा क्षेत्रों से एनडीए को भारी मतों से जीत हासिल की मगर राजग के विजयी विधायकों के लिए यह जीत चुनौतियों से भरी है. मतलब साफ़ है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की स्वच्छ छवि व बिहार में बहाल होती क़ानून व्यवस्था से भयमुक्त होते वातावरण में शांति की बहती बयार और विकास के बढ़ते कारवां ने राजग के प्रत्याशियों को भारी बहुमत से जीत दर्ज कराई है, शांति और विकास की लहर ने ही प्राय: जातीय समीकरणों को चकनाचूर कर ज़िले के कुल आठों विधानसभा क्षेत्रों में भाजपा के व्यासदेव प्रसाद, भूपेंद्र नारायण सिंह उर्फ़ चुन्नू बाबू, विक्रम कुंवर, रामायण मांझी, आशा पाठक और जदयू के श्याम बहादुर सिंह , दामोदर सिंह, व जगमातो देवी को भारी मतों से विजयी श्री की माला पहनाई है.

–धनंजय मिश्र

दो मुस्लिम महिलाओं ने भी चखा जीत का स्वाद

बिहार विधान सभा के इतिहास में पहली बार एक साथ दो मुस्लिम महिलाओं को सदन में आवाज़ बुलंद करने का अवसर मिला है. जदयू के टिकट पर साहेबपुर कमाल विधान सभा क्षेत्र से राज्य मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग के प्रधान सचिव अफज़ल अमानुल्लाह की धर्म पत्नी प्रवीण अमानुल्लाह और कल्याणपुर निर्वाचन क्षेत्र से इसी दल की रजिया खातून निर्वाचित हुईं हैं.

– अशरफ अस्थानवी

नीतीश ने पार लगा दी एनडीए की नैया

भारत–नेपाल सीमा से सटे चंपारण परिक्षेत्र में पूरे बिहार की तरह नीतीश की ऐसी आंधी बही कि राजद और लोजपा गठबंधन का सूपड़ा साफ़ हो गया. नीतीश के तीर ने न केवल लालटेन के शीशे को चकनाचूर कर दिया बल्कि झोपड़ी को भी उड़ा दिया. मतदाताओं ने सुशासन पर जमकर मुहर लगाई और राजद, लोजपा, वामदल समेत किसी दूसरे राजनीतिक दल का यहां खाता भी नहीं खुलने दिया. अलबत्ता चंपारण की इक्कीस सीटों में से तीन पर निर्दलीय ने क़ब्ज़ा जमाया लेकिन वे सभी एनडीए मानसिकता के ही हैं. पश्चिम चंपारण की नौ सीटों में सात पर एनडीए ने क़ब्ज़ा जमाया जबकि सिकटा और लौरिया में निर्दलीय ने बाजी मारी. पूर्वी चंपारण ज़िले के बारह विधान सभा क्षेत्रों में से ग्यारह पर एनडीए और एक ढाका पर निर्दलीय ने क़ब्ज़ा जमाया. तीनों निर्दलीय मूल रूप से नीतीश कुमार के आधार मतों से ही विजयी हुए हैं. हालांकि पश्चिम चंपारण में जदयू के दो तथा पूर्वी चंपारण में जदयू के एक प्रत्याशी हारे. यहां से निर्दलीय ने बाजी मारी. चंपारण के नागरिकों ने तमाम जातीय समीकरणों को धता बताते हुए शांति, विधि व्यवस्था, अपराध मुक्त समाज, विकास और बेहतरी को कुबूल किया. सभी जातीय सीमाएं यहां ध्वस्त हो गईं और लालू–रामविलास का पीआरएमवाई (पासवान, राजपूत, मुस्लिम व यादव) समीकरण तार–तार हो गया.

–रेणु

सारण में पिछला रिकॉर्ड कायम रहा

सारण के दस विधान सभा क्षेत्रों के परिणाम से एनडीए ज़िले में जहां अपनी साख बचाने में कामयाब हुई वहीं राजद ने अपनी दो सीटों के योग को बचाकर अपनी लाज रखने की कोशिश की. कांग्रेस पार्टी ज़िले में अपना खाता भी नहीं खोल सकी. लोजपा अपनी एकमात्र अमनौर सीट पर तीसरे नंबर पर सिमट कर रह गई. भाजपा के विनय कुमार सिंह को सोनपुर में पूर्व मुख्यमंत्री व राजद प्रत्याशी राबड़ी देवी के मुक़ाबले सबसे अधिक मत मिला. सर्वाधिक मतों के अंतर से जीत हासिल करने वालों में छपरा से भाजपा के जर्नादन सिंह सिग्रीवाल ने सफलता हासिल की है. विनय कुमार सिंह ने राबड़ी देवी को लगभग 20 हजार मतों से मात देकर सोनपुर सीट को भाजपा की झोली में डाल दिया.

–विजयेंद्र कुमार

Postal Regn. No. DL/ND-11/6139/2009-11, RNI No. DELHIN/2009/30467

बेटी की शादी के लिए लड़के वालों से बात करने के दौरान ही यह तय कर लिया जाता है कि किस प्रजाति के कितने विषैले सांप दहेज में दिए जाएंगे.

दहेज में ज़हरीले सांप

दहेज लेना और देना क़ानूनन अपराध होने के बाद भी इस समाज के लोग सांप लेने और देने पर क्यों आमादा रहते हैं, यह तो बहस का विषय है.

राजेश सिन्हा

समाज में आएदिन दहेज प्रताड़ना और महज चंद रुपयों के लिए बहू को मौत के घाट उतारने की घटनाएं सामने आती रहती हैं. आपको जानकर आश्चर्य होगा कि एक समाज ऐसा भी है, जो शादी के समय अपनी बेटी के हाथ में जहरीले सांप देकर उसे विदा करता है. इतना ही नहीं, अगर सांप न मिलें तो बहू को प्रताड़ित किया जाना जघन्य अपराध माना जाता है.

हम बात कर रहे हैं घुमंतू सपेरे समाज की. खगड़िया ज़िला मुख्यालय से महज़ कुछ ही दूर बसा है माड़र पंचायत का रसोंक गांव, जिसमें लगभग सौ परिवारों का एक टोला है, जिसे लोग सपेरों की बस्ती के नाम से जानते हैं. सुबह से लेकर शाम तक यहां के बच्चे और बूढ़े ज़हरीले सांपों से खेलते और उनकी देखभाल करते देखे जा सकते हैं. वहीं घर के मुखिया सांप के करतब दिखाकर पेट की भूख मिटाने के लिए शहर की ओर रुख़ कर चुके होते हैं. गांव के नईम नट बताते हैं कि विषहीन सांप देखकर ही लोगों की घिघ्घी बंद हो जाती है, जबकि ज़हरीले से जहरीले सांपों को जान ज़ोख़िम में डालकर पकड़ना हमारी मजबूरी है. अगर हम सांप को पकड़ कर करतब दिखाना छोड़ दें तो शायद घर के चूल्हे ही न जलें, बेटी की शादी भी होने से रही. नईम के मुताबिक़, बेटी की शादी के लिए लड़के वालों से बात करने के दौरान ही यह तय कर लिया जाता है कि किस प्रजाति के कितने विषैले सांप दहेज में दिए जाएंगे. यह भी देखा जाता है कि लड़के के परिवारीजन सांप रखने और पालने के मामले में कितने रसूख वाले हैं. अगर वायदे के अनुसार सांप बतौर दहेज नहीं दिए गए तो शादी टूटने का ख़तरा भी बना रहता है.

इस आधुनिक समाज के लोग दहेज में जहां घोड़ा, गाड़ी, कार, रुपये और न जाने क्या–क्या पाने की चाहत रखते हैं, मुंहमांगा सामान न मिलने पर बहू को प्रताड़ित भी करते हैं, वहीं इस समाज के लोग बेटी को शादी के समय ज़हरीले से ज़हरीले सांप देकर विदा करते हैं. जिस लड़के को जितने अधिक जहरीले सांप दहेज में मिलते हैं, उसके परिवार की प्रतिष्ठा में उतनी ही बढ़ोत्तरी हो जाती है. सांप न मिलने के कारण बहू को प्रताड़ित किया जाना भी इस समाज में जघन्य अपराध माना जाता है. निशार नट का कहना है कि दहेज में सांप देने या लेने की प्रथा यह सोचकर शुरू की गई थी कि किसी भी घर में बेकारी न रहे, क्योंकि इतना तय है कि जो भी सांप पकड़ने और उसका करतब दिखाने की कला में माहिर रहेगा, वह किसी भी कीमत पर भूखा नहीं रहेगा. असलम नट की मानें तो यह धंधा इन लोगों के लिए पुश्तैनी है.

वर्षों पहले उनके पूर्वज दो वक़्त की रोटी के लिए तरसते थे. एक दिन एक सपेरा उनके घर पर आया और दो रोटी खिलाने की जिद कर बैठा. रात में घर का चूल्हा जला नहीं था, इसलिए उससे कहा गया कि कमाई इतनी नहीं होती कि दोनों वक़्त भर पेट भोजन मिल सके. यह जानकर उस मेहमान ने उन्हें सांप पकड़ने और उसका करतब दिखाकर पैसा कमाने का गुर सिखाया. कई माह तक यह काम सिखाने के बाद जब गांव के कई लोग निपुण हो गए, तब वह चले गए. इसके बाद गांव के लोगों को कभी भी खाने के लिए किसी पर निर्भर नहीं रहना पड़ा. अब इस कला के ज़रिए हम लोग अपने बच्चों की परवरिश भी करते हैं.

क्यूम नट के अनुसार, वे लोग इस कला में इतने निपुण हो चुके हैं कि सांप की बांबी (बिल) देखकर ही सहज अंदाज़ा लगा लेते हैं कि वहां किस सांप का बसेरा है. इसके बाद वे एक जत्थे में परंपरागत जड़ी के ज़रिए सांपों को कुछ पल के लिए वशीभूत कर पिटारे में बंद कर लेते हैं. फिर बाद में उसके जबड़े का ऑपरेशन करके विष की थैली से ज़हर निकाल देते हैं. हालांकि इस बात के लिए सजग रहना पड़ता है कि पंद्रह दिनों के अंदर ही पुन: उसके जबड़े का ऑपरेशन करना है, क्योंकि पंद्रह दिनों के बाद थैली में पुन: विष आने लगता है. अगर पंद्रह दिनों के अंदर सांप के जबड़े का दोबारा ऑपेशन न किया गया तो वह इतना हिंसक हो जाता है कि उसे संभालना मुश्किल हो जाता है. निशार नट कहते हैं कि हम लोगों के लिए सरकार द्वारा कोई विकास योजना नहीं बनाई गई है या फिर जन प्रतिनिधियों द्वारा उसे ज़मीन पर उतरने नहीं दिया जा रहा है. अगर ऐसी किसी योजना का लाभ हम लोगों को मिलता तो शायद हमारे बच्चे सांप पकड़ने और सपेरा बनने से बच जाते. सही योजनाओं और उनके कार्यान्वयन के अभाव में इनके बच्चे न तो सामान्य बच्चों की तरह उचित शिक्षा और देखभाल हासिल कर पाते हैं और न ही उस तबके से बाहर निकलने का रास्ता खोज पाते हैं.

बहरहाल, दहेज लेना और देना क़ानूनन अपराध होने के बाद भी इस समाज के लोग सांप लेने और देने पर क्यों आमादा रहते हैं, यह तो बहस का विषय है, लेकिन इस निरक्षर समाज की सोच उन सभ्य कहे जाने वाले लोगों के गाल पर करारा तमाचा जड़ती है, जो दहेज की ख़ातिर बहू को मौत की नींद सुलाने से परहेज़ नहीं करते.

feedback@chauthiduniya.com